



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]

नई विल्हेमी, शनिवार, जून 29, 1974/आषाढ़ 8, 1896

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 29, 1974/ASADHA 8, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ तंत्रज्ञानी हो जाती है जिससे कि यह इलग संकालन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(राजा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आवेदन और अधिसूचनाएं

**Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities
(other than the Administrations of Union Territories)**

संविधान सचिवालय

(कानूनी और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई विल्हेमी, 18 जून, 1974

का० फ्र० 1592.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत के राजपत्र-अनाधिराज-भाग 2-खण्ड 3-उपखण्ड (ii), दिनांक 16 अक्टूबर, 1971, में प्रकाशित, भारत सरकार, संविधान सचिवालय (कानूनी विभाग) की अधिसूचना संख्या 375/31/71-ए० 3 (फा०फ्रा० 3863), दिनांक 16 अक्टूबर, 1971 में एनदब्ल्यूएस निम्ननिवित्त और संशोधन करती है, प्रणति:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, '30 जून, 1974 तक' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर '30 सितम्बर, 1974 तक' शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० 381/21/71-ए०बी०डी० 3]

मू० सी० अग्रवाल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 18th June, 1974

S.O. 1592.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) No. 375/31/71-AVD. III (S.O. 3863), dated the 16th October 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 16th October, 1971, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, for the words, figures and letters "by the 30th June, 1974" the words, figures and letters "by the 30th September 1974" shall be substituted.

[No. 381/21/71-AVD. III]

U. C. AGARWAL, Jt. Secy.

(विधि, न्याय तथा कार्य मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई विल्सनी, 15 जून, 1974

नोटिस

का० प्रा० 1593.—इसके द्वारा, नेतृत्व प्रमाणक के नियम (नोटरीज रुल्स), 1956 के नियम 6 के प्रतिमार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना दी जाती है। उक्त प्राधिकारी को श्री प्रकाश चन्द जैन, प्लॉकेट, 82, खुरबारा, देहरादून ने उक्त नियमों के नियम 4 के अधीन देहरादून में अपने कार्यालय के साथ परिवहन उत्तराखण्ड (उ० प्र०) की जजिप में नेतृत्व प्रमाणक (नोटरीज) का काम करने की नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र भेजा है।

उक्त व्यक्ति की नेतृत्व प्रमाणक के स्पष्ट में नियुक्ति के बारे में यहि कोई आपत्तियाँ हों तो वे इस नोटिस के प्रकाशित होने के बीचदूर दिन के प्रत्यन्दर नीचे हस्ताक्षर करने वाले को निष्प कर सेज दिये जायें।

[सं० 22/78/73-जस]

के० त्यागराजन

सक्षम प्राधिकारी तथा उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

New Delhi, the 15th June, 1974

NOTICE

S.O. 1593.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Prakash Chand Jain, Advocate, 82, Khurbara, Dehra Dun for appointment as a Notary to practice in the Judgeship West Uttrakhand (U.P.) with his office at Dehra Dun.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 22/78/73-JUS.]

K. THYAGARAJAN, Competent Authority and Dy. Secy.

(विधि मंत्रालय)
राजस्व और बोमा विभाग

आवेदन

नई विल्सनी, 13 मार्च, 1974

का० प्रा० 1894.—केन्द्रीय सरकार, घनकर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्ननिबित व्यक्तियों को मूल्यांकन प्रधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अधीतः—

क्रम सं० व्यक्तियों के नाम

1 2

मर्जी

1. श्री० वेन्कटरामा श्रवर
2. श्री० एस० सेशाद्री
3. श्री० रामेन्द्रा
4. ए० शीर्षना
5. श्री० गोविन्दन
6. श्री० एन० गणदप्पा
7. एम० वेन्कटरामण

1 2

8. श्रावण प्रभू गौतम
9. श्री० मक्षेना
10. ए० एन० प्रमाद
11. मुरेश कपूर
12. के० एस० यादव।

[मं० 13/74/का०सं० 328/63/73—धनकर (कृषि भूमि)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue & Insurance)

ORDER

New Delhi, the 13th March, 1974

S.O.—1594 : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. No. Name of the Person

S/Shri

1. R. Venkatarama Iyer
2. B.S. Seshadri
3. G. Ramegowda
4. A. Veeranna
5. C. Govindan
6. B.N. Gundappa
7. S. Venkataraman
8. R.A.S. Gautam
9. P. Saxena
10. A.N. Prasad
11. Suresh Kapoor
12. K.S. Yadava.

[No. 13/74/F. No. 328/63/73/W.T.(Agricultural Lands)]

आवेदन

का० प्रा० 1595.—केन्द्रीय सरकार, धन कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन प्रधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अधीतः—

क्रम सं० व्यक्ति का नाम

1 2

मर्जी

1. के० मधुबालामुखमण्डम
2. श्री० गोपाला श्रवर
3. श्रावण थोथाची
4. श्रावण वेंकटरामा श्रवर
5. के० श्री० मुकर्जी
6. श्री० एन० शाधन
7. एम० श्री० शर्मा।

[मं० 15/74/का० सं० 328/63/73—ध०क० (जैवर)]

ORDER

S.O. 1595.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. No.	Name of the person
1.	S/Shri
2.	K. Muthubalasubramanian
3.	B. Gopala Iyer
4.	R. Thothathri
5.	R. Venkatarama Iyer
6.	K.B. Mukerji
7.	B.L. Sachan
8.	M.C. Sharma.

[No. 15/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares)]

प्रावेश

का०ग्रा० 1596.—केन्द्रीय सरकार, धन-कार, अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है, जिनके पदनाम उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में को नत्स्थानी प्रथिष्ठि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं :—

सारणी

क्रम सं०	व्यक्तियों के नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री सुरेन्द्र नारायण	सहायक मूल्यांकन अधिकारी
2.	श्री आर० एल० ग्रोवर	मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 18/74/फा० सं० 328/54/74-धन-कार]

ORDER

S.O. 1596.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officers with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri Surendra Narain	Assistant Valuation Officer
2.	Shri R.L. Grover	Valuation Officer

[No. 18/74/F. No. 328/54/74-W.T.]

प्रावेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1974

का०ग्रा० 1597.—केन्द्रीय गरकार, धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में को नत्स्थानी प्रथिष्ठि में विनिर्दिष्ट पदाधिकार सहित मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त करती है :—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदाधिकार
1	2	3
1.	श्री आर० डॉ गुप्ता	मूल्यांकन अधिकारी

[सं० 19/74/फा० सं० 328/84/74-ध० क०—]

ORDER

New Delhi, the 28th March, 1974

S.O. 1597.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 12A of the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. Name of the person No.	Designation	
1	2	3
1.	Shri R.D. Gupta	Valuation Officer

[No. 19/74/F. No. 328/84/74-W.T.]

प्रावेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1974

का०ग्रा० 1598.—केन्द्रीय सरकार, धन-कार, अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, प्रथात् :—

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम
1	2
1.	सरबेशी
2.	एम० कौ० दत्ता
3.	आर० कौ० सेन
4.	एम० सी० नागपाल
5.	एम० कौ० जैम
6.	एम० एल० प्रभ्राल
7.	बी० एम० वाही
8.	कौ० कौ० मूद
9.	जगदीश प्रसाद
10.	आर० डॉ० गुप्ता
11.	एम० एन० सोनी
	रघुबीर गिह जैन

[सं० 20/74/फा० सं० 328/63/73-ध० क० (गोप्यसः)]

ORDER

New Delhi, the 29th March, 1974

S.O. 1598.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. No.	Name of the person
S/Shri	
1. S.K. Dutta	
2. R.K. Sen	
3. M.C. Nagpal	
4. M.K. Jain	
5. S.I. Aggarwal	
6. V.S. Wahi	
7. K.K. Sud	
8. Jagdish Parshed	
9. R.D. Gupta	
10. S.N. Soni	
11. Raghbir Singh Jain	

[No. 20/74/F. No. 328/63/73-WT. Shares]

प्रादेश

का०ग्रा० 1599.—केन्द्रीय सरकार, धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को मूल्यांकन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, प्रथम :—

S. No.	व्यक्ति का नाम
1	2
1.	श्री आर० एस० बहल
2.	श्री एस० पी० सिंह
3.	श्री राम प्रसाद

[सं० 22/74/फा० सं० 328/63/73-ध० क० (कृषि भूमि)]

ORDER

S.O. 1599.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the following persons as Valuation Officers, namely :—

S. No.	Name of the person
1.	Shri R.L. Bahl
2.	Shri S.P. Singh
3.	Shri Ram Prasad

[No. 22/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Agricultural Lands)]

प्रादेश

नई दिल्ली, 15 मई, 1974

धन-कर

का०ग्रा० 1600.—केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तर्जांबन्धी प्रतिलिपि में विनिर्दिष्ट प्रभिधानों सहित मूल्यांकन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी	पदाधिकारी	
क्रम सं०	व्यक्तियों के नाम	पदाधिकारी
1	2	3
	मंदसीरी	
1.	एस० के० लहरी	मूल्यांकन अधिकारी
2.	एस० एन० रमा०	यथोक्त
3.	के० रामाचन्द्रन	यथोक्त

[सं० 37/74/फा० सं० 328/107/74-ध० क०]

धी० डी वाहरकार, प्रवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 15th May, 1974

WEALTH-TAX

S.O. 1600.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the persons specified in column (2) of the Table below as Valuation Officers with the designations specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Name of the persons	Designation
1	2	3
S/Shri		
1.	Shri S.K. Lahri	Valuation Officer
2.	M.N. Sharma	Valuation Officer
3.	K. Ramachandran	Valuation Officer

[No. 37/74/F. No. 328/107/74-W. T.]
V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

प्रादेश (राष्ट्रकरण)

नई दिल्ली, नारीब 8 अप्रैल, 1974

का०ग्रा० 1601.—श्री के०वी० नरसिंह को, जिन्हे का० सं० 328/63/73-ध० क०, नारीब 6 मितम्बर, 1973 में प्रादेश सं० 43 द्वारा, धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 12क के अधीन, ऐयरों के लिए मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, नियुक्त रद्द की जाती है।

[सं० 27/74/फा० सं० 328/63/73-ध० क०]

ORDER CANCELLATION

New Delhi, the 8th April, 1974

S.O. 1601.—The appointment of Shri K. B. Narasimhan who was appointed as Valuation Officer for Shares u/s. 12A of the Wealth Tax Act, 1957 by Order No. 43 in F. No. 328/63/73-W.T dated the 6th September, 1973 is hereby cancelled.

[No. 27/74/F. No. 328/63/73-WT]

प्रादेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1974

का०ग्रा० 1602.—केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 12क की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रभिधानों सहित मूल्यांकन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है :—

की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिविष्ट पदाभिधान महिला, मूल्यांकन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैः—

नई दिल्ली, 22 मई 1974

आयकर

सूची		
क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	पदाभिधान
1.	श्री बी० एम० घोष	मूल्यांकन अधिकारी
[मं० 29/74/का० सं० 328/96/74-ध० क०]		
एम० बापू, अश्रु सचिव		

ORDER

New Delhi, the 17th April, 1974

S.O. 1602.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 12A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby appoints the person specified in column (2) of the Table below as Valuation Officer with the designation specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No.	Name of the person	Designation
1	2	3
1.	Shri B. M. Ghosh	Valuation Officer
[No. 29/74/F. No. 328/96/74 W.T.]		
S. BAPU, Under Secy.		

नई दिल्ली 10 मई, 1974

आयकर

का० आ० 1603.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, विहित प्राधिकारी, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के अंडे (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया हैः—

संस्था

वकील इस्टिट्यूट आफ कार्डिओलोजी एंड रिसर्च मेन्टर, मुम्बई। यह अधिसूचना 1-4-1973 से प्रभावी है।

[सं० 611 (का० सं० 203/28/74-आई टा० (प.2)]

New Delhi, the 10th May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1603.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Medical Research, the prescribed authority for the purpose of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 :—

INSTITUTION

VAKIL INSTITUTE OF CARDIOLOGY AND RESEARCH CENTRE, BOMBAY

This notification will take effect from 1-4-1973.

[No. 611 (F. No. 203/28/74-IT(AII)]

का० आ० 1604.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आयकर 1961 (1961 का 43) की धारा 35 वीं उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए निम्न उल्लिखित संस्था अनुमोदित की गई है।

संस्था

मेल्युनीसिस्क कन्सलटेन्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

[सं० 619 (का० सं० 202/48/71-आई टा० II)]

New Delhi, the 22nd May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1604.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub-section (2) of Section 35D of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).

INSTITUTION

Cellulosics Consultants (India) Private Ltd., New Delhi.

[No. 619 (F. No. 202/48/71-ITA. II)]

नई दिल्ली, 24 मई, 1974

आयकर

का० आ० 1605.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न-वर्णित मंस्था को विहित प्राधिकारी, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने आयकर अधिनियम, 1959 की धारा 35 की उपधारा (1) के अंडे (iii) के प्रयोजनों के लिए, प्रथमतया तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया है। न्यासी, मंस्था द्वारा इस छूट के अधीन प्राप्त दानों और जिस रीति से उनका उपयोग किया जाय उसकी वापत एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को भेजेगे।

संस्था

बलराज-दम्यनी साहनी ऐसोसिएशन ट्रस्ट, अल्मोड़ा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1973 से प्रभावी है।

[सं० 627 (का० सं० 203/20/74-आई टा० II)]

New Delhi, the 24th May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1605.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a period of three years in the first instance. The trustees will send to Indian Council of Social Science Research annually a report on the donation received by the Institution under this exemption and the manner in which they are utilised.

INSTITUTION

Balraj-Damyanti Sahni Memorial Trust, Almora.

The notification takes effect from 1-4-1973.

[No. 627 (F. No. 203/20/74-ITA. II)]

नई दिल्ली, 28 मई, 1974

प्राप्ति-कर

का० प्रा० 1606.—सर्वसाधारण की ज्ञानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित संस्था को इंजन वाल्व्हें के निर्माण सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, विद्वित प्राक्षिकारी, द्वारा आधिक अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है।

संस्था

इंजन वाल्व्हें लिमिटेड, मद्रास

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1973 में प्रभावी होती।

[स० 632(फा० म० 202/55/73-प्रा० ८० II)]

टी० पी० झुनझुनवाला, उा मत्रित्र

New Delhi, the 28th May, 1974

INCOME-TAX

S.O. 1606.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Central Board of Direct Taxes for the purposes of sub-section (2) of Section 35D of Income-tax Act, 1961 for purpose of imparting of technical know-how in respect of manufacture of engine valves:—

INSTITUTION

ENGINE VALVES LIMITED, MADRAS.

The notification takes effect from 1-4-1973.

[No. 632 (F. No. 202/55/73-ITA.II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1974

बीमा

का० प्रा० 1607.—यह केंद्रीय सरकार की राय है कि विविध बीमा कारबार अधिक वक्ष्या से चलाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार विविध बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमाकर्ताओं के अधीन पर्यवेक्षी, निपिकीय और अधीनस्थ पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के बेतनमानों और सेवा के अन्य निबंधनों तथा एनों के मुद्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण के लिए, उपबन्ध करने लेनु निम्नलिखित स्कीम द्वारा है, अर्थात्:—

1. **संस्थित नाम और प्रारम्भ:**—(1) इस स्कीम का नाम विविध बीमा (पर्यवेक्षी), निपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारी बृन्द के बेतनमानों और सेवा की अन्य भार्तीय और पुनरीक्षण स्कीम, 1974 है।

(2) यह गणपत्र में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होती।

2. **सामूहिका:**—इसमें अल्पिण्ट उपबन्ध, (अधिकारियों और विकास कर्मचारियों से भिन्न) भारत में पर्यवेक्षी, निपिकीय और अधीनस्थ पदों पर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों को सामूहिका हैं—

(i) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी में 31 दिसम्बर, 1972 को पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में पुष्ट हो गए थे और जो धारा 7 की उपधारा (1) के अनुमान किसी भारतीय बीमा कम्पनी के कर्मचारी हो गए थे;

(ii) जो किसी भारतीय बीमा कम्पनी से भिन्न किसी विद्वान बीमाकर्ता के 31 दिसम्बर, 1972 को पूर्णकालिक कर्मचारियों के रूप में पुष्ट हो गए थे और जो धारा 7 की उपधारा (1) के अनुमान किसी भारतीय बीमा कम्पनी के कर्मचारी हो गए थे;

(iii) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी कम्पनी या किसी भारतीय बीमा कम्पनी से भिन्न किसी विद्वान बीमाकर्ता के अधीन प्रस्थापित पूर्णकालिक फर्मेचरों के जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व पुष्ट हो गए थे;

(iv) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पश्चात निगम या उसके किसी समनुयानी द्वारा भर्ती किए गए थे, किन्तु ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होते:—

(क) जो नियोजन की विनियिष्ट भवित्वांत्रिका के अधीन नियोजित किए गए हैं;

(ख) जो अग्रामालिक नियोजन के अधीन है; और

(ग) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व पदवाया कर चुके हैं या जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं;

परन्तु खण्ड (iii) में निर्देशित व्यक्तियों की बाबत, इस स्कीम के उपबन्ध के बावजूद उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसको संबद्ध व्यक्ति अपने अपने पद पर पुष्ट हो गए थे।

3. **परिवाशार्थ:**—इस स्कीम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अंगठित न हो:—

(क) “अधिनियम” से विविध बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) अधिवेत है;

(ख) “अभिरक्षक” से, जब तक कि पद अध्यक्ष-प्रबन्ध-प्रबन्धक निदेशक के रूप में पुनः पदार्थित हो किया गया हो, धारा 16 की उपधारा (2) में निर्देशित चार भास्पनियों में से किसी का अभिरक्षक अभिवेत है, और पद के पुनः पदार्थित होने की नारीख में अभिरक्षक के प्रति इस स्कीम में किसी निर्देश से यह अप्रै लागाया जाएगा कि वह अध्यक्ष-प्रबन्ध-प्रबन्धक निदेशक के प्रति निर्देश है;

(ग) “कर्मचारी” से वह कर्मचारी अभिवेत है, जिसे इस स्कीम के उपबन्ध लागू होते हैं;

(घ) “बीमा परीक्षा” से प्रथम अनुसूची के पैरा 4 में विनियिष्ट कोई बीमा परीक्षा अभिवेत है।

(ङ) “प्रबन्ध निदेशक” से धारा 9 के अधीन बते भारतीय विधि बीमा नियम का प्रबन्ध निदेशक अभिवेत है;

(च) “नया बेतनमान” से प्रथम अनुसूची में यथा उपर्याप्त नसा बेतनमान और संबूद्ध भत्ता अन्य भत्ते अभिवेत है;

(ट) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिवेत है;

(ज) “अनुसूची” से इस स्कीम में संलग्न अनुसूची अभिवेत है;

(झ) “अधीनस्थ कर्मचारियों” से दफ्तरी, सर्वीन आरंडर, जमादार, प्रधान चपरासी, चपरासी, लिपटमैन, माली, नलाज, प्रहरी, और शाहुकश के पद पर कार्य करने वाला कोई कर्मचारी अभिवेत है।

4. **कर्मचारियों के बेतन और भत्ते**—(1) प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्यालय के प्रधान की मार्फत अभिरक्षक को संबोधित लिखित सूचना द्वारा इस स्कीम के प्रारम्भ होने की तारीख से तब्दि विन के भीतर या

तो नए वेतनमान द्वारा या इस स्फीट के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उसे लागू बेतनमान और भनों द्वारा शामिल होने के लिए चुनने का विकल्प देंगा और एक बार प्रयोग किया विकल्प अनिम होगा।

स्पष्टीकरण 1:—इस पैग और पैग 5 और 6 के प्रयोजनों के लिए, "कर्मचारी" से पैग 2 के खण्ड (i) या खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्देशित कोई कर्मचारी अभियन्त है।

स्पष्टीकरण 2:—इस पैग के प्रयोजनों के लिए, "नया वेतनमान" से बेतन, महंगाई भना और अन्य भना अभियन्त है, किन्तु इसमें किट भना और वर्दी तथा भुगाई भना सम्मिलित नहीं है।

(2) (क) यदि कोई कर्मचारी नए वेतनमान द्वारा शामिल होने के लिए चुनाव करता है तो उसे उस तारीख से जिसको वह उप-पैरा (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग करता है, नए वेतनमान के अनुमान बेतन, महंगाई भना और अन्य भना अभियन्त है, किन्तु इसमें किट भना और वर्दी तथा भुगाई भना सम्मिलित नहीं है।

परन्तु यह कि जहाँ पूर्वोक्त अवधि के लिए ऐसा कर्मचारी, नए वेतनमान के अधीन अवधारित रकम में अधिक रकम पुराने वेतनमान के अधीन बेतन, महंगाई भना और अन्य भनों के रूप में ने छुका हो थहा, उसमें इस प्रकार नी गई अधिक रकम लौटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ए) यदि खण्ड (क) में निर्देशित अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारी द्वारा छुट्टी का कोई भाग भुगाया गया था तो, ऐसे कर्मचारी से ऐसे भुगाया जाने के रूप में उसके द्वारा बसूत की गई रकम लौटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और यदि इस स्फीट के उपबन्धों को लागू करने के परिणाम-स्वरूप ऐसा कर्मचारी ऐसी छुट्टी की बाबत संदाय के किन्हीं बिकाए का तकदार तो तो ऐसे बिकाए उसे दिए जाएंगे।

(3) (क) यदि कोई कर्मचारी, इस स्फीट के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उसे लागू बेतनमान और भनों का भुगाय करता है तो, कर्मचारी ऐसे प्रारम्भ से, उस वेतनमान के अनुमान सामिक बेतन और भने प्राप्त करना चाहेगा।

(ख) यदि सुमंगल अवधि के दौरान ऐसा कर्मचारी उस पद में विभाजित, जिस पर वह प्रभामान्यत, नियोजित था, पद धारण कर रहा था या अस्थायी प्रकृति का कोई भना पा रहा था तो, केवल उस बेतन और भनों को, जो उसने प्रभामान्य पद पर निया होगा, हिसाब में निया जाएगा।

(ग) नए वेतनमान से भिन्न सभी बातों की बाबत ऐसे कर्मचारी, ऐसी बातों की बाबत इसमें अन्तिमित उपबन्धों द्वारा शामिल होगा:

परन्तु यदि ऐसे कर्मचारी की उच्चतर श्रेणी में संविधित उस श्रेणी में वेतनमान और भने वे होंगे जो ऐसी उच्चतर श्रेणी के लिए इसमें विनियिष्ट हैं।

5 कर्मचारियों का वर्गीकरण:—(1) कर्मचारियों का वर्गीकरण 1 जनवरी, 1973 से उसके अधिष्ठायी पदों और काम की प्रकृति के अधार पर उपयुक्त प्रबन्धों में किया जाएगा, जो उप-पैग (2) से (1) में विनियिष्ट है।

(2) (क) अधीक्षक.—उप-पैग (1) के अधीन रहते हुए, निम्न-लिखित अधीक्षकों के रूप में समझे जाने के पाव्र होंगे, अर्थात्:—

(i) वे गभी अविन, जो अधीक्षकों, प्रभुपाद ग्रमुर्द्वा, महाराज अधीक्षकों, कर्मचारियुन्द महायकों, प्रधान विपक्षों और पर्यंतेशी हैमियन में काम करने वाले पर्यंतेशीकों के स्वयं में वापापित हैं;

(ii) वे गभी अविन जो यूनाइटेड एडिया फायर और जनरल इंश्योरेंस कम्पनी निमिटेच, यूनिट "यूनियन कोओपरेटिव" में कनिष्ठ अधिकारियों के स्वयं में पदाधित हैं;

(iii) वे सभी कर्मचारी, जिनके विनियिष्ट बेतनमान या अहंताएँ हैं और जिन्हे उपचण्ड (i) या उपचण्ड (ii) में उल्लिखित पदों में से किसी समनुल्य पद पर विशेषज्ञता भर्ती किया गया है।

(घ) उच्चेष्ठ सहायक:

(i) उप-पैरा (4) के अधीन रहते हुए, जहाँ खण्ड (क) के अधीन वर्गीकृत अधीक्षकों की श्रेणी से भिन्न दो निपिकीय श्रेणियां हैं, वहाँ वे, जो दोनों श्रेणियों में से उच्चवर श्रेणी में हों, उसके द्वारा किये गए कर्तव्य के आधार पर उच्चेष्ठ सहायकों के स्वयं में वर्गीकृत किए जाने के पाव्र होंगे। जहाँ ऐसी वे श्रेणियों से अधिक श्रेणियां हों वहाँ, वे, जो ऐसी श्रेणियों में से उच्चतम श्रेणी में हों, उच्चेष्ठ सहायकों के स्वयं में वर्गीकृत किए जाने के पाव्र होंगे।

(ii) उप-पैरा (4) के अधीन रहते हुए, जहाँ केवल एक निपिकीय श्रेणी हो वहाँ, वे जो 1 जनवरी, 1973 की निम्नतिविधि गतीयों में से किसी को पूरा करते हैं, उच्चेष्ठ सहायकों के स्वयं में वर्गीकृत किए जाने के पाव्र होंगे, अर्थात्:—

(क) जिन्होंने निपिकों या सहायकों के रूप में 10 वर्ष की सेवा की हो; या

(ख) जिन्होंने निपिकों या सहायकों के स्वयं में 8 वर्ष की सेवा की हो और दीमा संस्थान परिसंघ की अनुशन्ति परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(ग) जिन्होंने निपिकों या सहायकों के रूप में 7 वर्ष की सेवा की हो और दीमा संस्थान परिसंघ या चार्टर्ड दीमा संस्थान की एसोशिएटिशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो; या

(घ) जिन्होंने निपिकों या सहायकों के रूप में 5 वर्ष की सेवा की हो और दीमा संस्थान परिसंघ या चार्टर्ड दीमा संस्थान की फेलोशिप परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(3) (क) आणुलिपिक : वे सभी अविन जो आणुलिपिकों के स्वयं में या समनुल्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और वे सभी अविन जो आणुलिंकों या आणुलिपि टंकों के स्वयं में या समनुल्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और जो सरकार द्वारा गठित किसी परीक्षण निकाय द्वारा जारी किया गया श्रुतलेख में प्रति मिनट कम से कम 100 शब्दों और टंकण में प्रति मिनट कम से कम 40 शब्दों का प्रमाणपत्र धारण करने होंगे या जो होने वाला परीक्षण श्रुतलेख में प्रति मिनट कम से कम 100 शब्दों और टंकण में प्रति मिनट कम से कम 40 शब्दों की गति के साथ उत्तीर्ण करने होंगे आणुलिपिकों के स्वयं में वर्गीकृत किए जाने के पाव्र होंगे।

(ख) सहायक : निम्नलिखित प्रबन्धों में से किसी एक में या अधिक में आने वाले सभी कर्मचारी सहायकों के स्वयं में वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात्:—

- (i) ऐसे सभी कर्मचारी जो नियमित आधार पर नैतिक लिपि-कार्य कार्य कर रहे हों;
- (ii) ऐसे सभी कर्मचारी जो लिपिकों कनिष्ठ लिपिकों, महायकों, ट्रेनीफोन आपरेटरों, ट्रेनेशन आपरेटरों, एच बार्ड आपरेटरों, यूनिट रेकर्ड मशीन आपरेटरों और परिकलन-यंत्र प्रकार्यकों के रूप में पदाधिक्षित हैं;
- (iii) ऐसे सभी कर्मचारी जो कनिष्ठ लिपिकीय श्रेणी या समतुल्य टंकक श्रेणी में टंककों के रूप में कार्य कर रहे हैं;
- (iv) वे सभी, जो आशुलिपिकों, आयु-नंककों, आशुलिपि टंककों के रूप में या गमतुल्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और जिन्हें आशुलिपिकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है;
- (v) ऐसे सभी अन्य निपिकीय कर्मचारियन्द, जिन्हें ज्येष्ठ महायकों या अधीक्षकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(g) अभिनेत्र लिपिक :

ऐसे सभी कर्मचारी जो अभिनेत्र लिपिकों या फाइलिंग महायकों के रूप में पदाधिक्षित हैं और वे सभी कर्मचारी जो अधीनस्थ कर्मचारी-बृद्धि में संबंधित विनियिप्त वेतन श्रेणी में नहीं हैं और जिनके कार्य सुख्य रूप से निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक हैं अभिनेत्र लिपिकों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे, अधीनत्:—

- (i) कागजपत्रों को फाईल करना और खोजना;
- (ii) आवक डाक को खोलना, छांटना और उसका विनाश करना;
- (iii) लिफार्डों पर पता लिखना;
- (iv) बांडा और अनुलिपिकरण मशीनों का प्रचालन;
- (v) हस्त-प्रचालित पता-लेखन मशीनों का प्रचालन;
- (vi) वर्णकम-विषयक या सांख्यिक अनुक्रमणिका को बनाए रखना;
- (vii) वरिष्ठों द्वारा नट्ट करने के लिए चिह्नित पुराने अभिनेत्रों का नट्ट किया जाना।

(g) (i) चालक.—ऐसे सभी कर्मचारी जो एकमात्र रूप में यंत्र नोकरियां के चालकों के रूप में कार्य कर रहे हैं; चालकों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

(ii) सभी अन्य अधीनस्थ कर्मचारियन्द:—ऐसे सभी कर्मचारी जो विभिन्न प्रधीनस्थ पर्सों पर कार्य कर रहे हैं, अधीनस्थ कर्मचारियन्द के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

(4) गैर (2) और उप-पैरा (3) के खण्ड (क) में विनियिप्त पदों के लिए काइर-संख्या का आधारागत विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न प्रकारों के कार्यक्रम की आवश्यकता के आधार पर अभिरक्षक द्वारा किया जाएगा। यदि इस प्रकार वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या आवश्यिक काइर-संख्या में अधिक हो जाती हो तो इस प्रकार वर्गीकृत किए जाने के लिए कर्मचारियों का नयन अहंताशों, गेजा-काल, और कार्य की दक्षता के आधार पर किया जाएगा।

(5) उम प्रवर्ग के जिसमें किसी कर्मचारी को नए वेतनमान में रखे जाने के प्रयोजन के लिए समतुदिष्ट किया जाएगा वारे में अभिरक्षक का विनियिचय कर्मचारी पर आवश्यक होगा।

6. विषयता को पढ़ति.—उन कर्मचारियों से जो नए वेतनमान द्वारा आसित नहीं होने का सुनाव करने हैं, भिन्न प्रत्येक कर्मचारी को उस प्रवर्ग में संबंधित नए वेतनमान में रखा जाएगा जिसमें वह नए

वेतनमान में मूल वेतन पर रखा जाता है जो निम्नलिखित अनुक्रमों के आधार पर अभिनियित तीनों रकमों में से सबसे अधिक रकम होती है:—

(क) उम प्रवर्ग में 1 जनवरी, 1973 की सेवा के प्रत्येक दो मंपूर्ण वर्षों के लिए प्रारम्भिक वेतनमान पर एक वृद्धि देकर।

गैर 4 के उप-पैरा (2) के खण्ड (घ) के उपमण्ड (ii) के अनुसार ज्येष्ठ महायकों के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों की बाबत, कनिष्ठ महायकों की श्रेणी में मूल वेतन इस अनुक्रम द्वारा अभिनियित किया जाएगा और ऐसे श्रेष्ठ सहायकों की श्रेणी में मूल वेतन को जो कनिष्ठ सहायकों की श्रेणी में मूल वेतन के समतुल्य या उससे ऊच्चतर है, उपर्युक्त मूल वेतन माना जाएगा।

यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेतन 270 रु. या अधिक हो किन्तु 500 रु. से अधिक न हो और श्रेणी की अधिकतम सीमा पर न हो तो, उस श्रेणी में मूल वेतन में एक और वेतन वृद्धि इस अनुक्रम के अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए दी जाएगी, या

(घ) यह अवधारित करके कि 1 जनवरी, 1973 को साए वेतनमान में मूल वेतन और मंहगाई भस्ते का योग उस तारीख को मूल वेतन और तत्संबंधी नवर्धन भत्ता या हाल के तदर्थे ममझीने के परिणामस्वरूप अनुदत्त तदर्थे वैयक्तिक वेतन और उम तारीख को तत्संबंधी मंहगाई भस्ते के योग के समतुल्य या उसके ठीक अगले वेतनस्तर से अधिक है।

यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेतन 245 रु. या अधिक हो किन्तु 315 रु. से अधिक न हो, और श्रेणी की अधिकतम सीमा पर न हो तो, उस श्रेणी में मूल वेतन पर एक और वेतन वृद्धि इस अनुक्रम के अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए दी जाएगी; या

(घ) यह अवधारण करके कि क्या नए वेतनमान में मूल वेतन अतंसामान कुल मूल वेतन और 10 रु. की रकम के योग के समतुल्य या उसके ठीक अगले वेतनस्तर से अधिक है,

यदि इस प्रकार अवधारित मूल वेतन 270 रु. या अधिक हो किन्तु 500 रु. से अधिक न हो और श्रेणी की अधिकतम सीमा पर न हो तो, उस श्रेणी में मूल वेतन पर एक और वेतन-वृद्धि इस अनुक्रम के अधीन मूल वेतन की रकम अवधारित करने के लिए दी जाएगी।

टिप्पण:—(1) अनुक्रम (ग) के प्रयोजन के लिए, “अंतेसामान मूल वेतन” पद से वह मूल वेतन अभिनेत्र है, जो कर्मचारी, यदि यह स्कॉल प्रशूत नहीं होती तो, 1 जनवरी, 1973 (उम तारीख को शोध्य वेतन-वृद्धि यदि कोई हो, के पश्चात्) को लेता और इसमें कोई अन्य रकम जैसे वैयक्तिक वेतन या हृत्यक भत्ता या तदर्थे भत्ता या कोई अन्य भत्ता, चाडे जिस नाम से भी जाना जाए, ऐसी रकमों के मंदाय से संबंधित नियंत्रणों और शर्तों में कोई उपबन्ध होते हुए भी सम्मिलित नहीं है।

टिप्पण:—(2) इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी, 1973 के ठीक पूर्व किसी ऐसी कम्पनी में, जिसमें मंहगाई भस्ते का कोई नियित मान नहीं है, संभेदित वेतन या भत्ता प्राप्त करता है, तो संभेदित वेतन मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा, किन्तु अभिरक्षक कर्मचारी के मामले में अंतेसामान मूल वेतन के रूप में मानी जाने वाली उपर्युक्त रकम अवधारित करेगा।

(2) यदि उप-पैरा (1) के अधीन यथा अवधारित मूल वेतन नए वेतनमान की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है तो, उसे नए वेतनमान की अधिकतम सीमा पर नियन किया जाएगा।

(3) जहाँ किसी कर्मचारी को उप-पैग (1) के अनुकूल (ब) या (ग) के आधार पर 270 रु. में कम सूल बेतन पर रखा जाता है और वह कर्मचारी का सूल बेतन, 1 जनवरी, 1974 को या के पूर्व वार्षिक बेतन-वृद्धि अनुदान किए जाने पर 270 रु. पर पहुंच जाता है या उसमें अधिक हो जाता है वश्या, कर्मचारी को उस थेणी में एक अतिरिक्त बेतन-वृद्धि दी जाएगी, जो उसकी वार्षिक बेतन-वृद्धि की तारीख से प्रभावी होगी।

(4) जहाँ किसी कर्मचारी को उप-पैग (1) के अनुकूल (ब) के आधार पर 215 रु. में कम सूल बेतन पर रखा जाता है और जहाँ कर्मचारी का सूल बेतन, 1 जनवरी, 1974 को या के पूर्व वार्षिक बेतन-वृद्धि अनुदान किए जाने पर 245 रु. पर पहुंच जाता है या उसमें अधिक हो जाता है वश्या, कर्मचारी को उस थेणी में एक अतिरिक्त बेतन-वृद्धि दी जाएगी, जो उसकी वार्षिक बेतन-वृद्धि की तारीख से प्रभावी होगी।

(5) जहाँ किसी कर्मचारी की बाबत हम पैग के अधीन 1 जनवरी 1973 को (नया सूल बेतन, भंगाई भना, अर्हता बेतन, कुल्यिक भना, गृह भाटक भना, नगर प्रतिकारास्वरूप भना और पहाड़ी रथान भना को समाविष्ट करते हुए) अवधारित कुल बेतन, उक्त तारीख के (फेवल बेतनमान सूल बेतन, भंगाई भना, नदर्श भना या नदर्श वैयक्तिक बेतन, कुल्यिक भना, अर्हता बेतन, गृह भाटक भना, नगर प्रतिकारास्वरूप भना पहाड़ी स्थान भना और नक्कड़ में अवृत्त लंच भना को समाविष्ट करते हुए) ठीक पूर्व के उसके कुल बेतन से कम हो वहाँ, बेतन नियन्त किए जाने के पश्चात् नया कुल बेतन में अधिक कुल बेतन की रूपमान कर्मचारी को नयक्तिक बेतन के रूप में दिया जाएगा।

7. बेतन वृद्धियाँ—(1) नए बेतनमान में बेतन वृद्धियाँ प्रतिवर्ष उस साम के प्रथम दिन को जिसमें, 1 जनवरी, 1973 के पूर्व अनियम बेतन वृद्धि अनुदान की गई थी या अगले साम के प्रथम दिन को जिस दिन को वह निरंतर सेवा के बारह मास पूरा कर नेता है, शोध्य छोगी। जहाँ बेतन-वृद्धि 1 जनवरी 1973 को शोध्य छोटी है वहाँ, कर्मचारी को उसके बेतनमान बेतनमान में एक वृद्धि देने के पश्चात् नया बेतनमान लागू किया जाएगा।

(2) ऐसे कर्मचारियों की बाबत जिनका सूल बेतन पैग (5) के अधीन, 1 जनवरी, 1973 को नए बेतनमान के अधिकानम पर नियन्त किया जाता है और उनके संघर्ष, में जो अपनी सेवा की अवधि के शीर्षक उसके पश्चात् किसी भी समय अधिकानम पर पहुंच जाएगा, यथास्थिति अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक कर्मचारियों के कार्य का नेपाई सतीषज्ञक पाते पर ही, उनके द्वारा 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् या उनके अपने-आपने बेतनमान के अधिकानम पर उनके पहुंचने की तारीख के पश्चात् की गई प्रत्येक दो वर्षों की सेवा के लिए एक अतिरिक्त बेतन वृद्धि और पश्चात्-वर्ती स्थिति में बेतनमान में ली गई अन्विष्ट वृद्धि के क्रियावर से देने के लिए विचार करेगा और इस उपबन्ध के अधीन अधिक में अधिक तीन ऐसी वृद्धियाँ अनुदान की जाएंगी।

8. काम के घर्वे—(1) (क) काम के घर्वे जो, सभी कार्यालयों में पर्यावर्की और लिपिकीय श्रेणियों के सभी कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यकरण दिन होंगे, सप्ताह दिनों में 45 मिनट के लंच के समय सहित, 10.00 बजे से 5.00 बजे होंगे और शनिवारों को 10.00 बजे से 2.00 बजे होंगे।

(ख) कार्यालयों में संलग्न अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के लिए काम के सामान्य घर्वे सप्ताह दिनों में 45 मिनट के लंच के समय सहित 9.30

बजे से 5.00 बजे होंगे और शनिवारों को 9.30 बजे से 2.00 बजे होंगे।

परन्तु टेलीफोन आपरेटरों, डाक विभाग कर्मचारिवृन्द और अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा विनियिष्ट किसी विशिष्ट विभाग के अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के लिए काम के घर्वे संबंध कार्यालय के सामान्य काम के घर्वों से भिन्न हो सकेंगे।

(2) चालकों और कर्मचारिवृन्द जैसे, नियमेन, कर्तीनर प्रहरी, विजली-मिस्ट्री नलाम और माली, के लिए काम के सामान्य घर्वे, शनिवार महिला सभी छह सप्ताह दिनों का 8 घर्वे होंगे, और प्राठ घर्वे की इस अधिकानम समग्र सीमा के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कार्यालय के लिए काम के बास्तविक घर्वे इस प्रकार होंगे जो अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियन्त किए जाएं।

9. अवकाशादित—सभी कार्यालय, परकार्मा लिक्विड अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन अवकाश दिनों के रूप में संबंधित राज्य गवर्नरों द्वारा धोयित सभी अवकाशादित मनाएंगे, किन्तु उन अवकाशदिनों को छोड़ देंगे जिन्हे वैकों को अपने लेखाओं को बदल करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अप्लाई देखित किया गया है। जहाँ पैमे अवकाशदिनों की संख्या किसी वर्ष में 22 दिन से कम हो वहाँ, पैमे अतिरिक्त अवकाशदित और अर्द्ध-अवकाशदिन, स्थानीय उच्चियों के अवसर पर मनाएं जा सकेंगे, जो कम्पनी के अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिकाशदित करें, परन्तु एक वर्ष में अवकाशदिनों की कुल संख्या 22 पूर्ण अवकाशदित और 3 अर्द्ध-अवकाशदिन से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी—अर्द्ध अवकाशदिनों की दशा में, कार्यालय या तो सामान्य कार्यकरण अवधि की लंच-पूर्व अवधि या लंच-पश्चात् अवधि के लिए बंब रहेगा। शनिवार को पहुंचे आपे अवकाशदिन पूर्ण अवकाशदिनों के रूप में याने जाएंगे।

10. छुट्टी—(1) इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कर्मचारी को निम्नलिखित प्रकारों की छुट्टी अनुदान की जा सकेंगी:—

- (क) आकस्मिक छुट्टी;
- (ख) उपार्जित छुट्टी;
- (ग) बोमारी छुट्टी;
- (घ) प्रसूनी छुट्टी;
- (ङ) परीक्षा छुट्टी;
- (च) वरनीन छुट्टी;
- (छ) व्यवसाय सव छुट्टी।

(2) किसी कर्मचारी को छुट्टी निम्नलिखित माध्यारण मिलान्तों के अनुकूल दी जाएगी:—

- (क) छुट्टी करनेवाले या मेशा द्वारा उपार्जित की जानी है;
- (ख) छुट्टी का दाशा अधिकारास्वरूप नहीं किया जा सकता है;
- (ग) यदि नियम या उसके किसी समनुरंगी की सेवा की अन्यावश्यकताओं से ऐसी अपेक्षा हो जो, किसी प्रकार की छुट्टी को छोड़कर करने या प्रतिसंदृढ़ करने का विवेकाधिकार उसे मज़बूत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी के पाय आरक्षित है।

टिप्पणी—छुट्टी की मंजूरी की उपलाग नहीं की जा सकेंगी और मांगी गई छुट्टी का उपयोग नब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसे विनियिष्टन: मंजूर नहीं किया गया जाए।

- (घ) यह अनुशेय होगा कि किसी प्रकार की छुट्टी से अवकाशदिनों या रविवारों को पहले या बाद में जोड़ दिया जाए;

(३) आकस्मिक छुट्टी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की लूटी के मात्र नहीं किया जाएगा। इस शर्त के प्रधीन रहते हुए, इस स्कौल के प्रधीन किसी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी किसी अन्य प्रकार की लूटी के मात्र, या शर्म में दी जा सकती।

(३) उपाजित छुट्टी:—(क) प्रत्येक कर्मचारी, निरत्य मेत्रा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन की उपाजित छुट्टी का लकड़ार होगा।

(ख) अधिकतम 120 दिन तक की छुट्टी किसी एक समय मंजूर की जा सकती।

(ग) उपाजित छुट्टी की वह अवधि, जो किसी कर्मचारी द्वारा सचिन की जा सकती, 180 दिन की होगी।

(४) आकस्मिक छुट्टी:—(क) किसी कर्मचारी को किसी कर्मचार वर्ष में अधिकतम 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुदान की जा सकती, किन्तु किसी समय 6 दिन से अधिक नहीं होगी। आकस्मिक छुट्टी का उपयोग सामान्यतः सदाचार प्राधिकारी द्वारा मंजूर दिए जाने के पश्चात् ही किया जा सकती; किन्तु एक दिन की आकस्मिक छुट्टी का उपयोग अनवेक्षित आपात की दशा में पूर्व मंजूरी के बिना किया जा सकता, परन्तु यह तब जब कि कार्यालय के प्रधान को उन परिस्थितियों के बारे में जिनमें पूर्व मंजूरी नहीं सी जा सकती, शीघ्र सचिन किया जाएगा है।

(ख) किसी सप्ताह दिन को या तो केवल पूर्वाह्न या शाराह्न के लिए आकस्मिक छुट्टी का उपयोग करना प्रतुक्षय है, उम वशां में छुट्टी भी वह अवधि आधा दिन मानी जाएगी, किन्तु गनिवार को या किसी ऐसे दिन को, जब कि आधे दिन के अवकाश की विधा पर गई है, तो गई छुट्टी पूर्ण दिन के स्वप्न में मानी जाएगी।

(५) बीमारी छुट्टी:—कोई कर्मचारी ऐसे, चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा, जो अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा चिरिंरिष्ट किया जाए, दिए गए चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर बीमारी छुट्टी का लकड़ार होगा। कर्मचारी प्रति वर्ष 30 दिन के हिसाब से बीमार छुट्टी का लकड़ार होगा और बीमारी की छुट्टी वह अवधि, जो किसी कर्मचारी द्वारा सचिन की जा सकती है, अधिकतम 240 दिन की होगी।

(६) प्रसूति छुट्टी:—कोई महिला कर्मचारी 90 दिन से अधिक प्रसूती छुट्टी की लकड़ार होगी। प्रसूत-पूर्व और प्रसूत-पश्चात् की अवधियों के बीच छुट्टी विस्तार कर्मचारी की सुविधा पर छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यदि कोई ऐसी महिला कर्मचारी, जिसके तीन जीवित बच्चे हों, प्रसूत के लिए छुट्टी नेती है, तो ऐसी छुट्टी उपाजित छुट्टी के स्वप्न में मानी जाएगी और यदि उपाजित छुट्टी अनुक्षय न हो तो उम दशा में बीमारी छुट्टी के स्वप्न में मानी जाएगी, जबकि ऐसी बीमारी छुट्टी प्रत्युक्षय हो।

(७) परीक्षा छुट्टी:—बीमा परीक्षा में ईडें वाले कर्मचारी को परीक्षा की बास्तविक कानाकाशि के लिए परीक्षा छुट्टी का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती और यदि काम के स्थान से भिन्न स्थान को परीक्षा में ईडें के लिए यात्रा करना प्रावधारक हो तो, निम्नतम केन्द्र को जाने और वहां से लौटने के लिए निम्नतम यात्रा-समय को भी परीक्षा छुट्टी के स्वप्न में माना जाएगा।

(८) करन्तीन छुट्टी:—अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक या अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अन्य अधिकारी गुण-गुण के आधार पर करन्तीन छुट्टी की प्रारंभना पर दिचार कर सकता, किन्तु कोई भी कर्मचारी ऐसी छुट्टी का दावा अधिकारात्मक नहीं करेगा।

(९) अवसाय संघ छुट्टी:—(क) किसी मान्यताप्राप्त संघ के और ऐसे संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट कम से कम 15 अविक्षियों में से प्रत्येक अविक्षिय

मद्भायिक अवसाय संघ के कार्ये के लिए विशेष छुट्टी प्रति वर्ष अधिक से अधिक 15 दिन तक, बास्तविक यात्रा समय घटा कर, मंजूर की जा सकती।

(ख) छण्ड (क) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त संघ के और ऐसे संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट कम से कम 20 अन्य अविक्षियों में से प्रत्येक अविक्षिय का असम्बूप प्रयोगजारी विशेष छुट्टी प्रति वर्ष अधिक से अधिक 10 दिन तक, बास्तविक यात्रा समय घटाकर, मंजूर की जा सकती।

11 अविक्षिय निधि:—प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन और मंजूर अन्य के 8 प्रतिशत के द्वितीय से अविक्षिय निधि में अभिदाय करेगा और निगम या उम के किसी अनुबंधी द्वारा समान अभिवाय किया जाएगा।

12. सेवानिवृत्ति:—सेवानिवृत्ति की आमान्य आयु 60 वर्ष की होती।

परन्तु कोई ऐसा कर्मचारी, जो किसी नाम के दौरान 60 वर्ष की आयु का हो जाता है, ठीक अपने नाम के प्रथम दिन को ही सेवानिवृत्त होगा।

13. उपदान:—उपदान मदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 19) के उपबन्धों के अनुसार किसी कर्मचारी को उपदान संबल किया जाएगा:

परन्तु निम्नलिखित शर्तों के प्रधीन रहते हुए, इस संघ के अधीन सदैय उपदान किसी भी दशा में 20 मास की मजदूरी या 20,000 रु. में जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा—

(i) जहाँ किसी कर्मचारी द्वारा अनिम सी गई मजदूरी 1,000 रु. में अधिक है तो इसे उपदान की मात्रा अवधारित करते के प्रयोगन के लिए 1,000 रु. में समझा जाएगा; और

(ii) वह दर, जिस पर उपदान संबल किया जाएगा निम्न अनुसार दर जाएगी।—

सेवा के पूरे किए गए वर्षों की मंजूरी	मास की मजदूरी की मंजूरी में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए उपदान की दर
12	0.6
13	0.7
14	0.8
15 या अधिक	1.0

स्पष्टीकरण:—इस पैग में, “मजदूरी” का वही अर्थ होगा जो उसे उपदान संबाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की आमा 2 वर्ष छण्ड (ध) में दिया गया है।

14. अतिकालिक भत्ता:—जब कभी भी कार्यालय के काम के हिस्से में यह आवश्यक पाया जाए, तो कर्मचारी से प्रमामान्य काम के घटों से परे काम करने की अपेक्षा की जा सकती। जब किसी कर्मचारी से किसी दिन उसके प्रमामान्य काम के घटों के पृष्ठात् आधे घटे से अधिक काम करने के लिए अपेक्षा की जाती है तो उसे निम्नानुसार परिकलित अतिकालिक भत्ता संदेन किया जाएगा:—

(क) पर्यवेक्षी और लिपिकीय कर्मचारिकर्ता:—जब प्रतिकालिक घटों की मंजूरी 42 काम-घटे से अधिक न हो, जिसके प्रत्येक रविवार से शनिवार एक सप्ताह के द्वैरात्र प्रमामान्य काम काज के घटे भी सम्मिलित हैं।

(i) मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा डेक्क गुणा होगी,

(ii) 12 घंटों में अधिक काम के अनिकालिक घंटों के लिए, जिसमें मप्ताह के दौरान प्रमाणात्मक काम घंटे भी सम्मिलित हैं—मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा दूगुणी होगी,

(ख) अधिकार्थ कर्मचारिकृत्व—जब अनिकालिक घंटों की मध्या सप्ताह के दौरान प्रमाणात्मक काम के घंटों को मिलाकर 45 घंटों में अधिक न हो तब—

(i) मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा डेक्क गुणा होगी,

(ii) 45 घंटों में अधिक काम के अनिकालिक घंटों के लिए, जिसमें मप्ताह के दौरान प्रमाणात्मक काम-घंटे भी सम्मिलित हैं—मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा दूगुणी होगी।

(ग) चालक और निर्माण कर्मचारिकृत्व—जब मप्ताह के दौरान काम के अनिकालिक घंटों की मध्या 7 घंटे में अधिक न हो तो—

(i) मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा डेक्क गुणा होगी,

(ii) सप्ताह के दौरान 7 घंटे से अधिक काम के अनिकालिक घंटों के लिए—मास के लिए मजदूरी की दर प्रति घंटा दूगुणी होगी।

(घ) साधारण—अवकाश दिनों और रविवारों को किए गए प्रतिकालिक काम के लिए संधाय उसी आशार पर किया जाएगा और अन्य दिनों के लिए है। किन्तु, रविवार को किए गए काम के लिए प्रतिक्रियात्मक श्रवकाण वित, अनिकाल भत्ता के सदाय के अनिरिक्त अपने सप्ताह के दौरान दिया जाएगा।

टिप्पणी:—अनिकाल की अवधि की निर्दिष्टतम आधे घंटे पर पूर्णाकृति किया जाएगा।

टिप्पणी:—किसी भी कर्मचारी को, किसी कर्नेंडर वर्ष में 90 घंटे से अधिक अनिकाल में काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा।

15 स्थानापन भत्ता:—किसी कर्मचारी से किसी उच्चतर प्रथर्ग में किसी पद का स्थानान्तरण रूप में भारसाधन धारण करने या सम्मुल्य पद का प्रतिरिक्त भारसाधन धारण करने की, जब किसी भी आवश्यक समझा जाए, अपेक्षा की जा सकेगी और जहाँ ऐसा स्थानापन रूप में भारसाधन या प्रतिरिक्त भारसाधन 15 दिन या अधिक की निरंतर अवधि के लिए किया जाता है अब तक कर्मचारी का निम्नलिखित रूप में प्रनुपातिक भत्ता दिया जाएगा, अर्थात्—

(i) उच्चतर प्रवर्ग पद पर स्थानापन किया जाना : प्रतिमास 100 रु. की अधिकतम रकम सीमा में रहने हुए अपने मूल बेतन का 20 प्रतिशत।

(ii) किसी समतुल्य पद का प्रतिरिक्त भारसाधन : प्रतिमास 50 रु. की अधिकतम रकम सीमा में रहने हुए अपने मूल बेतन का 10 प्रतिशत।

टिप्पणी:—यदि कर्मचारी ऐसे पद पर स्थानापन रूप में कार्य कर रहा है या वह ऐसे पद का अनिरिक्त भारसाधन धारण करना है जिस पर कुनिक भत्ता दिया जाता है तो कर्मचारी उस अवधि के लिए जिसके लिए वह स्थानापन रूप में कार्य

करता है या भारसाधन करता है, प्रनुपातिक कृतिक भत्ता प्राप्त करेगा।

16. यात्रा भत्ता:—किसी कर्मचारी से यात्राकीम कार्य के लिए दौरे पर जाने की अपेक्षा की जा सकेगी। यात्रा भत्ता और वित्राम भत्ता को दरें नदावे गते जिनके अधीन वे यांदेय होंगी, द्वितीय प्रनुपाती में यथाविनिर्दिष्ट होंगी।

17. घट्टी यात्रा सहायकी:—घट्टी यात्रा महावकी की दरें और ये जने जिनके अधीन ऐसी महावकी सदैह होंगी, तृतीय प्रनुपाती में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

18. स्थानान्तरण और कार्य-स्थान का परिवर्तन:—अभिरक्षक या प्रबद्ध निदेशक या अभिरक्षक या प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी कर्मचारी का एक किभाग में दूसरे में या किसी कम्पनी या निगम के एक कार्यालय से उस कम्पनी या किसी ग्रन्थ कम्पनी या निगम के दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण कर सकेगा।

19. कार्य-भार, मालक और व्यापारकरण:—(1) कार्य-भार भा ढांचा और कार्य-माप की पदानि ऐसी होंगी, जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा मांसों में पश्चात्त विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) प्रबन्ध निदेशक, मांसों से परामर्श करने के पश्चात् छंटनी किए विना ठीक-ठीक कार्यकरण के लिए आवश्यक विस्तार तक यंत्रीकरण पुरुष्यापन कर सकेगा:

20. उत्सव-अधिम—किसी कर्मचारी का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहने हुए उत्सव-अधिम अनुदान किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) उत्सव-अधिम प्रत्येक कर्नेंडर वर्ष के दौरान केवल एक बार अनुदान किया जाएगा;

(ख) कोई अधिम तब तक अनुदान नहीं किया जाएगा अब तक कि पहले लिया गया अधिम पूर्ण रूप से न चुका दिया गया हो;

(ग) अधिम की रकम एक मास के कुल बेतन या 400 रु., से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी;

(घ) अधिम को व्याज के बिना अधिक से अधिक वस मासिक किसी में चुका दिया जाएगा, जो उस मास से, जिसमें अधिम लिया गया है, प्रारम्भ होगा।

21. निर्बंधन:—यदि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी के निर्धारण के आरे में कोई संकेत या कठिनाई उत्पन्न हो तो, इसे केन्द्रीय सरकार को विविधत्य के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और वह सरकार उसका विविधत्य करेगी।

22. शिथिल करने की शक्ति—जहाँ प्रबन्ध निदेशक का समाधान हो जाए कि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के प्रशंसन से किसी विशिष्ट भास्त्र में कठिनाई होगी, तो वह श्राद्ध द्वारा और लेखकृत कारणों के आधार पर उस उपबन्ध की अपेक्षाओं को ऐसी सीमा तक और ऐसे अपवाद और शर्तों के अधीन रहने हुए जिन्हें वह सामते का व्यापारण और साम्यक रीति से विचार करने के लिए प्रावश्यक ममझे, छूट दे सकेगा यदि शिथिल कर सकेगा।

23. नये बेतनमान की अवधि.—नया बेतनमान प्रारम्भिक रूप से 31 दिसम्बर, 1976 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा और तस्वीरात् तथ तक प्रवृत्त रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उगमे परिवर्तन नहीं किया जाना।

24. अस्य सुविधाएः—कोई कर्मचारी ऐसी किसी सुविधा को पाने का हकदार नहीं होगा जो इस स्कीम से उद्भूत नहीं होती है।

25. सध्यारोही प्रभाव—तत्समय प्रवृत्त किसी करार, पंचाट या अन्य लिखत में अन्तिष्ठि कोई बात विरोध में होने हुए भी इस स्कीम के उपबन्धों प्रभावी होगे।

प्रथम अनुसूची

I. बेतनमाम (मूल बेतन)

क. पर्याप्तीय और लिपिकीय कर्मचारिष्वन्दः—
(पैरा 3 देखिये)

1. प्रधीनक

1 330-25-405-30-525-35-665-40-865 रु०

2. अपेक्ष सहायक

2 30-15-275-20-335-25-485-द०रो०-30-665-35-735 रु०

3. आशुलिपिक

2 30-15-275-20-335-25-485-द०रो०-30-665-35-735 रु०

4. महायक, टंकन, टेलीफोन आपरेटर, टेलेक्स आपरेटर, स्टागर्टी, पंच काई आपरेटर, यूनिट अभिलेख मणीन आपरेटर, परिकलन-यंत्र-प्रचालक, और अन्य समनुल्य पद : 175-10-235-15-295-20-395-द०रो०-25-495-30-585 रु०

5. अभिलेख लिपिक

1 65-6-177-7-191-8-215-9-260-10-300-15-390 रु०

क. अधिनस्थ कर्मचारिष्वन्द—

(1). आलक

1 66-5-181-6-199-7-234-8-274-9-310 रु०

(2) अस्य अधिनस्थ कर्मचारिष्वन्द

1 25-5-165-6-201-7-229-8-215 रु०

II. कृत्यिक भत्ता

अपने नियमित और मुक्य कृत्य के रूप में निम्नान्वित कृत्यों में से विस्तीर्ण में नियुक्ति कर्मचारियों को नीचे उपदर्शित रूप में कृत्यिक भत्ता दिया जाएगा—

(1) लिफ्टमैन, मणीन आपरेटर, प्रधान अपरामियों, जमादार या वास्तवियों के रूप में कार्य करने वाले अधीनस्थ कर्मचारिष्वन्द	20 रु० प्रतिमास
(2) बैंक में रोकड़ ले जाने या से ले जाने वाले अधीनस्थ कर्मचारिष्वन्द, जब किसी कलेण्डर मास के दौरान ले जाए गए रोकड़ की रकम सामान्यतः 25,000 रु० या अधिक हो	10 रु० प्रतिमास
(3) किसी कार्यालय में रोकड़ संभालने वाला रोकड़-दिया जब किसी कलेण्डर मास के दौरान रोकड़-संबद्धतार की कुल रकम गामान्यतः 25,000 रु० या अधिक हो	25 रु० प्रतिमास
(4) टेलेक्स आपरेटर, पंच काई आपरेटर और यूनिट अभिलेख मणीन आपरेटर	25 रु० प्रतिमास
(5) परिकलन-यंत्र प्रबालक	25 रु० प्रतिमास
(6) नियम के अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अभिरक्षक, महाप्रबन्धक, गहायक महाप्रबन्धक और समनुल्य पदों के आशुलिपिक	40 रु० प्रतिमास

टिप्पण 1:—कृत्यिक भत्ता लेने के लिए पात्र अवक्षियों की संख्या और नाम का अध्यारण, अभिरक्षक या प्रबन्ध निवेशक द्वारा किया जाएगा, जो कार्य की मात्रा और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

टिप्पण 2:—कोई कर्मचारी, किसी एक समय केवल एक कृत्यिक भत्ता लेगा।

टिप्पण 3:—छट्टी पर जाने वाला कोई कर्मचारी अपनी छट्टी अवधि के दौरान कृत्यिक भत्ता लेना चाहेगा, परन्तु यह तब जब कि वह अपनी छट्टी की समाप्ति पर उसी पद पर कार्य करें।

टिप्पण 4:—कोई भी कर्मचारी, अधिकार स्वस्थ, उम पद से संतुलन कृत्यिक भत्ते की उपयोग करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यालय का आवंठन किए जाने का दावा नहीं करेगा।

टिप्पण 5:—कोई भी कर्मचारी, कृत्यिक भत्ता वाले पद पर कार्य करने से डकार नहीं करेगा या यह शर्त नहीं रखेगा कि उसे वहाँ ऐसा भत्ता दिया जाए, जहाँ परधारी की मनुपस्थिति या अस्थायी कार्यालय के कारण कर्मचारी को उसके कार्यालय के प्रवान द्वारा ऐसा कार्य समनुदिष्ट किया गया है।

III. महगाई भत्ता

कर्मचारियों को लागू महगाई भत्ते के मान का अध्यारण निम्नानुगार देंगा :

सूचकांक—भारतीय थम पत्रिका में यथा प्रकाशित श्रीदोषिक कर्मकारों के लिए अधिक भारतीय औरत उगांडाका कीमत सूचकांक आधारित वर्ष : 1960-100

(2) महगाई भत्ते की दर—प्रत्येक कलेण्डर निमाही, अर्थात् जनवरी में मार्ज, अप्रैल से जून, जुलाई से भिन्नस्वर और अक्टूबर से दिसम्बर के दौरान कर्मचारियों को मंत्रय महगाई भत्ता ठीक पूर्ववर्ती कलेण्डर निमाही के सूचकांक के औरत पर आधारित होगा। इस प्रकार अप्रैल, मई और जून के लिए महगाई भत्ता पूर्ववर्ती अनवर्गी, फरवरी और मार्ज के औरत पर आधारित होगा और डम प्रकार यह अम अप्रैल तक रहेगा। निमाही औरत सूचकांक और 100 पर आधारित सूचकांक के शीघ्र के अन्तर को चार द्वारा विभाजित किया जाएगा और डम प्रकार अभिराष्ट्र पूर्ण भजनकल को निम्नवर्णित प्रतिशत के लिए गुणक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा—

मूल बेतन रेट

(i) जहाँ कर्मचारी का मूल बेतन 245 रु० या कम है	मूल बेतन का 4 प्रतिशत
(ii) जहाँ कर्मचारी का मूल बेतन 245 रु० से अधिक है किन्तु 700 रु० कम से कम है	मूल बेतन का तीन प्रतिशत, जिसकी न्यूनतम रणि 9.40 रु० होगी (अर्थात् जो 245 रु० का चार प्रतिशत है)
(iii) जहाँ कर्मचारी का मूल बेतन 700 रु० से अधिक है।	700 रु० का 3 प्रतिशत और अतिरिक्त का 2 प्रतिशत।

(3) महगाई भत्ते का पुनरीक्षण—महगाई भत्ते का पुनरीक्षण प्रत्येक चार अक्टूबर या घटने पर निमाही आधार पर किया जा सकेगा।

IV. अहता बेतन
कर्मचारी को मासिक भत्ता, जिसे शहरता बेतन कहा जाएगा, अनुदान किया जाएगा या निम्नलिखित आधार पर बेतन-जीनियां अनुदान की जाएँगी—

(1) इस स्कीम के प्रारम्भ होने पर विद्यमान अनुदानक महायकों को, जो 1 जनवरी, 1973 से पात्र वर्ष के भीतर स्नातकों के रूप में अँहित हो जाते हैं, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से उनके बैतनयान में दो बैतन वृद्धियों अनुदान की जाएगी।

(2) परिणाम के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित वीमा परीक्षा में अँहित करने यांत्रे किसी कर्मचारी को निम्न यथा-उपदण्डित अँहित बैतन की रकम संदर्भ की जाएगी :

प्रत्यन्तु एक अँहित बैतन से अधिक उत्तर प्रनुभीय नहीं किया जाएगा।

परीक्षा प्रति माह अँहित बैतन

वीमा संस्थान परिस्थ या

चार्टर्ड वीमा संस्थान

(i) अनुज्ञानिधारी

केवल महायकों या

ममतुल्य या निम्नतर

पदों को संदेय 15 रु

केवल ऊपरी गहायकों

या ममतुल्य या निम्न-

तर पदों को संदेय 25

रुपये

50 रु

(iii) फेलोशिप के पूरा करने पर

बीमांक संस्थान

(iv) कोई तीन विषय

25 रु

(v) कोई मान विषय

40 रु

(vi) फेलोशिप के पूरा करने पर

60 रु

चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान या सागत

और संकर्म सेक्यूरिटी संस्थान

(vii) हाटरमीशिएट पूरा करने पर

25 रु

(viii) एसोसिएटिशिप या फेलोशिप के पूरा करने पर

50 रु

(3) इस स्कीम के प्रारम्भ होने पर या के पासात् गहायकों को प्रवर्ग में या ममतुल्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को ।—

(क) सेक्वा में उनके पुष्टिकरण की तारीख गे, यदि वे पुष्टिकरण के पूर्व स्नातकों के रूप में सेक्वा ग्रहण करते हों या अँहित होते हों ;

(ख) परिणामों के प्रकाशन की तारीख से, यदि वे सेक्वा ग्रहण करने की तारीख से पात्र वर्ष की अवधि के भीतर स्नातकों के रूप में अँहित होते हों,

उम्मीदों में दो बैतन-वृद्धियां दी जाएंगी।

(4) अँहित बैतन के अनुदान या स्नातक होने पर बैतन-वृद्धियों से सबन्ध व्यक्ति की ऊपरीता प्रभावित नहीं होगी।

(5) यदि किसी कर्मचारी को अधिक बैतन-वृद्धि या किसी वीमा परीक्षा में अँहित हो जाते पर कोई अन्य शावर्ती धन संबंधी फायदा गहने हो दिया गया हो तो अँहित बैतन की रकम उपयुक्त रूप से कम कर दी जाएगी या अनुभेद नहीं होगी, यह पहले ही प्राप्त फायदे की मात्रा पर निर्भर होगा।

उदाहरण: यदि किसी महायको ने वीमा संस्थान परिस्थ की अनुज्ञित और एसोसिएटिशिप परीक्षाओं के पूरा करने के लिए दो बैतन-वृद्धियों ने

भी ही, जिनका धनीय मूल्य (क) 20 रु है तो—वह अँहित बैतन प्रतिमास 5 रु प्राप्त करेगा,

(ख) 30 रु है तो—वह कोई अँहित बैतन प्राप्त नहीं करेगा।

V. गृह भाटक भत्ता

कर्मचारियों की आवास गृह भाटक भत्ता, प्रति मास 10 रु की अधिक तम रकम के अधीन रहते हुए मूल बैतन के 10 प्रतिशत पर संदेय होगा। अधीनस्थ कर्मचारियून्द के लिए निम्नतम गृह भाटक भत्ता 22 रु और पर्यवेक्षी तथा नियिकीय कर्मचारियून्द के लिए 23 रु होगा।

VI. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

केन्द्रीय सरकार द्वारा समव्यवस्थ पर इस प्रकार घोषित सभी वर्ग 'क' श्रीर वर्ग 'ख' के नगरों में तैनात सभी कर्मचारियों को नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्रति मास 20 रु की दर से संदेय होगा।

VII. पहाड़ी स्थान भत्ता :

श्रीनगर, धर्मशाला, बागमुला, अनन्तनाम, पालनपुर, गिमला, प्रलोड़ा, तैनाताल, शिलाग, दर्जिकिंग, काठमाडू, ओटाकामड़ और मरकारा में तैनात कर्मचारियों को, प्रतिमास निम्नतम 20 रु और प्रतिमास 75 रु की अधिकतम सीमा में रहते हुए, उनके मूल बैतन के 15 प्रतिशत की दर से प्रत्येक मास पहाड़ी स्थान भत्ता दिया जाएगा।

VIII. किट भत्ता :

पैरा VII में सूचीबद्ध पहाड़ी स्थानों में से किसी स्थान को म्पातान्तरिन कर्मचारियों को 200 रु का किट भत्ता दिया जाएगा।

किट भत्ता एक पहाड़ी स्थान से दूसरे पहाड़ी स्थान को आनान्दण पर या यदि ऐसा भत्ता पूर्वामी 3 वर्ष के दौरान किसी समय लिया गया था तो, संदेय नहीं होगा।

IX. बर्दी और धुलाई भत्ता :

अधीनस्थ कर्मचारियून्द जिसमें चालक भी सम्मिलित हैं वो बर्दियों का दिया जाना और धुलाई करने या धुलाई भत्ता के संशय की अवस्था निमानुमार विनियमित होगी :

(i) कार्यान्वय बर्दिया अधीनस्थ कर्मचारियून्द जिसमें चालक भी सम्मिलित है, को दी जा सकती।

(ii) सूती बर्दी के 3 में प्रत्येक वर्ष एक बार अधीनस्थ कर्मचारियून्द जिसमें चालक भी सम्मिलित है, को दिए जा सकते। उन स्थानों में जो प्रबन्ध निदेशक द्वारा ऐसे स्थान विनियमित किए गए हैं जहाँ सर्दी अधिक पड़ती है, एक सूती बर्दी के बदले एक ऊनी बर्दी दी जा सकती और प्रत्येक दो बर्दी में नवीकृत की जा सकती।

(iii) ऊर कर्मचारी को, जिसे बर्दी दी गई है, वर्ष में एक बार एक जोड़ी नियमित दो बर्दी को दी जा सकती। जहाँ ऊनी बर्दी दी गई है, वहाँ बर्दावें के अन्वित दो वर्दी में एक बार एक जोड़े दिए जा सकते। जहाँ जूते दिए गए हैं वहाँ, वो जोड़े मोड़े भी प्रत्येक वर्ष दिए जा सकते। प्रत्येक ग्रन्तकल्पी वर्ष में एक बार एक छाता भी दिया जा सकता।

(iv) जहाँ सिगम या उमका कोई समनुष्ठानी, बर्दियों की धुलाई या सकाई करने की व्यवस्था नहीं करता वहाँ कर्मचारी को सुखर्दी, कलकत्ता, विल्ली और मत्राग में प्रतिमास 7 रु और अन्य स्थानों में प्रतिमास 5 रु की दर से धुलाई भत्ता अनुवत्त किया जा सकता। जहाँ ऊनी बर्दियां दी जाती हैं वहाँ उसके अन्वित वर्ष में एक बार वास्तविक ड्राईकलीनिंग-प्रभार की प्रतिपूति की जा सकती।

द्वितीय अनुसूची

(पैरा 6 देखिये)

1. कर्तव्यार्थ होने के द्वारा यात्रा और विराम भत्ता के लिए उक्तागी का विनियमन तीव्र ग्रथा उपदर्शित रूप में किया जाएगा।

क. यात्रा भत्ता

(1) रेल द्वारा यात्रा

प्रवर्ग

यात्रा का छंग

और श्रेणी

(i) 340 रु० और अधिक मूल बेतन वाले कर्मचारी

प्रथम श्रेणी

(ii) 340 रु० से कम मूल बेतन वाले कर्मचारी, जिनमें अधीनस्थ कर्मचारियन्द नहीं हैं

श्रेणी 2 या ए. सी श्रेणी
3*

(iii) अधीनस्थ कर्मचारियन्द

तृतीय श्रेणी

*जहाँ श्रेणी 2 या ए. सी श्रेणी 3 की व्यवस्था रखने द्वारा नहीं की गई है तबाँ, श्रेणी 1 द्वारा यात्रा अनुशासन की जा सकती। और, जहाँ यात्रा में रात की यात्रा भी गमिष्ठित है तबा समस्त यात्रा श्रेणी 1 द्वारा करनी अनुमति दी जाती।

2. स्टीमर द्वारा यात्रा

(i) 600 रु० से अधिक मूल बेतन पाले वाले उच्चतम श्रेणी कर्मचारी

(ii) 340 रु० और अधिक पाले वाले किन्तु दोनों श्रेणियों में से जो 600 रु० से कम पाले वाले कर्मचारी उच्चतर हो, और जहाँ वो श्रेणियों से अधिक की व्यवस्था हो वहाँ मध्यवर्ती या द्वितीय श्रेणी

(iii) 340 रु० से कम पाले वाले सभी कर्मचारी (अधीनस्थ कर्मचारियन्द में भिन्न)

दोनों श्रेणी में से जो निम्न-
तर हो, और जहाँ तीन श्रेणियाँ हो वहाँ मध्यवर्ती या द्वितीय श्रेणी यदि चार श्रेणियाँ हों तो तृतीय श्रेणी।

(iv) अधीनस्थ कर्मचारियन्द

निम्नतम श्रेणी

(3) सड़क द्वारा यात्रा

एकल स्थान संकर लोक परिवहन द्वारा *वास्तविक भाइ

*ग्रामीणस्थ कर्मचारियन्द के निवास न सभी कर्मचारियों के लिए उच्चतर श्रेणी द्वारा, यदि उमस्था अवस्था हो।

छ. विराम भत्ता

(क) विराम भत्ते की दरे निम्नलिखित रूप में होंगी, अर्थात्—

प्रवर्ग

रकम

(1) अधीनस्थ कर्मचारियन्द प्रतिदिन 10 रु०

(2) अधीनस्थ कर्मचारियन्द में भिन्न कर्मचारी

(i) 151-340 रु० के बीच मूल बेतन

प्रतिदिन 15 रु०

(ii) 341-600 रु० के बीच मूल बेतन

प्रतिदिन 25 रु०

(iii) 600 रु० से अधिक मूल बेतन

प्रतिदिन 30 रु०

(क) उपयुक्त विराम भत्ता में 25 प्रतिशत की वृद्धि मुम्हई, करकता, दिल्ली और मद्रास में अनुशासन की जाएगी।

(ग) मुख्यालयों से प्रत्येक 24 घंटे की अनुपस्थिति के लिए पूर्ण विराम भत्ता दिया जाएगा, अनुपस्थिति की अवधि, यात्रा प्रारम्भ करने के समय से और मुख्यालय लौटने के समय तक संगणन की जाएगी।

(घ) 24 घंटे में कम के लिए विराम भत्ता निम्नलिखित मात्र पर होगा :

(i) 12 घंटे के अधिक की अनुपस्थिति पूर्ण

(ii) 6 घंटे से अधिक किन्तु 12 घंटे से अनधिक की विराम भत्ते का अनुपस्थिति 50 प्रतिशत

(iii) 6 घंटे से कम विराम भत्ते का 30 प्रतिशत

(ङ) कर्मचर पर मुख्यालयों से प्रत्येक 30 दिन की अनुपस्थिति के लिए विराम भत्ता पूरी दरों पर और तत्त्वात् 90 दिन की अधिकतम अवधि तक प्रमाणान्य दरों की आधी दर पर अनुशासन किया जाएगा।

(च) ऐसे कर्मचारियों की दशा में, जो नियम या उसके किसी समनुष्ठानी द्वारा योग्यता अनुपस्थिति दरों में ठहरते हैं, यदि खाले या ठहरने की व्यवस्था सुपूर्ण हो तो विराम भत्ता प्रमाणान्य दर की आधी दर पर और यदि खाले और ठहरने, दोनों की व्यवस्था सुपूर्ण हो तो प्रमाणान्य दर की एक-चौथाई दर पर होगा।

11. स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता

भत्ता की दर और प्रत्येक सुगम शर्तें निम्नानुगार होंगी।

(क) कर्मचारी और उसके कुटुम्ब को उम यात्रा श्रेणी द्वारा, जिसके लिए कर्मचारी दोरे पर यात्रा करते के लिए हक्कावार है, यात्रा भत्ता अनुशासन किया जाएगा।

(ख) यात्रा के लिए अनुपस्थिति होतु, यात्रा पर बिताए गए समय के लिए कर्मचारी और उसके कुटुम्ब के मद्दस्त्रों को विराम भत्ता अनुशासन किया जाएगा। 12 वर्ष से कम उम्म के बढ़तों के लिए विराम भत्ता की हक्कावारी आधी दर पर होगी।

(ग) स्थानान्तरण पर कार्य ग्रहण करने का समय निम्नलिखित रूप में अनुशासन किया जाएगा :

(i) यदि कोई निवास-स्थान में परिवर्तन न हो तो एक दिन, इस प्रयोजन के लिए रविवार या अवकाश दिन को एक दिन के रूप में गिना जाएगा।

(ii) यदि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाने के कारण निवास-स्थान में परिवर्तन होता हो तो नैयारी के लिए 6 दिन और यात्रा भत्ता भग किये बिना विभिन्न प्रकार के परिवहन द्वारा की गई यात्रा का वास्तविक समय।

(घ) निजी सामान के परिवहन पर व्यायों की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर होगी :—

मूल बेतन से वाले कर्मचारियों के लिए कुटुम्ब महिला कुटुम्ब के बिना

600 रु० से अधिक 20 क्वीटप 10 क्वीटप

151 रु०-600 रु० के बीच 15 क्वीटप 7.5 क्वीटप

150 रु० तक 6 क्वीटप 2.5 क्वीटप

सामान मालगाड़ा द्वारा या यात्री गाड़ी द्वारा या यदि रेल परिवहन उपलब्ध न हो सो, परिवहन के अन्य प्रकार द्वारा इन शर्तों के अधीन जै जाया जा सकेगा कि परिवहन का बच्चे, मालगाड़ी द्वारा आनुभव अधिकार नम राशि में अधिक न हो।

(इ) मड़क द्वारा परिवहन की दर, प्रत्येक 35 कि० ग्रा० या उसके भाग के लिए प्रति कि० मी० 3 पैसे होंगी।

नियाम-स्थान से रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से नियाम स्थान तक भासान की छुट्टाई के लिए वही दरें लागू होंगी।

(ज) पैकिंग प्रभारों के लिए प्रतिपूर्ति निम्नानुमार होगी :

- (i) 340 रु० से कम मूल बेनन लेने वाले कर्म- प्रति कि० ग्रा० एक पैसे चारियों के लिए।
- (ii) 340 रु० और अधिक मूल बेनन लेने वाले प्रति कि० ग्रा० 2 पैसे कर्मचारियों के लिए।

(छ) पैकिंग और छुट्टाई की प्रतिपूर्ति के अनावा कर्मचारियों को निम्नलिखित मान दर स्थानान्तरण अनुदान किया जाएगा :

मूल बेनन	स्थानान्तरण अनुदान
150 रु० तक	100 रु०
151—600 रु० के बीच	200 रु०
600 रु० से अधिक	300 रु०

टिप्पणी—इस अनुसूची में, किसी कर्मचारी के संबंध में, "कुटुम्ब" के अन्तर्गत पति या पत्नी, धर्मज आश्रित बच्चे और कर्मचारी के माय रहने वाले और पूर्ण आश्रित माना-पिना है।

तृतीय अनुसूची

(पैरा 17 देखिये)

छुट्टी यात्रा सहायकी

(क) किसी कर्मचारी और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को प्रत्येक दो कलेण्डर वर्षों के ब्लाक में एक बार यह रियायत उपलब्ध होयी परन्तु यह तब जब कि काम-से-कम 15 दिन की उपर्याजित छुट्टी पर जाना हो। प्रथम ब्लाक कलेण्डर वर्ष 1974-75 का होगा।

(ख) कर्मचारी दोनों तरफ के पहले 200 किलो० के लिए यात्रा की लागत स्वयं बहन करेगा और दोनों तरफ के अपारे 1000 किलो० तक यात्रा की सामान नियम या उसकी किसी भौमनुषंगी द्वारा बहन की जाएगी। प्रधीनस्थ कर्मचारिकृद की बाबत दोनों तरफ के 1000 किलो० तक की यात्रा की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को की जाएगी।

(ग) प्रतिपूर्ति, उस श्रेणी के रेल भाड़ा या स्ट्रीमर भाड़े के आधार पर, जिसके द्वारा कर्मचारी दौरे पर कर्तव्यारूढ़ यात्रा का हकदार है, या उस श्रेणी द्वारा जिसके द्वारा वह या उसका कुटुम्ब बस्तुतः यात्रा करता है, जो भी कम हो, की जाएगी। मड़क द्वारा याद की दौरे पर यात्राश्री को याएं दर लागू होगी। यदि कर्मचारी अपनी साथियों में यात्रा करता है या कोई सवारी भाड़े पर लेता है तो, शाब्द के बल कर्मचारी तक शीघ्रता होगा।

(घ) रियायत या तो कर्मचारी के गृह की यात्रा के लिए या उसके चूनाव के किसी अन्य स्थान के लिए उपलब्ध होगी।

(इ) कर्मचारी 1000 कि०मी० से अधिक यात्रा के लिए अपने हकदारी की श्रेणी से धिन श्रेणी द्वारा यात्रा कर सकेगा किन्तु उसकी

जो प्रतिपूर्ति की जाएगी वह उसके द्वारा दिए गए वास्तविक भाड़े तक सीमित होगी जो उप-पैरा (ब) और (ग) के अधीन देय राशि तक सीमित होगी।

(च) रियायत को अप्रार्थी नहीं किया जाएगा और यह उस राशि में उपलब्ध नहीं होगी जबकि कर्मचारी स्वयं 15 दिन से अधिक छुट्टी पर नहीं जाता है।

(छ) रियायत कर्मचारी के कुटुम्ब के उन सदस्यों को, जो कर्मचारी के साथ या पूर्व या पीछे जाने हैं, छह मास से अनधिक अवधि के लिए उस परिणाम तक जिस तक कर्मचारी को है, ग्राह्य होगी, परन्तु यह तब जबकि छुट्टी की अवधि के दौरान कर्मचारी और उसका कुटुम्ब उसी आस्थान पर हो है।

टिप्पणी : इस अनुसूची में, कर्मचारी के मवन्ध में, 'कुटुम्ब' के अन्तर्गत कर्मचारी के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित पति या पत्नी, धर्मज आश्रित संतान और माना-पिना आवै है।

[पाठ० मं० 65(19) आठवाँ अन्त० एम० 111/21/73]

ग्राह० श० ३० शापर, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रस्तर कर शोर्ड

नई दिल्ली, 13 बार्च, 1974

प्रावेश

पाठ० शा० 1608—केन्द्रीय प्रस्तर कर शोर्ड, धन कर नियम, 1957 के नियम 3 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम देता है कि इसमें संलग्न मारणी के स्तम्भ (2) में विनियिट प्रत्येक मूल्यांकन अधिकारी यारणी के स्तम्भ (3) में नस्बांधी प्रविष्टि में विनियिट आयकर-आयकूपों की प्राक्षेपिक अधिकारियों के भीतर के क्षेत्रों में कृषि भूमि की बाबत मूल्यांकन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा :

सारांशी

क० मं० मूल्यांकन अधिकारी	आयकर-आयकूप
1	2
मर्व श्री	
1. ग्राह० बेंटारामन अय्यर, आयकर अधिकारी मैसूर० [श्रीरा० II] कम्पनी मॉकिल, बंगलौर।	3
2. श्री० एम० बेशाद्री, आयकर अधिकारी, मैर- कारा।	—पर्योक्त—
3. श्री० गोपीनाथ, आयकर अधिकारी (मंग- लौर) बंगलौर।	—पर्योक्त—
4. ए० वृग्राम, आयकर अधिकारी, गुलबर्ग	—पर्योक्त—
5. श्री० गोविन्दा, आयकर अधिकारी, मंगलौर	—पर्योक्त—
6. श्री० एन० गुड्डपा, आयकर अधिकारी, निधि- रण-3, मॉकिल-1, मंगलौर।	—पर्योक्त—

1	2	3
7.	एम० वेस्टरामन, आयकर अधिकारी, मॉकल-1	--प्रधोक्तन-- बंगलौर।
8.	आर० ए० एग० गोतम, आयकर अधिकारी	कानपुर-I और II
9.	पी० सरसेना, आयकर अधिकारी	--प्रधोक्तन--
10.	ए० एन० प्रसाद, आयकर अधिकारी	--प्रधोक्तन--
11.	मुरेश कपूर, आयकर अधिकारी	--प्रधोक्तन--
12.	के० एम० यादव, आयकर अधिकारी	--प्रधोक्तन--

[सं० 14/74/फा० सं० 328/63/73—उक्त्यू० टो० (कृषि भूमि)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

ORDER

New Delhi, the 13th March, 1974

S.O.1608:—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Valuation Officer specified in Column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of agricultural lands in the areas within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry in column (3) of the Table :

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioner of Income-tax	
1	2	3	
S/Shri			
1.	R. Venkatarama Iyer, Income-tax Officer, Company Circle, Bangalore	Mysore I & II	
2.	B. S. Seshadri, Income-tax Officer, Mysore	Do.	
3.	G. Ramegowda, Income-tax Officer, (Collection), Bangalore	Do.	
4.	A. Vecaranna, Income-tax Officer, Gulbarga	Do.	
5.	C. Govindan, Income-tax Officer, Mangalore	Do.	
6.	B. N. Gundappa, Income-tax Officer, Assessment-3, Circle-I, Bangalore	Do.	
7.	S. Venkataraman, Income-tax Officer, Circle-I, Bangalore	Do.	
8.	R. A. S. Gautam, Income-tax Officer	Kanpur-I & II	
9.	P. Saxena, Income-tax Officer	Do.	
10.	A. N. Prasad, Income-tax Officer	Do.	
11.	Suresh Kapoor, Income-tax Officer	Do.	
12.	K. S. Yadava, Income-tax Officer	Do.	

[No. 14/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Agricultural Lands)]

का० आ० 1009.—केन्द्रीय प्रश्नकार बोर्ड, धन-कर नियम, 1957 के नियम 3क के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त अकिलों का प्रयोग करने हुए, निदेश देता है कि इसमें उपायज्ञ मारणी के स्तरम् (2) में विनिविष्ट प्रथेक मूल्योक्तन अधिकारी—

- (i) कोंपनियों के, जिनमें उनके रजिस्ट्रीड कार्पोरेशन भी गमिलित हैं, स्टॉक अंशों, डिवेलरों और प्रतिभूतियों;
- (ii) भागीदारी फर्मों के जिनमें उनके मूल्य कार्पोरेशन भी गमिलित हैं, अंशों;
- (iii) प्रतिभूतियों, मित्राय उनके जो लंबे (i) में उल्लिखित श्रीर मिथन हों और;
- (iv) चालू कारबाह की कागजार आमिलों, की बाबत मारणी के स्तरम् (3) में की नतंबंधी प्रविष्टि में विनिविष्ट आयकर आयकरों की प्रादेशिक अधिकारियों के भीभत के खेतों में मूल्योक्तन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करेगा।

स्वल्पकरण: भारत में “कारबाह आमिलों” में गुडबिल भी गमिलित है किन्तु इनके प्रत्यंगत स्थावर संपत्ति, कृषि-भूमि, आगान, घन, खान तथा खदान, मर्णीनशी तथा संयंत्र, आमूषण, कलाकृति और आजीवन द्वित, प्रतिवर्तन तथा प्रत्याशा द्वित नहीं हैं।

सारणी

क्रम सं०	मूल्योक्तन अधिकारी	आयकर आयकर
1	2	3
संवंशी		
1.	के० मुथुशाळामुश्शामणियन, II आयकर अधिकारी, कानपुर-I और II कार्पोरी, कंपनी मक्किल, बंगलौर।	
2.	बी० गोपाला अग्रवाल, III आयकर अधिकारी, कंपनी मक्किल, बंगलौर।	--प्रधोक्तन--
3.	आर० ठोठाड़ी, आयकर अधिकारी, निर्धारण-7, मॉकल-1, बंगलौर।	--प्रधोक्तन--
4.	आर० वेस्टरामन्था अग्रवाल, आयकर अधिकारी, कार्पोरी, कंपनी मक्किल, बंगलौर।	--प्रधोक्तन--
5.	के० बी० मुकर्जी, आयकर अधिकारी	कानपुर-I और II
6.	बी० एल० सच्चन, आयकर अधिकारी	--प्रधोक्तन--
7.	एम० सी० शर्मा, आयकर अधिकारी	--प्रधोक्तन--

[सं० 16/74/फा० सं० 328/63/73-प्रन-कर(गोर्म)]

S.O. 1609.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 3A of the Wealth tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Valuation Officer specified in column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of the a valuation officer in respect of :—

- (i) Stock shares, debentures and Securities of companies with their registered offices;
- (ii) Shares in partnership firms with their head offices;

(iii) Securities, other than those mentioned in clause (i) and situated and
 (iv) Business assets of business carried on; in the areas within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry to column (3) of the Table.

Explanation : In the order "business assets" includes goodwill but does not include immovable property, agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries, machinery & plant, jewellery, works of art and life interest, reversions and interest in expectancy.

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioners of Income-tax
1	2	3
<i>S/Shri</i>		
1.	K. Muthubalasubramanian, II Income-tax Officer, Company Circle, Bangalore	Mysore-I & II
2.	B. Gopala Iyer, III Income-tax Officer, Company Circle, Bangalore.	-do-
3.	R. Thothathri, Income-tax Officer, Asst-7, Circle-I, Bangalore.	-do-
4.	R. Venkatarama Iyer, I Income-tax Officer Company Circle, Bangalore.	-do
5.	K.B. Mukerji, Income-tax Officer	Kanpur-I & II
6.	B.L. Sachan, Income-tax Officer	-do-
7.	M.C. Sharma, Income-tax Officer	-do-

[No. 16/74/F. No. 328/68/73-W.T. (Shares)]

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1974

का. आ० 1610 :—केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, धन-कर नियम, 1957 के नियम 3के के उपनियम (2) द्वारा प्रवत्त जनकियों का प्रयोग करते हुए, मूल्यांकन नियम देता है कि इसमें उपाखण्ड मारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी, सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त की अधिकारिता के भीतर के श्रेणी में, हृषि भूमि (धन-कर नियम, 1957 के नियम 3के के उपनियम (4) में निर्वैधित वागानों से भिन्न) की बाबत, मूल्यांकन अधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा।

सारणी

क्रम सं०	मूल्यांकन अधिकारी	आयकर आयुक्त
1	2	3
<i>सर्वश्री</i>		
1.	आर० एल० वहन आयकर अधिकारी,	पश्चिमी बंगाल-I से VI फलकता

36 GI/74-3.

1	2	3
2. एम० पी० गिह आयकर अधिकारी		—पथोक्त—
3. राम प्रसाद, आयकर अधिकारी		राजस्थान

[मा० 23/74 का० मा० 328/63/73-ध० क० (हृषि भूमि)]

ORDER

New Delhi, the 29th March, 1974

S.O.1610.—In exercise of the powers conferred by sub-rule 2) of Rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every Valuation Officer specified in Column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of agricultural lands (other than plantations referred to in sub-rule (4) of rule 8 A of the Wealth-tax Rules, 1957) in the areas within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry in Column (3) of the Table.

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioner of Income-tax
1	2	3
<i>S/Shri</i>		
1.	R.L. Bahl, Income-tax Officer, Calcutta.	West Bengal-I to VI
2.	S.P. Singh, Income-tax Officer.	-do-
3.	Ram Prasad, Income-tax Officer.	Rajasthan

[No. 23/74/F. No. 328/62/72-W.T. (Agricultural lands)]

आदेश

का. आ० 1611.—केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, धन-कर नियम, 1957 के नियम 3के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देता है कि इसमें उपाखण्ड मारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मूल्यांकन अधिकारी, सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त की अधिकारिता के भीतर के श्रेणी में,—

- (i) कम्पनियों के, उनके रजिस्ट्रीड फार्मलियों सहित, स्टाक शेयरों विवेचनों और प्रतिभूतियों;
- (ii) भागीदारी कर्मी में, उनके मूल्य फार्मलियों सहित, शेयरों;
- (iii) छाप्ट (i) में वर्णित और अवस्थित प्रतिभूतियों से भिन्न प्रतिभूतियों, और
- (iv) अलाये गये कारबार की कारबार भालियों की बाबत मूल्यांकन अधिकारी के कृत्यों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण: इस आदेश में "कारबार भालियों" में सूनाम भी सम्मिलित है, किन्तु इसमें स्थावर सम्पत्ति, हृषि भूमि, बागान, बन, खाने और खदान में मारणी और संयंत्र, आमूषण, कलाकृति और आजीवन हित, प्रतिष्ठान और प्रत्याशा हित नहीं है।

सारणी		
सं०	मूल्यांकन अधिकारी	आयकर आयुक्त
1	2	3
सर्वश्रेष्ठ		
1. एम० के० दत्ता, आयकर आयुक्त, कलकत्ता पश्चिमी बंगाल-J से VI	—पथोक्त—	
2. आर० के० सेन, आयकर आयुक्त, कलकत्ता	—पथोक्त—	
3. एम० सी० नागपाल, आयकर आयुक्त	दिल्ली-I से III	
4. एम के० जैन, आयकर आयुक्त	—पथोक्त—	
5. एस० एस० भगवाल, आयकर आयुक्त	—पथोक्त—	
6. श्री० एम० बाही, आयकर आयुक्त	—पथोक्त—	
7. के० के० सूद, आयकर आयुक्त	—पथोक्त—	
8. जगदीश प्रसाद, आयकर आयुक्त	—पथोक्त—	
9. आर० डी० गुप्ता, आयकर आयुक्त	—पथोक्त—	
10. एस० एन० सोनी, आयकर आयुक्त, जयपुर	राजस्थान	
11. रघुबीर सिंह, आयकर आयुक्त, जयपुर	—पथोक्त—	

[सं० 21/74/फा० सं० 328/6373 ध० क० (प्रेसर)]

ORDER

S.O.1611.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 3A of the Wealth-tax Rules, 1957, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that every valuation officer specified in column (2) of the Table appended hereto shall perform the functions of a Valuation Officer in respect of:—

- (i) Stock shares, debentures and securities of companies with their registered offices;
- (ii) Shares in partnership firms with their head offices;
- (iii) Securities, other than those mentioned in clause (i), and situated;
- (iv) Business assets of business carried on, in the area, within the territorial jurisdiction of the Commissioners of Income-tax specified in the corresponding entry in column (3) of the Table.

Explanation : In the order "business assets" includes goodwill but does not include immovable property, agricultural lands, plantations, forests, mines and quarries, machinery and plant, jewellery, works of art and life interest, reversions and interest in expectancy.

TABLE

S. No.	Valuation Officer	Commissioner of Income-tax
1	2	3
S/Shri		
1. S.K. Dutta, Income-tax Officer, Calcutta.	West Bengal-I to VI	
2. R.K. Sen, Income-tax Officer, Calcutta.	-do-	
3. M.C. Nagpal, Income-tax Officer.	Delhi-I to III	

1	2	3
4. M.K. Jain, Income-tax Officer	Delhi-I to III	
5. S.L. Agarwal, Income-tax Officer	-do-	
6. V.S. Wahi, Income-tax Officer	-do-	
7. K.K. Sud, Income-tax Officer	-do-	
8. Jagdish Parshad, Income-tax Officer	-do-	
9. R.D. Gupta, Income-tax Officer	-do-	
10. S.N. Soni, Income-tax Officer, Jaipur	Rajasthan	
11. Raghbir Singh, Income-tax Officer, Jaipur	-do-	

[No. 21/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares)]

तुदि-पत्र

का०पा० 1612.—(क) बोर्ड का प्रादेश सं० 7/74/फा० सं० 328/63/73-डस्ट्यूटी० (प्रेसर), तारीख 2 फरवरी, 1974 से संलग्न सारणी के स्तम्भ (3)में ऋम सं० 21, 22, 23 और 24 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'पटियाला' पढ़े और ऋम सं० 25, 26, 27 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'मृतसर' पढ़े।

(म) बोर्ड का प्रादेश सं० 9/74/फा० सं० 328/63/73-डस्ट्यूटी० (क्षमि भूमि), तारीख 2 फरवरी, 1974 से संलग्न सारणी के स्तम्भ (1) में '32' के पश्चात '53' के स्थान पर '33' रखा जाएगा और उक्त प्रादेश सं० 9, तारीख 2 फरवरी, 1974 के स्तम्भ (3) में ऋम सं० 18, 19, 23, 24, 32 और 33 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'पटियाला' पढ़े और ऋम सं० 20, 21, 22, 26, 28, 30 और 31 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर 'मृतसर' पढ़े।

[सं० 25/74/फा० सं० 328/63/73-डस्ट्यूटी०]

श्री० डी० वाखरकर, अवर सचिव

CORRIGENDUM

S.O. 1612.—(a) In column (3) of the Table appended to the Board's Order No. 7/74-F. No. 328/63/73-W.T. (Shares) dated the 2nd February, 1974, read 'Patiala' for the existing entries against S. Nos. 21, 22, 23 and 24, and read 'Amritsar' for the existing entries against S. Nos. 25, 26 and 27.

(b) In column (1) of the Table appended to the Board's Order No. 9/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Agricultural lands) dated the 2nd February, 1974, '33' be substituted for '32' after '32' and in column (3) of the said Order No. 9 dated the 2nd February, 1974, read 'Patiala' for the existing entries against S. Nos. 18, 19, 23, 24, 32 and 33 and read 'Amritsar' for the existing entries against S. Nos. 21, 22, 26, 28, 29, 30, 31.

[No. 25/74/F. No. 328/63/73-W.T.]

V. D. WAKHARKAR, Under Secy.

नई विल्ली, 8 अप्रैल, 1974

शुद्धि-पत्र

का० आ० 1613.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड के आदेश सं० 7/74/का० सं० 328/63/73-ध०क० (शेयर), तारीख 2 फरवरी, 1974 में स्तम्भ (3) के नीचे कम सं० 3 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “मद्रास-I और II तथा ग्रान्थ प्रदेश-I और II” रखा जाएगा और कम सं० 4 से 8 के मामने की प्रविष्टि के स्थान पर “मद्रास-I और II” रखा जाएगा।

[सं० 26/74/का० सं० 328/63/73-ध०क० (शेयर)]

एस० बापू, अवर सचिव

New Delhi, the 8th April, 1974

CORRIGENDUM

S.O. 1613.—In the Central Board of Direct Taxes Order No. 7/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares), dated 2nd February, 1974 the existing entry under column (3) against S. No. 3 shall be substituted by “Madras-I & II and Andhra Pradesh-I & II” and against S. Nos. 4 to 8 by “Madras (Shares) I & II”.

[No. 26/74/F. No. 328/63/73-W.T. (Shares)]

S. BAPU, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग

नई विल्ली, 13 जून, 1974

का० आ० 1614.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10ब० के उपर्युक्त 30 मितम्बर, 1974 तक बड़ी दोआवृ बैंक लिं०, होशियारपुर पर लागू नहीं होंगे।

[सं० 15 (6)-भी० आ० III/73]

मे० भा० उमरांवकर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Banking)

New Delhi, the 13th June, 1974

S.O. 1614.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 10B of the said Act shall not apply to the Bari Doab Bank Ltd., Hoshiarpur, till the 30th September, 1974.

[No. 15(6)-B. O. II/73]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया

नई विल्ली, 15 जून, 1974

का० आ० 1615.—रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुमति में मई, 1974 की 31 तारीख को समाप्त हुए सम्भाह के लिये लेखा दण्ड विभाग

देप्ताएं	रुपये	रुपए	प्राप्तियां	रुपए	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	22,87,02,000		सोने का सिक्का और मुदि-यन:-		
संचलन में नोट . . .	64,61,06,65,000		(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा		
			दुमा विदेशी प्रतिभूतियां	160,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट	64,83,93,67,000		जोड़	349,27,02,000	
			रुपये का सिक्का	6,04,16,000	
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिभूतियां	€ 1,28,62,49,000	
			वेशी विनियम बिल और		
			दूसरे आणिंज्य-पत्र		
कुल देप्ताएं . . .	64,83,93,67,000		कुल प्राप्तियां	64,83,93,67,000	

तारीख 5 जून, 1974

वी०धी० चाहो, उप गवर्नर

31 मई, 1974 को रिजर्व बैंक भारत इंडिया के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

वेतनाएँ	रुपए	आस्तियाँ	रुपए
चुक्ता पूँजी	5,00,00,000	नोट	22,87,02,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	6,83,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,57,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	85,00,00,000	खरीद और भूनाये गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	205,00,00,000	(क) देशी	267,98,62,000
जमाराशियाँ:-		(ख) विदेशी	
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	130,93,52,000
(i) केन्द्रीय सरकार	50,91,12,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	602,74,51,000
(ii) राज्य सरकारें	13,84,32,000	ऋण और अधिमः—	
(ख) बैंक		(i) केन्द्रीय सरकार को	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	581,83,99,000	(ii) राज्य सरकारों को	146,34,07,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	15,83,59,000	ऋण और अधिमः—	
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,36,43,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	407,38,31,000
(iv) अन्य बैंक	69,18,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को (i)	182,36,31,000
		(iii) दूसरों को	10,45,23,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से	
		ऋण, अधिम और निवेश	
(क) ऋण		(क) ऋण और अधिम :-	
		(i) राज्य सरकारों को	67,94,37,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	16,67,31,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिक्षक बैंकों को	
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	36,70,00,000
(ग) अन्य	372,66,24,000	(ख) केन्द्रीय भूमिक्षक बैंकों के डिवेंचरों में निवेश	
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से	
		ऋण और अधिम	11,31,64,000
देय बिल	104,99,21,000	राज्य सहकारी बैंक को ऋण और अधिम राष्ट्रीय	
		औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से	44,16,19,000
अन्य वेतनाएँ	683,82,09,000	ऋण, अधिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अधिम	173,56,86,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा आरी किये गये बोर्डों/डिवेंचरों	
		में निवेश	
		अन्य आस्तियाँ	165,65,84,000
रुपए	25,09,96,17,000	रुपए	25,09,96,17,000

*खारी, आबधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिष्ठूतियाँ शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि में से किए गये निवेश शामिल नहीं हैं।

†राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी और रद्दापट शामिल हैं।

‡रिजर्व बैंक भारत इंडिया अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सीयादी बिलों पर अधिम दिये गये 103,85,98,000 रुपए शामिल हैं।

(i) गर्जीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अधिम शामिल नहीं हैं।

[सं.फा. 10/1/74—बी.ओ. १]

वी. ओ. चारी, उप गवर्नर

Reserve Bank of India

New Delhi the 15 June, 1974

S.O...1615 AN ACCOUNT PURSUANT TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, FOR THE WEEK ENDED THE 31st DAY OF MAY, 1974 ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Day	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department		22,87,02,000		Gold Coin and Bullion —		
Notes in circulation		6461,06,65,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
Total Notes issued			6483,93,67,000	(b) Held outside India		
				Foreign Securities	166,73,97,000	
						Total 349,27,02,000
				Rupee Coin		6,04,16,000
				Government of India Rupee		6128,62,49,000
				Securities		
				Internal Bills of Exchange and Other Commercial paper		
Total liabilities			6483,93,67,000	Total Assets		6483,93,67,000

Dated, 5th June 1974

V.V. CHARI, Dy. Governor

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 31st May, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	22,87,02,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	6,83,000
		Small Coin	3,57,000
		Bills Purchased and Discounted:—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	(a) Internal	267,98,62,000
		(b) External	
		(c) Government Treasury Bills	130,93,52,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	Balances Held Abroad*	602,74,51,000
		Investments**	222,75,97,00 0
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government	
		(ii) State Governments @.	146,34,07,000
Deposits :—		Loans and Advances to :—	
(a) Government		(i) Scheduled Commercial Banks +	407,38,31,000
(i) Central Government	50,91,12,000	(ii) State Co-operative Banks ++	182,36,31,000
(ii) State Governments	13,84,32,000	(iii) Others	10,45,23,000
		Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(b) Banks		(a) Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	581,83,99,000	(i) State Governments	67,94,37,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	15,83,59,000	(ii) State Co-operative Banks	16,67,31,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,36,43,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	
(iv) Other Banks	69,18,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	36,70,00,000
(c) Others	372,66,24,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,31,64,000
Bills Payable	104,99,21,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
Other Liabilities	683,82,09,000	Loans and Advances to State Co-operative Banks	44,16,19,000
		Loans, Advances and Investment from National industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	173,56,86,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	165,65,84,000
Rupees	2509,96,17,000	Rupees	2509,96,17,000

*Includes Cash, Fixed Deposits, and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

+Includes Rs. 103,65,98,000 advances to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

---Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 5th day of June 1974.

V.V. CHARI, Dy. Governor.
[No. F.10(1)/74-BO.1]

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

बा० आ० 1616:—रिजर्व बैंक भारत इंडिया अधिनियम, 1934 के अनुमरण में जून 1974 की 7 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के लिये लेखा
इशु विभाग

देयताएँ	रुपये	रुपये	आस्तियाँ	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	10,50,99,000		सोने का सिक्का और शुल्कियन		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,53,05,000	
संचलन में नोट	6561,04,46,000		(ख) भारत के बाहर रखा		
			हुआ		
जारी किये गये कुल तोट		6571,55,45,000	विदेशी प्रतिशूलियाँ	166,73,97,000	
			जोड़		349,27,02,000
			रुपये का सिक्का		4,02,84,000
			भारत सरकार की रुपया		
			प्रतिशूलियाँ		6218,25,59,000
			देशी विनियम बिल और		
			दूसरे वाणिज्य-पत्र		
कुल देयताएँ	6571,55,45,000		कुल आस्तियाँ		6571,55,45,000

तारीख: 12 जून 1974

ग्राह० फ० हजारी, उप गवर्नर

7 जून 1974 को रिजर्व बैंक भारत इंडिया के बैंकिंग विभाग से कार्यकलाप का विवरण

देयताएँ	रुपये	आस्तियाँ	रुपये
चक्रता पूंजी	5,00,00,000	नोट	10,50,99,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	4,71,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	239,00,00,000	छोटा सिक्का	3,48,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि	85,00,00,000	खरीद और भुताय गये बिल	
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि	205,00,00,000	(क) वेशी	270,09,59,000
जमाराशियाँ—		(ख) विदेशी	
(क) सरकारी		(ग) सरकारी खजाना बिल	145,96,78,000
(1) केन्द्रीय सरकार	75,45,41,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	589,04,93,000
(2) राज्य सरकारें	9,06,32,000	निवेश**	238,51,13,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:-	
(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	573,66,18,000	(1) केन्द्रीय सरकार को	
(2) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	14,41,34,000	(2) राज्य सरकारों को (1)	147,07,96,000
(3) गैर अनुसूचित सहकारी बैंक	1,25,43,000	ऋण और अग्रिम:-	
(4) अन्य बैंक	67,08,000	(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को	413,99,56,000
		(2) राज्य सहकारी बैंकों को	180,53,56,000
		(3) दूसरों को	12,67,01,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएँ) निधि से	
		ऋण और अग्रिम निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :-	
		(1) राज्य सरकारों को	67,94,37,000
		(2) राज्य सहकारी बैंकों को	12,87,93,000
		(3) केन्द्रीय भूमिकांदक बैंकों को	
		(4) कृषि पुनर्वित्त निगम को	36,70,00,000

देयताएँ	रुपये	प्राप्तियां	रुपये
(ग) अन्य	361,04,41,000	(व) केन्द्रीय भूमिक्षेत्र बैंकों के उद्योगों में निवेश राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	11,31,64,000
देय बिल	121,99,49,000	गजय सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वीर्धकालीन क्रियाएँ) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	43,89,26,000
अन्य देयताएँ	679,33,39,000	(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	173,56,85,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा आई किये गये बांदों/ उद्योगों में निवेश अन्य प्राप्तियां
		अन्य प्राप्तियां	166,09,30,000
रुपये	2520,89,05,000	रुपये	2520,89,05,000

*नकदी, आवधिक जमा और अत्यकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्धकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वीर्धकालीन क्रियाएँ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्धकालीन क्रियाएँ) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओबज़ाफ़ शामिल हैं।

†रिजर्व बैंक इहां अधिनियम की धारा 17(1)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयावी बिलों पर अग्रिम दिये गये 123,79,73,000/- रुपए शामिल हैं।

‡राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्धकालीन क्रियाएँ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

तारीख : 12 जून, 1974

[सं० एफ 10/1/74 वीओ I]
प्रार० के हजारी, उप गवर्नर।

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1616.—An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 7th day of June 1974.

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	10,50,99,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	6561,04,46,000		(a) Held in India	182,53,05,000	
Total Notes issued	6571,55,45,000		(b) Held outside India	
			Foreign Securities	166,73,97,000	
			Total	349,27,02,000	
			Rupee Coin	4,02,84,000	
			Government of India Rupee Securities	6218,25,59,000	
			Internal Bills of Exchange and other Commercial paper		
Total Liabilities	6571,55,45,000		Total Assets		6571,55,45,000

R.K. HAZARI, Dy. Governor.

Dated the 12th day of June, 1974.

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India Banking Department as on the 7th June, 1974

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	10,50,99,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Rupee Coin	4,71,000
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	239,00,00,000	Small Coin	3,48,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	85,00,00,000	Bills Purchased and Discounted —	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	205,00,00,000	(a) Internal	270,09,59,000
Deposits :—		(b) External
(a) Government		(c) Government Treasury Bills	145,96,78,000
(i) Central Government	75,45,41,000	Balances Held Abroad*	589,04,93,000
(ii) State Governments	9,05,32,000	Investments**	238,51,13,000
(b) Banks		Loans and Advances to —	
(i) Scheduled Commercial Banks	573,66,18,000	(i) Central Government
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	14,410,34,000	(ii) State Governments@	147,07,96,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,25,43,000	Loans and Advances to —	
(iv) Other Banks	67,08,000	(i) Scheduled Commercial Banks +	413,99,56,000
(c) Others	361,04,41,000	(ii) State Co-operative Banks ++	180,53,56,000
Bills Payable	121,99,49,000	(iii) Others
Other Liabilities	679,33,39,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	12,67,01,000
Rupees	2520,89,05,000	(a) Loans and Advances to —	
		(i) State Governments	67,94,37,000
		(ii) State Co-operative Banks	12,87,92,000
		(iii) Central Land Mortgage Banks
		(iv) Agricultural Refinance Corporation	36,70,00,000
		(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	11,31,64,000
		Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	43,89,26,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	173,56,85,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank
		Other Assets	166,09,30,000
		Rupees	2520,89,05,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

+Includes Rs. 123,79,73,000 advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

++Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

Dated the 12th day of June 1974.

R.K. HAZARI, Dy. Governor,
No. F. 10/1/74 B.O.I.
C.W. Mirchandani, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संयुक्त-मुद्रा नियन्त्रक आयात नियोगी का कार्यालय

प्रावेश

वर्ष 15 मार्च, 1973

कांगड़ा 1617.—सर्वश्री जनरल स्पेयर्स हैट्टस्ट्रीज़, प्रा० नि० वर्मर्झ को
 (1) एम०एस०की कॉटिंग ब्लैक बार्स (सीमा किम्ब के) (2) अप्रैल-मार्च, 1973
 की रेड बुक के परिशिष्ट 14 के अनुसार नियंत्रण तथा प्रतिबंधित से भिन्न अनुमेय
 प्राकारों वाले बाल बेर्मरिंग, (3) अप्रैल-मार्च, 1973 की रेड बुक के
 परिशिष्ट 16/6(ए) तथा 16(6)(बी) में विशिष्टिकृत से भिन्न तोपहू
 रोलर बेर्मरिंग (4) संलग्न सूची के अनुसार का आयात करने के लिए
 6640/र० का एक आयात लाइसेंस संख्या: 2663813, विनांक 24-1-73
 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क
 तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति दोनों के लिए इस आधार पर
 आवेदन किया है कि मूल प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के
 पास पंजीकृत कराए बिना और उसका बिल्कुल उपयोग किए बिना
 ही खो गई है। अब अनुलिपि प्रतियों की जनरल लाइसेंस के पूरे
 मूल्य प्रति 6640 रुपये के लिए है। अपने दावे के समर्थन में
 आवेदक ने प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट, एस्लेनेड कोर्ट, वर्मर्झ के मम्मुद्ध
 विधिवत शपथ लेने शुरू एक शपथ पत्र दाखिल किया है और इसके
 साथ विलेनार्ने पुलिस स्टेशन द्वारा एक प्रमाण पत्र भी भेजा है
 जिसमें इसकी पुष्टि की गई है कि वह छोटा बैग जिसमें अन्य वस्तावेजों
 के साथ साथ लाइसेंस भी थे, आवेदक द्वारा हवाई फ्लूट पर खो गया
 था।

2. मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस संख्या पी/प०/2663813, विनांक 24-1-73
 की मूल सीमाशुल्क तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता हूँ कि आवेदक को अनुलिपि प्रति जारी की जाए।

3. लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति रद्द की जाती है।

[मिसिल संख्या : 236/13033/थी बी, 71/एम/ई पी एस सी-2-सी]

दी० दिसूजा, उप-मुद्रा नियंत्रक,
 हूँ ते संभुक्त भूद्य नियंत्रक,

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE JOINT CHIEF CONTROLLER OF
 IMPORTS & EXPORTS

ORDER

Bombay, the 15th March, 1973

S.O. 1617.—M/s. General Spares Industries, P. Ltd., Bombay have been granted Licence No. 2663813 of 24-1-73 for Rs. 6640/- for import of "(1) M.S. Free Cutting Black Bars (leaded quality). (2) Permissible sizes of Ball Bearings other than those banned and restricted as per App. 14 of AM. 73 R.B. (3) Tapered Roller Bearings other than those specified in app. 16/6(A) and 16(6)(B) of AM. 73 R.B. (4) As per list attached." They have applied for duplicate copy of both Customs and Exchange Control copy of the 36 GI/77—4

said licence on the ground that the original has been lost without having been registered with any Customs authority and without having been utilised at all. The duplicate copies now required is for the full value of the licence i.e. Rs. 6640/- In support of their claim. The applicants have filed an affidavit duly sworn in before the Presidency Magistrate, Esplanade Court, Bombay alongwith a Photostate of a certificate from the Vile-Parle Police Station confirming that a brief case containing licences alongwith other documents was lost at the Air-Port by the applicant.

2. I am satisfied that the original copy of Customs and Exchange Control purposes of the licence No. P/U/2663813 of Rs. 6640/- have been lost and direct that the duplicate copy of the licence be issued to the applicant.

3. The original of Customs and Exchange control copy of the licence is cancelled.

[F. No. 236/13033/OD. 71/L/EPSC. II. C.]

D. D'SOUZA, Dy. Chief Controller.
 for Joint Chief Controller

केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र

प्रावेश

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1973

कांगड़ा 1618.—सर्वश्री प्रोडक्ट्स आफ इंडिया, अणोका होटल, नई दिल्ली को 1. अनिमित हापी दाल/नन्हा गजदान तथा पूरा गजदान 2. ब्रक्सों के लिए पीला कवचे पीला के पेंच, कुडिया तथा स्टेपल, कर्ण टाप्स के के लिए क्रिप्स, 305 र० तक कार्यविलयों के लिए दुक तथा पेंचों के आयात के लिए 4880 र० का एक आयात लाइसेंस सं० पी/एल 2686284/सी विनांक 30-3-72 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने आयात व्यापार नियंत्रण तथा क्रियाविधि देव बुक 1973-74 की कंडिका 320 के अंतर्गत अपेक्षित एक शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि लाइसेंस सं० पी/एल 2686284/सी विनांक 30-3-72 मूल्य 4880 र० (सीमाशुल्क बार्यसंबंधी प्रति) को एतद्वारा रह किया जाना है।

मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति खो गई/प्रस्थानस्थ हो गई है।

अद्यतन यथासंघोषित आयात व्यापार नियंत्रण आवेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की धारा 9(मी) के अन्तर्गत मेरे लिए प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग कर लाइसेंस सं० पी०/एल/2686284 विनांक 30-3-72 मूल्य 4880 र० (सीमाशुल्क बार्यसंबंधी प्रति) को एतद्वारा रह किया जाना है।

अब आवेदक को आयात व्यापार नियंत्रण तथा क्रियाविधि हैडब्ल्यू, 1973-74 की कंडिका 320 की व्यवस्थाओं के अनुसार उक्त लाइसेंस को अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जा रही है।

[मि० मं० हैंडी/54/ज०पी० 71/एस सी 3/पी एल ए/3308]

ए०एन० भरुचा, उपमुद्रा नियंत्रक, और
 मंयुक्त मुद्रा नियंत्रक, आयात-नियांत्रित

(Central Licensing Area)

ORDER
 New Delhi, the 4th December, 1973

S.O. 1618.—M/s. Products of India, Ashoka Hotel, New Delhi were granted licence No. P/L/2686284/C dated 30-3-72 for Rs. 4880/- for the import of 1. Ivory un-manufactured/baby tusks & full tusks. 2. Brass Hinges, Brass

screws, hasps and staples for boxes, clips for ear tops, hooks and screws for ear-rings upto Rs. 305/- They have filed an affidavit as required under para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74 wherein they have stated that Custom purpose copy of licence No. P/L/2686284/ dated 30-3-72 for Rs. 4880/- has been lost/misplaced without having been utilised at all.

2. I am satisfied that the Customs Purposes copy of the said licence has been lost/misplaced.

3. In exercise of the powers conferred on me under subject clause 9(c) in the Import Trade Control Order 1955 dated 7-12-55 as amended upto date, the said Licence No. P/L/2686284 dated 30-3-72 for Rs. 4880/- (Custom Purpose copy) is hereby cancelled.

4. The applicant is now being issued duplicate Custom Purposes Copy of the said licence in accordance with the provisions of para. 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1973-74.

[File No. Handi/54/JS-71/SC-III/CLA/3308]

A. L. BHALLA, Dy. Chief Controller &
Jt. Chief Controller.

आवेदन

कलकत्ता, 20 अप्रैल, 1974

S.O. 1619

**सांख्या 1619—गर्वशी पोर्ट्स एण्ड स्पिल (इंडिया) प्रा० नि०, कलकत्ता को
प्रतीतमाचे 1974 की प्रवधि के लिए निम्नलिखित लाइसेंस आरी किए गए थे :—**

लाइसेंस सं० तथा विनांक	विवरण	मूल्य
1	2	3
1. लाइसेंस सं० 0241091/सी/एक्स क्रम सं० 82/4 30-11-73	दिनांक के अन्तर्गत स्वीकार करने के बाद आवेदन किए गए थे।	2007 रु० (दो एक्स/49/सी/37-38 मात्र)
2. लाइसेंस सं० 0241092/सी/एक्स क्रम सं० 83/4 30-11-73	दिनांक के अन्तर्गत शराब के लिए आवेदन किए गए थे।	1250 रु० (एक एक्स/49/सी/37-38 मात्र)
3. लाइसेंस सं० पी/ई/0241093/सी/एक्स क्रम सं० 84/4 30-11-73	दिनांक के अन्तर्गत शराब के लिए आवेदन किए गए थे।	1250 रु० (एक एक्स/49/सी/37-38 मात्र)

फर्म ने उपर्युक्त पूरे मूल्य के लिए उक्त लाइसेंसों की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों के लिए यह पुष्टि करने के बाद आवेदन किया है कि जब उन्होंने मात्र पत्र खोलने के लिए उक्त लाइसेंसों की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों सेन्ट्रल बैंक को प्रस्तुत की थीं तो वे बिल्कुल उपयोग किए जिना ही आग में नष्ट हो गई थीं। कुल मूल्य जिसके लिए मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों आरी की गई थी वह 2007 रु०, 1250 रु० एवं 1250 रु० या और कुल मूल्य जिसके

लिए मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों का उपयोग कर लिया गया था, वह शून्य था प्रबन्धनालिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों की आवधिकता उपर्युक्त उल्लिखित पूरे मूल्य के लिए है।

2. इस तर्फ के समर्थन में आवेदक ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत साध्याकात माध्यम कागज पर लाइसेंसों की प्रत्येक मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिए एक शापथ पत्र दाखिल दिये गए।

3. मैं संतुष्ट हूँ कि आवेदक को आयात लाइसेंस सं० पी/ई/0241091/सी, पी/ई/0241092/सी/एवं पी/ई/0241093/सी जिनका क्रमांक: मूल्य 2007 रु० 1250 रु० एवं 1250 रु० है की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों जारी की जानी चाहिए। उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों उपर्युक्त उल्लिखित पूरे मूल्य के लिए रह की जानी है।

संख्या ईप्राई/37324/8/एम74/बी

एस० क०० मन्त्री उप-मुख्य
मिंस्ट्रेट,
कृते मुख्य मिनिस्ट्रेट

ORDER

Calcutta, dated 20 April, 1974

**S.O. 1619—M/s. Peters & Smith (India) Pvt. Ltd., Calcutta
were issued Import Licences for the period April-March 1974
as under :—**

Licence No. & Date	Description	Value
1. L. No. 0241091/ C/XX/49/C/37-38 dt. 30-11-73.	Goods permissible under S. No. 82/IV.	Rs. 2007/- (Rupees two thousand & seven only)
2. L. No. 0241092/ C/XX/49/C/37-38 dt. 30-11-73.	Wines under S. No. 83/IV.	Rs. 1250/- (Rupees one thousand two hundred & fifty only).
3. L. No. P/E/0241093/C/XX/49/C/37-38 dt. 30-11-73.	Brandy/Whisky under S.No. 84/IV.	Rs. 1250/- (Rupees one thousand two hundred & fifty only)

The firm have applied for duplicate Exchange Control copies of the above licences for the full values mentioned above, since they have confirmed that the Exchange Control copies of the said licences, while submitted for opening letters of credit to the Central Bank, were destroyed by fire without having been fully utilised. The total amount for which the original Exchange Control copies were issued were for Rs. 2007/-, Rs. 1250/- and Rs. 1250/- and the total amount for which the original Exchange Control copies were utilised were nil. The duplicate Exchange Control copies now required are to cover the entire amount mentioned above.

2. In support of this contention the applicant has filed an affidavit on a stamped paper duly attested by the first Class Magistrate against each of the above Exchange Control copies of the licences.

3. I am satisfied that the Exchange Control copies of Import Licence Nos. P/E/0241091/C, P/E/0241092/C and P/E/0241093/C for the full value of Rs. 2007/-, Rs. 1250/- and Rs. 1250/- respectively should be issued to the applicant. The Exchange Control copies of the above import licences are cancelled for the entire amount mentioned above.

[No.FI/37324/8/AM74/B]

S. K. MANDAL,
Dy. Chief Controller
For Jt. Chief Controller

आवेदन

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1974

का. आ. 1620.—सर्वश्री इन्टरनेशनल आटो सप्लाइज 903, क्वीन्स रोड, दिल्ली को मिटटी हटाने वाली मशीन में उपयोग के लिए हैंड लैम्प्स के फालतू पुर्जों के रूप में 72 नग सील्ड बीम लैम्प्स के आवात के लिए 4484 रु. का एक बदलाई लाइसेंस सं. पी/आई/3031965 दिनांक 21-7-1972 स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति के लिए हस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति खां गई/अस्थानस्थ हो गई है। फर्म द्वारा आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी सीमा-शुल्क कार्यालय में पंजीकृत नहीं कराई गई थी और इस लिए उसका उपयोग नहीं किया गया है।

उक्त घोषणा के समर्थन में आवेदक ने यह बताते हुए विवरित साक्षात्कार एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति खां गई है या अस्थानस्थ हो गई है।

मैं संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति खां गई है और निवेश देता हूँ कि आवेदक को अनुलिपि सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क कार्यसंबंधी प्रति रद्द की जाती है।

[सं. आई पी टी./28/ए एम 71/क्यू एल/सी एल ए]

ओ. एन. आनन्द, उप-मुख्य नियंत्रक,

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 1974

S.O. 1620.—M/s. International Auto Supplies, 903 Queens Road, Delhi were granted a replacement licence No. P/I/3031965 dated 21-7-72 for Rs. 4484/- for import of 72 pieces Sealed Beam Lamps as parts of Head Lamps for use on Earthmoving Machinery. They have applied for the duplicate Customs purpose copy of the said licence on the ground that the original has been lost or misplaced. It is, further stated by the firm that the original Custom Purpose Copy of the licence was not registered with Customs House and hence has not been utilised.

In support of this declaration, the applicant has filed an affidavit duly attested stating that the original Customs Purpose Copy of the licence has been lost or misplaced.

I am satisfied that the original Customs Purpose copy of the said licence has been lost and direct that duplicate Custom Purpose copy should be issued to the applicant. The original Customs Purpose copy of the licence is cancelled.

[F. No. Rept./28/AM-71/QL/CL]

O. N. ANAND, Dy. Chief Controller

आवेदन

हैदराबाद, 11 अप्रैल, 1974

का. आ. 1621.—सर्वश्री जूप्ल एम्स सं. 5-4-14/2, निजामगाही रोड, हैदराबाद को सामान्यमुद्रा भोक्त्र में (1) टम्बलिंग मशीन, (2) पालिंग

एवं लैम्पिंग मशीन (3) कटिंग स्लिपिंग एवं स्लोइंग मशीन के आवात के लिए 12,000 रु. का एक आवात लाइसेंस सं. पी/एस/1736671/सी/एस/एस/44/डब्ल्यू/33-34 दिनांक 31-8-1972 स्वीकृत किया गया था।

उन्होंने लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस बिल्कुल उपयोग किए बिना ही खो गया है।

आपने तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं सन्तुष्ट हूँ कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है और निवेश देता हूँ कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति जारी की जानी चाहिए। लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

[संचया : जॉ. 15/एस एस आई/सी जी/ए एम 72/हैवर०]

पी० गोविन्द राजू, उप मुख्य नियंत्रक

ORDER

Hyderabad, the 11th April, 1974

S.O. 1621.—M/s. Jewel Gems, No. 5-4-14/2, Nizamshahi Road, Hyderabad were granted an import licence No. P/S/1736671/C/XX/44/W/33-34 dated 31-8-1972 for Rs. 12,000/- for the items (1) Tumbling Machines, (2) Polishing and Lapping Machines, (3) Cutting Slabbing and Slicing Machines for import from General Currency Area.

They have applied for a duplicate copy of the Exchange Control Purposes Copy of the Licence on the ground that the Original Licence has been lost without having been utilised at all.

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original Exchange Control Copy of the Licence is lost and direct that a duplicate Exchange Control Copy of licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy of the licence is hereby cancelled.

[File No. J. 15/SSI/C.G./A.M.-72/Hyd.]

P. GOVINDA RAJU, Dy. Chief Controller.

मुख्य नियंत्रक आवात निर्यात का कार्यालय नई दिल्ली

आवेदन

नई दिल्ली, 15 जून 1974

का० आ० 1622.—सर्वश्री मोद्दानी उद्योग, नारायण, राजस्थान को एक आवात लाइसेंस सं. पी/सी जी/2066478 दिनांक 17-12-73 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए हस आधार पर आवेदन किया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति खो गई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत कराएँ बिना और विलक्षुल भी उपयोग किये बिना खो गई है।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने नोटरी पछिलक, राजस्थान के मामने विधिवत शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनगार में संतुष्ट हूँ कि उक्त लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण

श्रति खो गई है। इसलिए यथासंशोधित आयात (नियन्त्रण) प्रादेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उपर्युक्त 9 (सी सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री मोड़ानी उद्योग नारायण राजस्थान को जारी किए गए लाइसेंस सं. ३० धी/सीजी/2066478 दिनांक 7-12-73 की मूल मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[मंद्या : 29(3)/73-74/सी जी-4]

जे० शंकर, उप-मुख्य नियन्त्रक

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF
IMPORTS & EXPORTS
ORDER

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1622.—M/s. Modani Udyog, Naraina, Rajasthan were granted an Import licence No. P/CG/2066478 dated 17-12-73. They have applied for the issue of a duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence on the grounds that the original Exchange Control Purposes copy has been lost. It is further stated that the original Exchange Purposes copy has been lost without having been registered with any Customs authority and has not been utilised at all.

2. In support of this contention, the applicant has filed an affidavit duly sworn in before Notary Public Rajasthan. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended, the said original Exchange Control Purposes copy of licence No. P/CG/2066478 dated 17-12-73 issued to M/s. Modani Udyog, Naraina is hereby cancelled.

3. A duplicate Exchange Control Purposes copy of the said licence is being issued separately.

[No. 29(3)/73-74/CG. IV]
J. SHANKAR, Dy. Chief Controller.

प्रावेश

नई दिल्ली, 17 जून, 1974

का० आ० 1623.—सर्वश्री इंगिलिश इलैक्ट्रिक आफ इंडिया लि० द्वारा उक्त लाइसेंस विल्डिंग 202-धी थीर नारिमन रोड, बम्बई को ६७,७१६ रु० का एक आयात लाइसेंस सं. ३० धी/प्रादृ/2087589/एस/प्राई ए दिनांक 22-४-७० स्वीकृत किया गया था। उक्ते उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यांक संबंधी प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क कार्यांक संबंधी प्रति के निकासी अभिकरण कार्यालय, बम्बई में आग में जलकर नष्ट हो गई है और उसका विलकुल उपयोग नहीं किया गया था। इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूँ कि लाइसेंस सं. ३० धी/प्रादृ/2087589/एस/प्राई ए/ दिनांक 22-४-७० की मूल सीमाशुल्क कार्यांक संबंधी प्रति फर्म के निकासी अभिकरण कार्यालय बम्बई में आग में जल कर नष्ट हो गई है और आवेदक को उसी की अनुलिपि सीमाशुल्क कार्यांक संबंधी प्रति जारी की जानी चाहिए।

प्रदत्त यथासंशोधित आयात (नियन्त्रण) आवश्यक सं. 17/55 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9 (सी सी) के प्रत्यंगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर अधोहस्ताकारी सर्वश्री इंगिलिश इलैक्ट्रिक कं० आफ इंडिया लि०,

बम्बई के नाम जारी किए गए आयात लाइसेंस सं. ३० धी/प्रादृ/2087589 दिनांक 22-४-७० की सीमाशुल्क कार्यांक संबंधी प्रति को रद्द करता है।

[संघा : 17-ई/रेलवे/69-70/जी एल एस]

चन्द्र गुप्त, उप-मुख्य नियन्त्रक

ORDER

New Delhi, the 17th June, 1974

S.O. 1623.—M/s. English Electric Co. of India Ltd. Vulcan Insurance Building, 202-B, Veer Nariman Road, Bombay were granted an Import Licence No. G/R/2087589/S/IA dated 22-4-70 for Rs. 67,716/- They have applied for issue of Duplicate Customs Copy of the same on the ground that the original customs copy of import licence has been destroyed in the fire at the firm's clearing Agents office at Bombay and the same was not registered at any Customs House and was not utilised at all. In support of their contention the applicant has filed an affidavit. I am satisfied that the original customs copy of import licence No. G/R/2087589/S/IA dated 22-4-70 has been destroyed in the fire at the firm's clearing agents office at Bombay and duplicate customs copy of the same should be issued to the applicant.

In exercise of the powers conferred on me by clause 9(cc) of the Import (Control) Order No. 17/55 dated 7-12-1955 as amended from time to time the undersigned cancels the customs copy of import licence No. G/R/2087589 dated 22-4-70 issued in favour of M/s. English Electric Co. of India Ltd., Bombay.

[No. 17-E/Rly/69-70/GLS/27]

CHANDRA GUPTA, Dy. Chief Controller

आँग्लो-रिंग विकास मंत्रालय

आवेश

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

का. आ. आर्ह. डी. आर. ए. ६/२/७४, केंद्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रौद्योगिकीय) नियम, 1952 के नियम ३ और ८ के साथ पीठत, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का ६५) की धारा ६ इच्छाप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री के. एस. गम्भीर के स्थान पर श्री धी. के. राय और श्री एस एन जूनारकर ध्वे २८ नवम्बर, 1974 तक की, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, अवधि के लिए अकाब्दीनिक स्थायन उद्योग विकास परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के आँग्लो-रिंग विकास मंत्रालय के आवेदन सं. का. आ. 4062/आर्ह. डी. आर. ए. ६/७/७२, तारीख 29 नवम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आवेश के पैरा १ में,—

(1) क्रम सं. ६ के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. रखी जाएगी, अर्थात् :—

“६. श्री धी. के. राय, नमक आयुक्त,

डाकघर बाक्स सं. 139, जयपुर १”

(2) क्रम सं. २९ के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“३०. श्री एस. एन. जूनारकर,

४९, देसाई काटेज, डा. एम. धी. रायपुर रोड, शिवाजी पार्क भूमध्य-४०००२८ १”

[सं. ८(५)/७४-सी. डी. एम.]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1624.—1 DRA/6/2/74.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 3 and 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints Shri B. K. Roy, Vice Shri K. L. Gambhir and Shri S. N. Junnarkar, as members of the Development Council for Inorganic Chemical Industries, for a period upto and inclusive of the 28th November, 1974, and makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 4062/IDRA/6/7/72 dated the 29th November, 1972, namely:—

In paragraph 1 of the said Order:—

(i) for serial No. 6, the following serial No. shall be substituted, namely:—

“6. Shri B. K. Roy, Salt Commissioner, P. O. B. No. 139, Jalpur”.

(ii) after serial No. 29, the following serial No. shall be inserted, namely:—

“30. Shri S. N. Junnarkar, 49, Desai Cottage, Dr. M.B. Raut Road, Shivaji Park, Bombay-400028.”

[No. 8(5)/74-CDN]

PREM NARAIN, Under Secy.

प्रौद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 15 मई, 1974

S.O. 1625—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के मनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या मी एम एल-3401 जिसके ब्यारे तीव्र अनुसूची में दिये गए हैं, फैक्टरी के स्थान बदल देने के कारण 1 अप्रैल 1974 से रद्द कर दिया गया है:

अनुसूची

क्रम	लाइसेंस संख्या तथा तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	भारतीय मानक की संख्या तथा पश्नाम
1	2	3		
1. सीएम/एल-3401 30-4-1973		मीमर्स चंद्राज कॉमिकल इन्डरप्राइज प्रा० लि०, 13-साऊथ टांगरा रोड, कलकत्ता-46 इतका रजिस्ट्रेशन कार्यालय पी-24 सी: आई.टी.०.रोड, स्कीम 52, कलकत्ता-14 में है।	जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने पक्के चेप पदार्थ;	IS : 4663-1968 जूता उद्योग के लिए रबड़ के बने पक्के चेप पदार्थ की विशिष्टि

[सी एम एल/55:3401 (सीओ)]
ए० पी० बनर्जी उप महानिवेशक

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY

(Indian Standards Institution)

New Delhi, the 15th May, 1974

S.O. 1625—In pursuance of Sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. CM/L-3401, particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1 April 1974, due to shifting of the factory.

Sl. Licence No. No. and date	Name and address of the licensee	Articles/Process covered by the licence can- celled		
1	2	3	4	5
CM/L-3401 30 4-1973	M/s. Chandras' Chemical Enterprises (Pvt.) Ltd. 13 South Tangra Road, Calcutta-46 having their Redg. office at P-24, C.I.T. Road, Scheme 52, Calcutta-14.	Permanent Rubber bassed adhesive for footwear Industry. Brand: (i) "DENDRITE" (ii) "PC-65" (iii) "PC-67"	IS: 4663-1968 Specification for Rubber- bassed Adhesive for foot- wear Industry.	

[No. CMD/55 : 3401 (CD)]

A.P. BANERJI, Deputy Director General.

1	2	3	4	5
	519	0	07	20
	520	0	06	36
	517/1	0	05	04
	516	0	12	00
	515	0	08	28
	514	0	10	80
	फार्ट देन	0	02	04
	544	0	13	44
	547/1	0	04	90
	546	0	09	24
सन्थाल	626	0	13	08
	625	0	11	28
	624	0	03	60
	635	0	06	36

[12018/7/74-एन एण्ड एल]

S.O. 1627.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Santhal-6 to Santhal-4, in Gujarat Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Pipeline from Santhal-6 to Santhal-4.

State : Gujarat Dist & Taluka : Mehsana

Village	Survey No.	Hec-tare	Arc	P. Are
i	2	3	4	5
Kasalpura	525	0	06	36
	518/2	0	03	48
	518/1	0	03	60
	519	0	07	20
	520	0	06	36
	517/1	0	05	04
	516	0	12	00
	515	0	08	28
	514	0	10	08
	Cart track	0	02	04
	544			

1	2	3	4	5
	547/1	0	04	80
	546	0	09	24
Santhal	. .	626	0	13
		625	0	11
		624	0	03
		635	0	06

[No. 12016/7/74-L&L/II]

का० श्रा० 1628.—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एम डी के धोलका-1 तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिश्वाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् पाबद्ध अनुमती में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अनियंत्रित वर्षा का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बासरें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप समझ प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड वरोदा-9 की इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि वह चालना है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की साफेत।

अनुसूची

डी एम डी के से धोलका-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात

जिला : कैरा

तालुका : मतर

ग्राम	मर्वेक्षण संख्या	हेक्टर	ए. प्रार. ए.	पी. प्रार. ए.
1	2	3	4	5
राधू	. .	996	0	03
		999	0	07
		1000	0	08
		998	0	11
		986 धैकी	0	10
		986 धैकी	0	06
		985/1 + 2 + 3	0	05
		955/2	0	07
		955/4	0	07
		949	0	11
		988/1	0	03
		840/1	0	10
		885	0	10

1	2	3	4	5
	884/2	0	10	80
	883/5	0	26	60
	883/6	0	01	00
	856/5	0	07	92
	856/6	0	02	04
	855/1	0	06	48
	851/1	0	05	18
	851/1	0	03	00

[12016/7/74-एल एल I]

S.O. 1628.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from DS-DK to Dholka-I in Gujarat State Pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE'

To Laying pipeline from DS-DK to Dholka-1.

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are.	P. Are.
1	2	3	4	5
Radhu	. . .	996	0	03 60
		999	0	07 80
		1000	0	38 40
		998	0	11 76
	986 Paiki	0	10	44
	986 Paiki	0	06	60
	983/1+2+3	0	05	64
	985/1/2/3			
	955/2	0	07	64
	955/4	0	07	00
	949	0	11	40
	888/1	0	03	36
	840/1	0	10	08
	885	0	10	80
	884/2	0	10	80
	883/5	0	26	60
	883/6	0	01	00
	856/5	0	07	92
	856/6	0	02	04
	855/1	0	06	48
	851/1	0	05	16
	851/4	0	03	00

[No. 12016/7/74-L & L/I]

गुरुदिवाल

S.O. 1629.—भारत सरकार के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उपक्रमण (II) दिनांक 14 प्रकृत्यावर, 1972 पृष्ठ सं 4180 से 4192 तक प्रकाशित भारत सरकार के राजपत्र में का०आ०सं० 2804 के अधीन पैट्रोलियम और स्थायी मंकाग्य (पैट्रोलियम विभाग) भारत सरकार की प्रधिसूचना सं० 11(2)/72-लेवर और ऐजेंस में :

ग्राम : सेज	तालुका : कलोल	जिला : महसाना
मह. पक्षे		
सर्वेक्षण सं०	हैक्टर	ए. आर.ई
1083/3	0	08
998/2/ए	0	04
998/2/बी	0	02
998/2/सी	0	06
1083/1/ए	0	03
1083/1/बी	0	03
1081/2	0	04
1085/1/ए	0	01
काटौ ट्रैक	0	01
1084/1/सी	0	03
1084/1/बी	0	08
998/1/बी/सी	0	00
सर्वेक्षण सं०	हैक्टर	ए. आर.ई
1083/3	0	06
998/2/ए	0	02
998/2/बी	0	02
998/2/सी	0	11
1083/1/ए	0	02
1083/2/बी	0	02
1081/2	0	05
1085/1/ए	0	05
काटौ ट्रैक	0	04
1084/1/सी	0	00
1084/1/बी	0	08
998/1/बी/सी	0	00

ग्राम : सरीसा	तालुका : कालोल	जिला : महसना							
पहें		के स्थान पर							
सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर ई	पी. ए. आर ई	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर ई	पी. ए. आर ई		
89		0	04	60	89		0	94	60
ग्राम : धोएन मोसी	तालुका : कलोल	जिला : महसना							
पहें		के स्थान पर							
सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर ई	पी. ए. आर ई	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर ई	पी. ए. आर ई		
741/2/वी	0	00	25	741/2/ई	0	00	25		
कार्ट ट्रैक	0	01	20	कार्ट ट्रैक	0	01	00		
ग्राम : करोली	तालुका : कालोल	जिला : महसना							
पहें		के स्थान पर							
सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर ई	पी. ए. आर ई	सर्वेक्षण सं०	हेक्टर	ए. आर ई	पी. ए. आर ई		
कार्ट ट्रैक	0	01	60	कार्ट ट्रैक	0	01	00		

[सं० 11(2)/72-एन एड एन भाग-1]

बी० शार० भला, प्रबर मनित्र

ERRATUM

S.O. 1629.—In the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of Petroleum) No. 11(2)/72-Lab & Legis, dated 23rd September, 1972, under S.O. No. 2804 in the Gazette of Government of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated 14th October, 1972, page Nos. 4180 to 4192 :

Village : Sajj	Taluka : Kalol	Dist : Mehsana					
Survey No.	Hectare	Arc	P. Arc	Survey No.	Hectare	Arc	P. Arc
1083/3	0	08	30	1083/3	0	06	80
998/2/A	0	04	00	998/2/A	0	02	20
998/2/B	0	02	48	998/2/B	0	02	00
998/2/C	0	06	15	998/2/C	0	11	40
1083/1/A	0	03	15	1083/1/A	0	02	80
1083/1/B	0	03	00	1083/1/B	0	02	60
1081/2	0	04	95	1081/2	0	05	60
1085/1/A	0	01	00	1085/1/A	0	05	70
Cart track	0	01	68	Cart track	0	04	30
1084/1/C	0	03	42	1084/1/P	0	00	60
1084/1/B	0	08	60	1084/1/P	0	08	60
998/1/B/P	0	00	50	998/1/D/P	0	00	50

Village : Serja

READ

Taluka : Kalol

Dist : Mehsana

FOR

Survey No.

Hectare Are P. Are

89

0 04 60

Survey No.

Hectare Are P. Are

0 94 60

Village : Bhoyan Moti

Taluka : Kolol

Dist : Mehsana

READ

FOR

Survey No.

Hectare Are P. Are

741/2/B

0 00 25

0 00 25

Cart track

0 01 20

0 01 00

Village : Karol

Taluka : Kalol

Dist : Mehsana

READ

FOR

Survey No.

Hectare Are P. Are

Cart track

0 01 60

0 01 00

[No. 11(2)/72-L & L. Vol. I]

B.R. BHALLA, Under Secy.

स्वास्थ्य तथा परीक्षार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई विली, 5 जून, 1974

का० द्वा० 1630.—यतः भारत सरकारके भूत्पूर्व स्वास्थ्य मंत्रालयकी 23 जूलाई, 1962 की प्रधिसूचना सं० 16-44/61-च० 1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद प्रधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिए एम्स्टरडम विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता "आर्ट्स एक्जामिन" अर्थात् डिप्लोमा मैडिकल फैकल्टी माध्य चिकित्सा अर्हता होगी, और यस डॉ० (कुमारी) एच० क्रेंगेर को जिसके पास उक्त अर्हता है; गिरण तथा धर्मर्थ कार्य के प्रयोजन के लिए फिस्हाल जलना मिशन प्रस्पताल, पुना किशियन मैडिकल एसोसिएशन जलना, जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के साथ सम्बद्ध है।

प्रतः अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 14 की उप धारा (1) के परन्तुकृ के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा —

(1) इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की लिंग से दो वर्ष की अवधि के लिए;

अधिकारी

(2) उस अधिकारी जब तक डॉ० (कुमारी) एच० क्रेंगेर जलना मिशन प्रस्पताल, पुना किशियन मैडिकल एसोसिएशन, जलना, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अधिक विनियिष्ट करती है, जिसमें पूर्णत डॉ० मैडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे।

[प० सं० ओ० 11016/3/74-एम पी टी]

कुमारी सती बालकृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 5th June, 1974

S.O. 1630.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-44/61-MI, dated the 23rd July, 1962, the Central Government has directed that the Medical qualification "ARTSEXAMEN" (i.e. Diploma Medical Faculty) granted by the University of Amsterdam shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. (Miss) H. Kreuger who possesses the said qualification is for the time-being attached to the Jalna Mission Hospital of the Poona Christian Medical Association, Jalna Distt. Aurangabad (Maharashtra State) for the purposes of teaching and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the provision to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies—

- a period of two years with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, or
- the period during which Dr. (Miss) H. Krenger is attached to the said Jalna Mission Hospital of the Poona Christian Medical Association, Jalna—Distt. Aurangabad (Maharashtra State) whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shall be limited.

[No. V. 11016/3/74-MPT]

MISS SATHI BALAKRISHNA, Under Secy.

रेल मन्त्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 जून, 1974

का० प्रा० 1631.--रेल यात्रियों पर सीमाकर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 4 द्वारा प्रवत्त यात्रियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा निरेण देती है कि इसके साथ संकरन नमूनी में उल्लिखित अधिसूचित स्थान से/सक रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले किसी यात्री पर ऐसे अधिसूचित स्थान से उनतीस किलोमीटर की परिधि के भीतर स्थित किसी रेलवे स्टेशन तक/स, सीमाकर नहीं लगाया जायेगा।

2. यह अधिसूचना 1 जूनाई, 1974 से प्रभृत होगी।

अनुमूली

करवी

[सं० एफ(एस) 1-69/टी एस-19/2-1]

Ministry of Railways

(Railway Board)

New Delhi, the 27th June, 1974

S.O.1631 In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956), the Central Government hereby directs that no terminal tax shall be levied on any passenger travelling by railway from or to the notified place mentioned in the Schedule annexed hereto, to or from any railway station situated within a radius of twenty-nine kilometres from such notified place.

2. This notification shall have effect on and from the 1st July, 1974.

SCHEDULE
Karwi

[No. F (X)I-69/TX-19/2-II]

का० प्रा० 1632:--रेल यात्रियों पर सीमाकर अधिनियम, 1956 (1956 का 69) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त यात्रियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड) की 17 जून, 1971 की अधिसूचना संख्या एफ(एस) 1-71/टी एस-19/I-IV का अधिनियम करते हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा--

(क) इस अधिसूचना के साथ संकरन अनुमूली के कालम (2) में उल्लिखित दरें निश्चित करनी हैं। इन्हीं दरों के अनुसार उक्त अनुमूली के कालम

(1) में विनियोग अधिसूचित स्थान तक रेलवे द्वारा ले जाये जाने वाले सभी यात्रियों के प्रत्येक रेलवे टिकट पर सीमाकर लगाया जायेगा;

(ब) यह निरेण देती है कि उपर्युक्त सीमाकर 1 जूनाई, 1974 से उद्घाहय होंगी।

2. यह अधिसूचना 1 जूनाई, 1974 से प्रभृत होगी।

अनुमूली

(1)

(2)

अधिसूचित स्थान का नाम

प्रति इकहरे टिकट पर सीमाकर की दरें

दर्जा	वयस्क	3 से 12 वर्ष तक के बच्चे	
पोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए (30 कि० मी० से 242 कि० मी० तक)	लंबी दूरी के यात्रियों के लिए (242 कि० मी० से आगे)	पोड़ी दूरी के यात्रियों के लिए (30 कि० मी० से 242 कि० मी० तक)	लंबी दूरी के यात्रियों के लिए (242 कि० मी० से आगे)
रेलवे दर्जा	रु० ५०	रु० ७५	रु० २५
पहला दर्जा	०. 30	०. 45	०. 15
वानानुकूल कुमर्मेयान दर्जा	०. 30	०. 45	०. 15
दूसरा दर्जा	०. 15	०. 20	०. 05

ज्ञान्या:—वापसी टिकट पर सीमाकर अनुमूली में निर्धारित दर से दुगुना होगा।

[सं० एफ(एस) I-69/टी एस-19/2-II]

अनुमूल लाल गुप्ता, सचिव

S.O. 1632.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Terminal Tax on Railway Passengers Act, 1956 (69 of 1956) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board No. F (X)-I-71/13/1-IV, dated the 17th June, 1971, the Central Government hereby—

(a) fixes the rates mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the rates at which terminal tax shall be levied in respect of every railway ticket on all passengers carried by railway from or to the notified place specified in column (1) of the said Schedule; and

(b) directs that the aforesaid terminal tax shall be leviable with effect from the 1st July, 1974.

2. This notification shall come into force on the 1st July, 1974.

SCHEDULE

Name of notified place	Rates of terminal tax per single ticket	Adults		Children between 3 & 12 years of age	
		For short distance passengers (30 kms—242 kms.)	For long distance passengers (beyond 242 kms.)	For short distance passengers (30 kms—242 kms.)	For long distance passengers (beyond 242 kms.)
Karwi	Class of accommodation				
	Air-conditioned class	Rs. P. 0.50	Rs. P. 0.75	Rs. P. 0.25	Rs. P. 0.40
	I Class	0.30	0.45	0.15	0.25
	Air-conditioned Chair Car Class	0.30	0.45	0.15	0.25
	II Class	0.15	0.20	0.05	0.10

Explanation : The terminal tax on a return ticket shall be double the rates fixed herein.

[No. F.(X) I -69/TX-19/2-II]

A.L. GUPTA, Secy.

श्रम मंत्रालय

धर्म और रोजगार विभाग

प्राक्षेप

नई दिल्ली, 8 मई, 1973

का० आ० 1633.—यह: उपाध्यक्ष अनन्तसूची में विनिविष्ट श्रौद्धोगिक विवाद केन्द्रीय सरकार श्रौद्धोगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित है;

और यह: विवाद से संबंधित कर्मकारों ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया है कि मामला दिल्ली से चण्डीगढ़ को अन्तरित कर दिया जाए;

और यह: केन्द्रीय सरकार इस मामले को युक्तियुक्त समझती है;

अतः, श्रव श्रौद्धोगिक विवाद प्रधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क तथा धारा 33ख की उपधारा (1) धारा प्रदत्त अक्षियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एक श्रौद्धोगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० मोदी होंगे, जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा, और केन्द्रीय सरकार श्रौद्धोगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित उक्त बाद से संबंधित कार्यवाही को प्रतिसंहृत करती है तथा उसे श्री एच० आर० मोदी, पीठासीन अधिकारी के अधीन गठित श्रौद्धोगिक अधिकरण को अन्तरित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों से उसी प्रक्रम में कार्यवाही करेगा जिस पर वे उसे अन्तरित की गई हैं और विधि के अनुमार उसका निपटारा करेंगा।

प्राक्षेप

क्रम संख्या आदेश संख्या और तारीख

विवाद के पक्षकार

1. एस० 12012/173/72/आई० आर० iii मंडल बैंक आफ इण्डिया तारीख 27 अप्रैल, 1973। तथा उसके कर्मकार।

[संख्या एस० 12012/173/72/आई० आर० 3] करनेम सिंह, अवर मर्जिव

MINISTRY OF LABOUR

Department of Labour and Employment

(New Delhi, the 8th May, 1973)

S.O. 1633.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Central Government Industrial Tribunal, Delhi;

And whereas the workmen concerned in the dispute have requested the Central Government for the transfer of the case from Delhi to Chandigarh;

And whereas the Central Government considers the request as reasonable;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and sub-section (1) of section 33 B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri H.R. Sodhi as the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh, withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before the Central Government Industrial Tribunal, Delhi and transfers the same to the Industrial Tribunal constituted with Shri H.R. Sodhi as Presiding Officer thereof and directs that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which they are transferred to it dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. Order No. and date No.	Parties to the dispute
-------------------------------	------------------------

1. L. 12012/173/72/LRIII Central Bank of India and their
dated the 27th April, 1973.
workmen.

[No. L-12012/173/72/LRIII]
KARNAIL SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जून, 1974

का० आ० 1634 पी० ईस्य० ए० खान/नियम/ए० एस०—मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 में और संशोधन करने के लिए कलिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो संशोधन केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 21 के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए करना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी अधिकारी के जानकारी के लिए एवं इन्हाँग प्रकाशित किया जाता है जिनका उनमें प्रभावी होना समावित है, तथा एन्ड्राधारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास की अवधि के पश्चात् तिनांक किया जाएगा।

इन प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकार के पूर्व जो भी अधिकार या सुधार किसी अधिकार से उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त होगे, उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेंगी। ऐसे आधेष्ट और सुधार भारत सरकार के मंत्रिक, अम मन्त्रालय, अम शक्ति भवन, रकी मार्ग, नई दिल्ली-1 को संशोधन किए जा सकते हैं।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1974 है।

2. मजदूरी संदाय (खान) नियम, 1956 के नियम 1 के उपनियम (3) में “जम्मू और काश्मीर राज्य के मिश्राय” शब्दों का प्राप्त किया जाएगा।

[संख्या एस 65012/2/71/अप्राईड्यार० 111]

जे० आर० वागची, भवर मचिय

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1634.—PWA/Mines/Rules/Am.—The following draft of certain rules further to amend the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 26, read with section 24, of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is hereby published, as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objections or suggestions which may be received from any persons with respect to the said draft before the period so specified, will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions may be addressed to the secretary to the Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-1.

DRAFT RULES

- These rules may be called the Payment of Wages (Mines) Amendment Rules, 1974.
- In the Payment of Wages (Mines) Rules, 1956, in rule 1, in sub-rule (3) the words “except the State of Jammu and Kashmir” shall be omitted.

[No. S. 65012/2/71/I RII]

J. R. BAGCHI, Under Secy.

प्रावेश

नई दिल्ली, 18 जून, 1974

का० आ० 1635—यह: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायद्वय प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के बारे में मैसर्स इशारिम सूचा मर्विसेज कम्पनी, मुम्बई के प्रबंधतात्व में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कमेकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और यह: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः यह: भव, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण मंडपा 2, मुम्बई को न्यायनिर्णय के लिए निर्देशित करती है।

प्रनुसूची

“क्या नेशनल डॉक एण्ड जनरल वर्कर्स यूनियन, 35, सागर विहार, 89, पी० डिमेलो रोड, मुम्बई-9 द्वारा मैमसे इशारिम सूचा मर्विसेज, कम्पनी के विश्व निम्नलिखित मांग न्यायोचित हैं और यदि हां, तो कर्म कार किस अनुतोष के हक्कदार है:—

पहरेदारों (वाचमैन) को 1969-70 और 1970-71 के में बीच वर्षों में से प्रत्येक के लिए कुल मजदूरी का 20-प्रतिशत बोनस दिया जाना चाहिए?”?

[संख्या एस 31011/4/72-पी०एण्ड झे)

वी० संकरलिंगम, अवयर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th June, 1974

S.O. 1635.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Ebrahim Moosa Services, Company, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDUI E

“Whether the following demand made by the National Dock and General Workers' Union, 35, Sagar Vihari, 89, P. D'Mello Road, . Bombay-9, against Messrs Ebrahim Moosa Services Company, 65, P. D'Mello Road, Bombay-9, is justified and if so, to what relief are the workmen entitled:—

The watchmen should be paid bonus at 20 per cent of the total wages for each of the accounting years 1969-70, and 1970-71”?

[No. L-31011/4/72-P&D]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1974

कांग्रा० 1636.--यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाध्यक्ष अनुसूची में विनियोजित विषयों के बारे में मैसर्स जी० सामोन्टा, अबरक खान मालिक, डाकघर कोडर्मा, जिला हजारीबाग के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के छठे (अ) द्वारा प्रदत्त विभिन्नों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स जी० सामोन्टा, अबरक खान मालिक, डाकघर कोडर्मा, जिला हजारीबाग द्वारा नियोजित विभिन्नों की, वर्ष 1971 में आरंभ होने वाले लेखा वर्ष के लिए उनके द्वारा अर्जित मजदूरियों के 20 प्रतिशत की दर से बोनस के भुगतान की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार-उस वर्ष के लिए बोनस की किस राशि के हकदार हैं?

[सं० एल० 28011/6/73-एल० आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1974

S.O. 1636.--Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs G. Samonta, Mica Mine Owners, Post Office Koderma, District Hazaribagh, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And where the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed by Messrs G. Samonta, Mica Mine Owners, Post Office Koderma, District Hazaribagh for payment of bonus at the rate of 20 per cent of the wages earned by them for the accounting year commencing in the year 1971 is justified. If not, to what quantum of bonus are the workmen entitled for that year?

[No. L-28011/6/73-LRIV]

आदेश

27 मई, 1974

कांग्रा० 1637.--यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्यक्ष अनुसूची में विनियोजित विषयों के बारे में गानपात्रा सेंड स्टोन माइन, डाकघर दाबी, जिला बून्ही के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के छठे (अ) द्वारा प्रदत्त विभिन्नों का प्रयोग करते हुए, उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री कमल हमन, मूरज पोल, कोटा (राजस्थान) की गानपात्रा सेंड स्टोन माइन, डाकघर दाबी (जिला बून्ही) में नियोजित कर्मकार विभिन्नों द्वारा प्रदत्त विभिन्नों की मजदूरी के सवेतन हकदार हैं?

[सं० एल-29011(21)/74-एल० आर०-4]

ORDER

New Delhi, the 27th May, 1974

S.O. 1637.--Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Patpada Sand Stone Mine, Post Dabi, District Bundi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And where the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in the Patpada Sand Stone Mine Post Dabi (District Bundi) of Shri Kamrul Hassan, Surajpole, Kota (Rajasthan) are entitled for grant of any paid national and festival holidays?

[No. L-29011(21)/74-LR. IV]

आदेश

कांग्रा० 1638-यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाध्यक्ष अनुसूची में विनियोजित विषयों के बारे में मुधपुरा सेंड स्टोन माइन डाकघर मुधपुरा, जिला बून्ही (राजस्थान) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना चाहनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के छठे (अ) द्वारा प्रदत्त विभिन्नों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्री बाबूनाथ जी यादव की मुधपुरा सेंड स्टोन माइन, डाकघर मुधपुरा, जिला बून्ही (राजस्थान) में नियोजित कर्मकार की 1965-66 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 लेखा वर्षों की मजदूरियों की 20% की दर से बोनस मंदाय की मांग न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए बोनस की किस राशि के हकदार हैं?

[संख्या एल-29011(10)/74-एल० आर०-4]

पी० पी० कान्तन, अवर सचिव

ORDER

S.O. 1638.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Budhpura Sand Stone Mine, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule here annexed;

And where the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Govt. Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mine of Shri Babulalji Yadav, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) for payment of bonus @ 20 per cent of wages for the Accounting years 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 is justified? If not to what quantum of Bonus are the workmen entitled for each of these years?

(No. L-29011(10)/74-LR. IV)

P. P. KANTHAN, Under Secy.

New Delhi, the 15th June, 1974

S.O. 1639.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th June, 1974.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : DELHI.

REFERENCE I.D. Nos. 5 & 6 of 1973

BETWEEN

The employers in relation to the Bank of Baroda, Parliament Street, New Delhi,

AND

Their workmen.

Dr. Anand Parkash with Sh. Madho Kapur—for the management.

Shri M. K. Ramamurthi with Shri Romesh Pathak—for the workmen.

AWARD

As common questions of facts and law arise in both these references and both the workmen were employees of a single employer, they are being disposed of by a single award.

2. By Order No. L. 12012/170/72/LRIII dated 6th March 1973 the Central Government referred the following industrial dispute existing between the aforesaid parties for adjudication to the Tribunal presided over by my learned predecessor Shri R. K. Baweja:—

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating service of Shri Dharmanand watchman-cum-peon was justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The same Government by another Order No. L. 12012/169/72/LRIII dated 13th March, 1973 referred another industrial dispute existing between the said employer and Shri Kedar Lal, workman for adjudication to the Tribunal presided over by my learned predecessor Shri R. K. Baweja with the following term of reference:—

"Whether the action of the management of Bank of Baroda in terminating the services of Shri Kedar Lal, watchman-cum-peon was justified? If not, to what relief is he entitled?"

4. The former reference pertains to the justification or otherwise of the order of termination of services of Shri Dharmanand, watchman-cum-peon. In I.D. No. 6 of 1973, the matter which was referred for adjudication is if the management was justified in terminating the services of another watchman-cum-peon Shri Kedar Lal. In the written statement filed by the management, the preliminary objections raised were that as no demand was made on the management, there was no industrial dispute which could be validly referred for adjudication and that there was no proper espousal of the dispute. On these pleadings of the parties, the following three preliminary issues were framed in both these references:—

- (1) Whether a demand was made on the management in respect of the subject-matter of the dispute? If not, its effect?
- (2) Whether the dispute is not an industrial dispute?
- (3) Whether there was espousal of the dispute? If not, its effect?

All these issues were decided by my learned predecessor Shri R. K. Baweja vide his order dated the 7th of September 1973 and the cases were fixed for evidence on merits. Both these references proceeded before me as successor to Shri R. K. Baweja.

5. The allegations of the workmen as contained in the statement of claims filed by the Secretary of the Bank of Baroda Employees Union on their behalf are that Sarvashri Dharmanand and Kedar Lal were employed against permanent vacancies by the Bank in July and June 1970 respectively as watchmen-cum-peons-cum-liftmen but were not paid their salaries at the rates prescribed in the Bipartite settlement and awards which governed the service conditions of the employees working in the banking industry. According to the union, the management had been adopting unfair labour practice in the matter of employment. They approached the management to confirm them in service and also to pay them their dues as per the Bipartite settlement and the service conditions applicable to all other workmen working in the Bank but instead of accepting their justified and reasonable demand, they were told by the Security-cum-Administrative Officer of the Bank that the management had decided to terminate their services with effect from the 31st of July, 1972 and that they should sign a receipt in token of their having received money in full and final settlement of their dues. When they wanted to know the reasons, they were told that their services were no longer required by the management as they had allegedly put in their claim for being treated as permanent employees of the Bank. It was, therefore, prayed that as the action of the management in discharging them from service was in utter violation of the directions contained in the Bipartite settlement and awards in force at the relevant time, besides being illegal and unjustified, the management be directed to reinstate them in service with full back wages and continuity of service.

6. In the written statements filed by the management the pleas of the workmen as contained in the statement of claims were controverted and it was stated that as they were engaged on purely casual and temporary basis in connection with the construction of Parliament Street Building of the Bank their services came to an end automatically on the completion of the said construction work. According to the management, they were not entitled to salaries and other benefits admissible to the permanent employees of the Bank who were issued regular appointment letters. It is further stated that when the workmen came to know that their services were going to be terminated as temporary employees, they as an after-thought, started putting in claims for being treated as regular employees of the Bank. After

the completion of the main construction work, the concerned workmen and others were given certain casual jobs. It is also averred that, though under the law no retrenchment compensation was required to be paid to them, the management tendered one month's salary and compensation by way of precautionary measure but they refused to accept the same. It was, therefore, prayed that their claim be rejected as no case had been made out for any relief far less the relief of reinstatement or full back wages or continuity of service.

7. The first point that falls for determination is whether the two concerned workmen were employed on construction work or whether they were part of the regular staff of the Bank and were working against permanent vacancies. Now I shall proceed to consider on the basis of the oral and documentary evidence placed on record as to which version is correct.

8. In support of its case, the management produced two witnesses and relied on certain documents which are on the files. Shri Ishwar Dass Dogra MW1 is the Security-cum-Administrative Officer of the Bank at Karol Bagh, New Delhi. He deposed that the construction work of the Bank Building in Parliament Street started in 1965. One Kothai was the Architect who engaged 28 persons including the two concerned workmen. The wages to those workmen were paid on the basis of the certificate given by the Architect and they were engaged on different jobs from time to time as per the need. To workers like masons, carpenters, electricians, chowkidars and peons etc., no appointment letters were issued as they were not regular employees. According to Shri Dogra even for a temporary bank employee, the management issued a letter of appointment. The construction workers were not given any leave excepting the weekly paid holidays. The bank employees were governed by different awards and the Bipartite settlement while the casual workers were not governed by those settlements and awards. He further stated that when the main construction work of the building had been completed in June/July, 1972 their services were dispensed with alongwith twelve other construction workers. Before the start of the construction work, no casual or temporary employee was ever employed. Shri Dogra produced the attendance registers of temporary and regular employees who were recruited during the relevant time. In these registers names of the concerned workmen do not find a place. Shri Dogra, then, called the two concerned workmen alongwith others on the 31st of July, 1972 and offered them one month's salary, one month's notice pay and other compensation. Excepting the two concerned workmen, all others received their dues and went away. Thereupon, Shri Dogra gave a note on the chits Exts. W/10 and W/11 to the effect that the two workmen had not accepted their dues. The dues were later sent by money orders. Copies of the receipts which Shri Dogra obtained from the other employees were Exts. M/12 to M/21. Exts. M/22 to M/43 are copies of the appointment letters issued to the temporary employees of the bank who were appointed during the relevant period. He went on to say that the salaries of casual employees were debited to C.D.Misc. Property Revenue Account and they were paid at the rate of Rs. 200/- per month whether the month was of 28 days, 30 days or 31 days. On the 31st of July, 1972 this witness told them that their services were no longer required as the main construction work of the building had been completed. Shri Dogra denied that their services were terminated as they had made representations regarding terms and conditions of their service. The staff of the Bank shifted to the new building in April, 1971 as the major portion of the work had been completed. From the cross-examination of this witness it was not shown that what he had stated in his examination-in-chief was wrong.

9. The next witness produced by the Bank in support of its case is Shri R. RaghuRaman MW2. In 1970-71, he was in the Regional Office of the Bank at New Delhi, and was looking-after the work connected with the construction of the building in Parliament Street. He said prior to the construction of the building, no casual employees were employed. The two concerned workmen were working on the construction site and were given different jobs like watch and ward of the building material and sometimes they also did the lift-operating work but it was not their regular duty. Certain casual staff was retained after 1971 when the main construction work had been completed. In cross-examination he stated that their service record was maintained by the

construction site office. The casual workers were employed by the site engineer on the recommendations of the Architect and were paid by the Bank. The statement of this witness remained unshaken in cross-examination.

10. The evidence on the side of the workmen consists of three witnesses. The first of them Shri Kedar Lal WW1 deposed that he worked as lift-operator-cum-peon for about eleven months. There was a permanent lift operator during that period. With him, twelve other workers were there at the Bank site. He looked after the building material and furniture. The office of the Architect and the bank engineer was there and when he joined, the first floor had been constructed. The site engineer used to certify the number of days for which he worked in a month. The second witness is Shri Dharma Nand WW2. His statement is similar to that of Shri Kedar Lal. In cross-examination, he explained that before joining the management, he worked in the postal department on daily wages as porter. He was assigned the work of chowkidar-cum-peon when he started working at the building site. He was a watchman for the office and building manager and worked by rotation during day and night. On Sundays and holidays he worked on lift and on other days he worked as peon. The others are permanent as they are getting their full wages and uniforms. He denied that any retrenchment compensation was paid to him. The third witness Shri R. L. Virmani WW3 is the secretary of the union. He deposed that the construction of the building started in 1965 and he used to go there in 1971-72. He saw the two concerned workmen working there. For different work different chowkidars were there.

11. From the above evidence it is quite obvious that the management treated the concerned workmen as Casual employees. The fact that the workmen were employed on construction work and were doing work in its connection is more or less admitted by the workmen themselves. Shri Kedar Lal contacted the Bank Engineer for appointment and with him twelve other workers were at the site of the bank building, who looked after the building material. This shows that they were employed in connection with the construction work. Shri Dharmanand has also admitted that he was assigned the work of looking-after the building material. Even the secretary of the union has stated that he saw the two workmen working on the site of construction of the building. It is also clear from the evidence of the management's witnesses that their names were not mentioned in the attendance registers or regular employees and they were not given other facilities admissible to regular employees of the Bank. This shows that they were not being treated as bank employees. The fact that the concerned workmen were not paid wages under the Bipartite settlement, is not disputed even by the union. It also, goes to show that these workmen were not treated as regular employees of the bank. Then there were no letters of appointment in respect of them, though, it is the case of the bank that it issued such letters in respect of even temporary employees. Shri Dharma Nand stated that he was a chowkidar-cum-peon when he started working at the site. On Sundays and holidays, he worked on the lift. Exts. M/46 to M/50 are the statements of salary paid to such workers. All these documents show that they were paid at the site by the site engineer on the recommendations of the Architect. Exts. M/1 to M/9 are the attendance registers of permanent employees and they were produced at the instance of the Union. In these registers the names of the construction workers do not find a place. There is no evidence that the workmen were employed on permanent basis or against permanent vacancies. On the contrary the workmen made representations that they should be made permanent. But they never stated that they were employed on permanent basis against permanent vacancy. Dr. Anand Parkash took me through the entire evidence of the workmen and pointed out that in their evidence there was no assertion that they were employed against jobs of permanent nature. Thus, the workers have failed to establish that they were employed against permanent vacancies or on permanent basis. Shri Kedar Nath was operating the lift on Sundays and holidays. Now if a construction worker is asked to operate lift on Sundays and holidays, it cannot be said that he was working against a permanent post, or in connection with the affairs of the bank. It is in evidence of the management that posts of liftmen were in existence and had not been abolished. It is also in the evidence of the workmen that on Sunday and holidays they were asked to work on lift though on other days they were looking-after the construction work. This

merely would, however, not mean nor make them permanent workmen in view of the dictum of the Hon'ble Supreme Court of India in Rohtas Industries Vs. its workmen (1956 II. LLJ. 444) cited by Dr. Anand Prakash appearing for the management. It was held, therein, that even if after the completion of the temporary work, the temporary worker worked for sometime in production department then it did not make him permanent. In the present case also, both the workers were employed on construction work which work was of a temporary character. It would be wholly inequitable, too, in the very nature of their employment to force the employer to continue to employ them beyond the completion of the work for which they were engaged (1970, Lab. I. C. 907). The allegation of the management that they were paid on daily basis does not, however, carry any conviction with me. MWI Shri Ishwar Dass Dogra admitted in cross-examination that they were paid at the rate of Rs. 200/- per month irrespective of the fact whether a month was of 28 days, 30 days or 31 days.

12. Hence, I reach a conclusion that the concerned workmen were employed at the site of the construction work of the building of the bank and when that work came to an end, their services could be retrenched as they were no longer required in connection with the construction of the said building.

13. In view of my finding above that the concerned workmen were employed in connection with the construction work of the building of the bank, it remains no more of any consequence whether they were temporary workmen or casual workmen. As held in 1971, I. LLJ. 241 even a casual worker is a worker within the meaning of the word, 'workman' as defined in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act. It was further held that although casual workmen are expressly excluded from the benefits of lay-off compensation yet they are not excluded from the benefit of retrenchment compensation if they fulfil certain conditions prescribed in Section 25F of the Act. The same view was taken by the Madras High Court in 1970 II. LLJ. 454 (Elomalai v. Management of Simplex Concrete Piles (India) Ltd. Madras and another) whether it was held that the definition of worker in Section 2(s) is in the widest possible terms and includes a casual worker. In view of this I hold that even if these workers are taken to be casual workers it does not make any difference.

14. It is, also, of no importance whether the case falls under Section 25F or 25FFF(2) of the Industrial Disputes Act, as in either case compensation payable to the workmen is the same, except that in case of 25F, the payment of compensation is a condition precedent to retrenchment which it is not under section 25FFF(2). Sub-section (2) of Section 25-FFF of the Act reads as follows:—

"Where any undertaking set-up for the construction of building, bridges, roads, canals, dams or other construction work is closed down on account of the completion of the work within two years from the date on which the undertaking had been set-up, no workman employed therein shall be entitled to any compensation under clause (b) of Section 25-F, but if the construction work is not so completed within two years, he shall be entitled to notice and compensation under that section for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of six months."

In the present case, the construction work was not completed within two years. It is, therefore, clear from a perusal of the above sub-para that in case of an undertaking set-up for construction of building a workman will be entitled to compensation if the work does not complete within two years from the date on which the undertaking had been set-up. As already stated above, in this case the construction work was started in 1965 and it continued till 1973; therefore, the workman was entitled to compensation under Section 25-F. The difference, however, between Section 25-F and Section 25-FFF is that the conditions specified in Section 25F are conditions precedent to retrenchment so that if retrenchment is effected without complying with the said conditions the retrenchment is void whereas Section 25FFF does not provide for any condition precedent. An employer can close down his business without prior payment of compensation as held

36 G. of I. /74—6.

by the Supreme Court in the case of Hathising Manufacturing Co. Ltd. v. Union of India (1960, II. LLJ. 1). Applying Section 25F with its condition precedent, I find that Shri Dharmanand workman was offered Rs. 200/- as wages for July 1972 and a further sum of Rs. 400/- as compensation. He refused to accept the said sums on the 31st of July 1972. These amounts were then sent by pay-order and he accepted the same under protest. Similarly, in the case of Shri Kedarlal Rs. 200/- and Rs. 400/- were offered on the 31st of July 1972 but he too refused to accept the same. Thus, there was no violation of the condition laid down in Section 25F. Moreover, it was not the case of the workmen that their termination of service was in violation of the provisions of Section 25F of the Act. In this connection my attention was drawn to the case of Gyanchand Vs. Rawal Pindi Victory Transport Co. Ltd. (1970, 37. FJR. 451). It is a case in which the facts are on all fours the same as in this case. It has been held therein that, "a tribunal would be acting beyond its jurisdiction in giving a decision on a matter which has not been raised in the pleadings." In their demand notices Exts. W/1 and W/2, too, the workmen did not take the stand that the termination of their services was in violation of the provisions of Section 25F of the Act. The result is that so far as Section 25F is concerned, the workmen are not entitled to any relief under it.

15. Similarly, under Section 25FFF, too, they are not entitled to any relief as ultimately under it, section 25F was to be pressed into service and it has been already held that there was no violation of it.

16. Shri Ramamurthi submitted that the services of the workmen were terminated on malafide intentions and untenable grounds. Dr. Anand Parkash on the other hand urged that in that sense the malafide intentions and untenable grounds meant that if the workmen were able to prove that the construction work had not been over or that there had been victimisation it would be untenable grounds and malafide intention. I have already held above that the concerned workmen were employed against a specific work and the same had been completed. So, there is no question of malafides on the part of the management inasmuch as when the main construction work against which they were engaged came to an end, their services could be retrenched.

17. The last question is whether the action of the bank in terminating the services of Sarvashri Dharmanand and Kedarlal was justified.

18. On consideration, I am of the opinion that the management was quite justified in their action of retrenching the concerned workmen. They were employed in connection with the construction work of the Parliament Street building of the bank and it having been completed, it was well within the management discretion of the bank to organise and arrange its work and to retrench the dead weight of uneconomic surplus.

19. There was no violation of any law, either, in this retrenchment. Due compensation was offered and even paid which the workmen accepted. Hence, in view of this, the workmen are not entitled to any relief in these proceedings; and the award is made accordingly.

D. D. GUPTA, Presiding Officer

4th June, 1974.

[No. L. 12012/170/72/IRIIII]

New Delhi, the 17th June, 1974

S.O. 1640.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs. Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th June, 1974.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL—
CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (CAMP AT
ALLAHABAD)

Case No. CGIT/LC (R) (24)/73

(Notification No. L-29011(55)/72-LR. IV) dated 24th November, 1973.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Messrs. Jaipur Udyog Limited, Sawaimadhopur P.O. Phalodi Quarry, district Sawaimadhopur and their workmen.

APPEARANCES :

For the workmen—1. Sri P. K. Sharma, 2. Sri B. L. Gautam.

For the management—Sri C. N. Sharma, Advocate.

Industry : Lime Stone Quarries District : Sawaimadhopur (Rajasthan).

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter called 'the Act'. The question referred for the adjudication of this Tribunal is :—

"Whether the management of Messrs. Jaipur Udyog Limited Sawaimadhopur have implemented the recommendations of the Central Wage Board for Cement Industry in regard to piece-rated stone cutters employed in their Phalodi Bharopura Bajarakho and Laxmipura Lime Stone Quarries? If not, to what relief are these workmen entitled?"

In short, the contention of the workmen of Messrs Jaipur Udyog Limited Sawaimadhopur hereinafter called the management, is that the management did not give the piece-rated stone cutters employed by it any annual increments which were due to them in the year 1961 and onwards.

Preliminary objections have been raised on behalf of the management. Firstly, that the dispute, by a mutual agreement dated 22-12-1971, was referred to the arbitration of Sri Mohan Lal Ji Sukhadia, presently the Governor of Karnataka, and the reference before this Tribunal is illegal. The representative of the management could not give any information to the Tribunal as to the progress made in the aforesaid arbitration proceeding before Sri Mohanlal Ji Sukhadia. Merely because the dispute was referred to the said Arbitrator as far back as 22-12-1971 and in absence of anything on the record to indicate as to the stage of the proceedings before the Arbitrator, I am not prepared to hold that the reference before this Tribunal suffers from any legal infirmity. Evidently, there was a dispute between the parties and it came before the Assistant Labour Commissioner (Central), Kota for conciliation. Eventually, the conciliation proceedings ended in failure, and the dispute has been referred to this Tribunal. I hold that the reference before me is in accordance with the law.

Secondly, it was contended on behalf of the management that the workmen have claimed increments from 1961 onwards and on the face of its their claim is very belated. There appears to be substance in this contention. If the workmen were entitled to increments from 1961 onwards they should have put forward their claim within a reasonable time soon after when the management denied them the increments for the first time. Evidently, the workmen did not pursue their claim for a long time and on the fact of it their claim now made before this Tribunal is stale and belated. The management relied on the decision of the Supreme Court in Inder Singh & Sons. Ltd., and their workmen (1961(I)LLJ-P.89). The Supreme Court observed :—

"It is true that laws of limitation which might be any Civil Court from giving remedy in respect of law-

ful rights are not and should not be applied by the Industrial Tribunals. On the other hand it is well-accepted principle of Industrial adjudication that stale claims should not generally be encouraged or allowed, unless there is a satisfactory explanation for the delay."

In the circumstances of the present case I would have been reluctant to grant to workmen any relief as claimed by them in view of the very belated nature of their claim.

On the merits it appears that there is not much substance in the claim for annual increments as put forward by the workmen. Reliance was placed on their behalf on the recommendations of the 1st Central Wage Board for Cement Industry which came into effect on 1st January, 1960. The Wage Board classified the piece-rated workmen as unskilled workmen. On page 74 para 13.11.1. the Board said :—

"In the case of piece-rated operatives, the basic wages mentioned above should be the basic wage payable on the Standard Minimum workload."

It was contended on behalf of the workmen that in accordance with the aforesaid recommendations, the management fixed the piece-rated stone cutters in "E" grade of operatives and fixed the minimum workload on existing rates i.e. @ 50 paisa per tonne on monthly basis at 104 tonnes. While implementing the recommendations the management deliberately ignored the recommendations regarding the annual increments to such piece rated workers and related the output with annual increments against the recommendations. In other words, the management did not treat the annual increments given to such piece-rated stone-cutters an additional basic wage and increased the workload every year with the annual increment. It was submitted on behalf of the workmen that by the abovementioned practice the management fixed the minimum workload on existing rates i.e. @ 50 paisa per tonne on monthly basis at 104 tonnes to such piece-rated stone cutters.

The recommendations of the Second Central Wage Board came into operation with effect from 13-2-1968. The only modification in the recommendations of the 1st Central Wage Board that the Second Central Wage Board made was that it provided for Rs. 61.60 p.m. or Rs. 2.35 per day as the basic wage for an unskilled workman. It said :—

"We, therefore, stipulate that the new piece rate should be arrived at by dividing this basic wage by the existing workload. Except for this, the other recommendations of the First Cement Wage Board in respect to piece-rate shall remain unaffected. The new fall back wage, as per our recommendations, shall be Rs. 61.60 p.m. if the workload is fixed on monthly basis and Rs. 2.35 per day if workload is on a daily basis. The other conditions mentioned in para 13.13.4 of the First Wage Board in regard to fall back wage shall continue to hold good."

On the basis of the aforesaid modification in the First Wage Board recommendations, it was contended on behalf of the workmen that due to the increase in fall back wage from Rs. 52 p.m. to Rs. 61.60 p.m. on existing minimum workload the new rate comes to Rs. 59.23 paise per tonne instead of 50 paise per tonne and all the payments had to be made accordingly after 13-2-1968, but the management did not implement these recommendations and calculated and paid wages @ 50 paise per tonne. It was thus contended that :—

"In substance, the company did not give any annual grade increment to piece-rated stone-cutters which fell due to them in the year 1961 and onwards. The payment is also being made @ 50 paise per tonne instead of 59.23 p. per tonne w.c.f. 13-2-1968."

Admittedly, the workmen who are claiming the annual increments, are about 325 in number. They are only a section of unskilled piece-rated stone cutters. It was contended on behalf of the management and not denied by the representative of the workmen that stone is drilled and blasted by other workmen and the duty of the workmen in question before me is only to load the pieces of stone. It was con-

tended on behalf of the management that it has to incur separate expenses for drilling and blasting the stone rocks and the workmen in question have only to collect them. It was strenuously argued on behalf of the management that the fixation of the wage at Rs. 52 by the First Wage Board had no relevance to the workload and it was wholly wrong on the part of the workmen to say that an average of Rs. 104 per tonne should be made the basis of calculation. Reference was made to the report of the National Productivity Council with regard to excavation in which it was said that the average excavation should be 13 tonnes per day (vide page 129 para 19.2.8.). The management referred to the settlement between it and the workmen dated 15-4-1955 which, according to it, was a comprehensive settlement in respect of the various demands pertaining to the workmen of Phalodi Quarry. The question of wages of stone cutters was mutually settled. The relevant terms of the aforesaid settlement are:—

- (i) For white hard stone (high) at the rate of annas eight per tonne plus two annas and six pies for compressor charges. Company would recover from the workers for the drilling charges at the rate of five annas and six pies per running foot for 1-1/4" to 2" size holes. After working for the period of a month if it would be found that 1 ft. hole yields less than 2-1/4" tonnes of stone the recoverable rate for drilling charges would be reduced to five annas per running foot. In case we go in for the bigger size boring experiment would be made and rates for charging the recoverable amount would be adjusted proportionately. Quantity of explosives considered reasonable by the Company would be supplied free of cost.
- (ii) For red stone workers would be paid at the rates of annas ten per tonne. No boring is to be done by the Company. Quantity of explosives considered reasonable by the Company would be supplied free of cost."

The management contended that from the aforesaid terms it would appear that the rate of 8 annas per tonne was inclusive of all allowances and payments were actually made for a long time on that basis and according to it out of payment of 8 annas per tonne, the company could recover from the workmen drilling charges at the rate of five annas and six pies per running foot for 1-1/4" to 2" size holes. This amount was to be adjusted from the rate of 8 annas per tonne of excavated limestone. According to the management the workload immediately preceding the operation of the First Wage Board for the Cement Industry was 6.02 tonnes per man per day calculated on the basis of the average for the year 1959. According to it, the payment at the rate of Rs. 2 per day had to be made to the workmen on the basis of 6.02 tonnes production which would work out to 33 paise per tonne out of which drilling charges had further to be recovered in terms of the settlement dated 15-4-1955. It was emphatically denied that the management had fixed the minimum workload on existing rates i.e. at the rate of 50 paise per tonne on a monthly basis at 104 tonnes. It was emphasized that the existing workload was 6.02 tonnes per man per day and as such the minimum monthly workload worked out to 156.52 tonnes and not 104 tonnes as alleged on behalf of the workmen. The management has stated that it has not given less to the workmen concerned than what was recommended by Wage Board irrespective of their production and that additional payments at the rate of 8 annas per tonne were to be given to the workmen who produced more than 6.02 tonnes per day which was the existing workload on 1-1-1960. It was further emphasised that the management had refrained from recovering the drilling charges which had been incurred by it from the workmen and had acted with a view to give overall benefits to workmen to whom they were entitled under the settlement of 1955 or under the Wage Board recommendations. According to the management, at no time its piece-rated operatives were paid less than what the unskilled operatives were paid. It was emphasised that the settled rate was 50 paise per tonne under the said settlement and it was not or could not be 59.23 paise as was claimed on behalf of the workmen. An affidavit was produced on behalf of the management along with certain enclosures. Annexure '2' of the affidavit shows the average per man per day production of limestone in 1959 in Phalodi Quarry of the

management. From the aforesaid statement, the average production per tonne per man comes to Rs. 156.52. It would thus appear that the entire controversy between the parties is with regard to the quantum of the workload and whether it would be Rs. 104 tonnes as claimed by the workmen or the minimum monthly workload would work out to Rs. 156.52 as alleged by the management. The Recommendations of the First Wage Board only said:—

"The proper method to do this will be to divide the new basic wage of Rs. 52 per month if the workload is fixed on monthly basic or Rs. 2 per day on daily basis by the existing workload in order to arrive at the new piece-rate, dearness allowance and house rent allowance to be paid as recommended for unskilled operatives in para 13.7.1."

It did not mention the quantum of the workload. There is no evidence in support of the contention on behalf of the workmen that the management "had fixed the minimum workload on existing rates i.e. @ 50 paise per tonne on monthly basis at 104 tonnes". On the other hand, the management had produced sufficient evidence to show that the quantum of the workload per day was 6.02 tonnes. There is no force in the contention of the workmen that the management had wrongfully increased the workload every year and had thus neutralised the annual increments. The workmen have been getting their due annual increments, and it could not be said that such annual increments had been neutralised by the output of the workmen.

My answer to the question referred to this Tribunal is in the affirmative. I hold that the management has implemented the recommendations of the Central Wage Board for Cement Industry in regard to piece-rated stone cutters employed in their Phalodi, Bharonpura Bajarakho and Laxmi-pura Lime Stone Quarries and as such the workmen are not entitled to any relief as claimed by them. I make my award accordingly. Parties will bear their own costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer.

Dated 24-4-1974.

[No. L-29011/55/72-LR. IV]

S.O. 1641.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-Cum-Labour-Court, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Chand Khan, Mine Owner, Budhpura Sand Stone Mine, Post Office, Budhpura District Bundi and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1974.

CAMP AT PACHMARHI

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT JABALPUR (M.P.)

PRESENT :

Mr. Justice S. N. Katju, Presiding Officer.

Case No. CGIT/LC(R)(6) of 1974

(Notification No. L-29011/5/74-LRIV Dated 25-2-1974)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Shri Chand Khan, Mine Owner Budhpura Sand Stone Mine, P.O. Budhpura, Distt. Bundi and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent), Kota (Rajasthan).

APPEARANCES :

For employer—None.

For workmen—Shri Mahabir Prasad Sharma.

Industry : Sand Stone Mine District : Bundi (Rajasthan)

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

The question referred to this Tribunal for its adjudication is :—

"Whether the workmen employed in the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Chand Khan, Post Office Budhpura, Distt. Bundi (Rajasthan) are entitled for grant of any paid national and festival holidays ? If so, for how many days ?"

The workmen of the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Chand Khan, Post Office Budhpura, district Bundi have claimed that they are entitled to the grant of the following Festival and National holidays as paid holidays :—

1. 26th January (Republic Day)	... 1 day.
2. Holi (Dhulendi)	... 1 day.
3. 1st May (Labour Day)	... 1 day.
4. Raksha Bandhan	... 1 day.
5. Krishna Janmastmi	... 1 day.
6. 15th August (Independence Day)	... 1 day.
7. Dipawali	... 1 day.
8. 2nd October (Gandhi Jayanti)	... 1 day.
9. Dushabra	... 1 day.
10. Id or Local Festival	... 1 day.

The dispute with regard to the said claim of the workmen was sponsored on behalf of the workmen by the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota. The President of Pathar Khan Mazdoor Sangh, Shri Mahabir Prasad Sharma, at first sent a letter to the management with regard to the claim on 2-11-1973 (Ex. W/1) the acknowledgment receipt of which is Ex. W/2. But the management did not send any reply to the said letter. Thereafter the Mazdoor Sangh raised the present dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota by its letter dated 24-11-1973 (Ex. W/3). The management's representative did not appear before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota and the conciliation proceedings before him ended in failure.

No one appeared on behalf of the management on the various dates fixed for the hearing of the reference. The acknowledgement receipts of the notices to the management were not received back by this Tribunal. The hearing of the case had to be adjourned on 10-4-1974, 26-4-1974, 8-5-1974 and 9-5-1974 because on the aforesaid dates neither any representative of the management appeared before me nor the acknowledgement of the service of notices issued were received back.

On 9-5-1974 I passed the following order :—

"Acknowledgement of the service on the management has not been received so far.

Put up for filing of written statement-cum-rejoinders of the parties and for final hearing on 22-5-1974 at Pachmarhi (New Rest House)."

It is difficult to understand as to why repeated notices sent to the management have not been served on it. I am not prepared to postpone the hearing of this reference any further. The management had been duly informed of this reference by the Central Government and it should by itself have filed its written statement within 10 days of the receipt of the order of reference by the Central Government.

Shri Mahabir Prasad Sharma, the President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota, gave evidence on behalf of the workmen. He has stated that the workmen

in the neighbouring mines are given the aforesaid Festival and National holidays as paid holidays. In a number of references, which have come to me from districts Bundi and Sawai Madhopur, the same question as is involved in the present reference came for consideration before me. I expressed the view that the workmen are entitled to the aforesaid holidays as paid holidays. These holidays are national holidays and are observed as such throughout the country. There is no reason why these holidays should be denied to the workmen employed in the Budhpura Sand Stone of Shri Chand Khan, Post Office Budhpura, District Bundi. The mere fact that the workmen are given one day's off in a week under the Mines Act is no ground for withholding the aforesaid National and Festival holidays from them. I am clearly of the view that the workmen of the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Chand Khan are entitled to the grant of the aforesaid National and Festival holidays as paid holidays from 2-11-1973 and I make my award accordingly. The workmen will have Rs. 100/- as costs.

Dated 22-5-1974.

S. N. KATJU, Presiding Officer.

[No. L-29011(5)/74-I.R. IV]

S.O. 1642.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Tiwari Jhumar Lal Swarooplal, Mine Owner, Karauli and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th June, 1974.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL
CUM-LABOUR COURT AT JABALPUR (CAMP AT
ALLAHABAD)

Present :

Mr. Justice S. N. Katju, Presiding Officer.

Case No. CGIT/LC(R)(23)/1973.

(Notification No. L-29012/29/73-LR-IV dated September 24, 1973).

Parties :

Employers in relation to the management of Messrs Tiwari Jhumar Lal Swarooplal, Mine Owners, Post Office-Karauli District Sawai Madhopur and their workmen.

APPEARANCES :

For the workman—Shri M. P. Sharma.

For the management—Sri B. L. Sharma.

Industry: Lime Stone District : Sawai Madhopur (Raj.)

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, hereinafter called 'the Act'. The dispute before me refers to the termination of service of Shiv Shanker Sharma. He was employed as a Munshi in the Mining Office, Karauli, of M/s. Tiwari Jhumar Lal Swarooplal, Mine Owners, Post Office Karauli, district Sawai Madhopur, hereinafter called 'the management'.

The dispute of the workman was sponsored by the Pathar Khan Mazdoor Sangh, hereinafter called the Mazdoor Sangh,

which is a registered Trade Union, of which the workman, Shiv Shanker Sharma, is a member. It was contended on behalf of the workman that he was employed as a Munshi by the management since the last 30 years, and was getting Rs. 275/- at the time of the termination of his service on 31-10-1972. It was further contended that no notice with regard to termination of service of the workman was given to him and his services were abruptly terminated by a registered letter sent by the management to him dated 30-10-1972 which said that his services were terminated with effect from 31-10-1972. The Mazdoor Sangh first wrote directly to the management on behalf of the workman by its letter dated 14-5-1973 to which the management did not give any reply. Then the dispute was raised before the Assistant Labour Commissioner (Central) Ajmer. It appears that on the dates fixed for discussions before the Regional Labour Commissioner (Central) Ajmer, the management did not send any representative and only sought adjournments. Eventually, the proceedings before the Regional Labour Commissioner ended in failure. Thereafter, the dispute was referred to this Tribunal.

Before this Tribunal also, the management did not put in appearance on a number of dates fixed in the case and did not file its written statement. The representative of the management appeared before me on 4-4-1974 at Jaipur. With considerable reluctance I gave him another opportunity to file the management's written statement on 5-4-1974.

An application was made on behalf of the management for being permitted to be represented by an Advocate. This was opposed by the workman and the application was rejected. Another application was made on the same date viz. 5-4-1974 on behalf of the management for adjournment of the hearing which was rejected by me.

The workman Shiv Shanker Sharma was examined and cross-examined before me. He stated that he was working in the mines of the management since the last 30 years as a Munshi and his services had been terminated by the management by a letter (Ex.W/1), which was received by him on 30-10-1972, and which said that his services were terminated from 31-10-1972. He admitted that he had received his salary for the period upto 31-10-1972. He further stated that he did not receive any notice nor any chargesheet was given to him by the management. He stated that he had sent a notice to the management through his Advocate dated 4-11-1972 (Ex.W/6), which was not accepted by the management. He further stated that he did not know reasons for the termination of his service and has prayed that he should be reinstated on his post and get his back wages from the management.

In his cross-examination, Shiv Shanker Sharma said that he was employed in the mines of the management in 1944 or 1945 on a salary of Rs. 15/- per month. Thereafter, the salary was increased periodically and he was getting Rs. 275/- per month since about two years before the termination of his service. He denied that he had a personal business or owned a Truck. He further stated:—

"I have no mining business of my own. My sons do mining business. This mining business is of my two sons, who are grown up and have their own children. My two sons are separate with me. There is no truck even in the name of my sons. It is wrong to say that my services were terminated because I had started my separate business. In my reply given through an Advocate dated 3-11-1972 I had not asked for reinstatement of my service."

In the course of arguments on behalf of the management, it was contended that Shiv Shanker Sharma had started a rival business in the name of his sons, and he was negligent in the performance of his duties and had lost the confidence of the management. As mentioned above, Shiv Shanker Sharma denied that he had a separate business of his own. He, however, admitted that his two sons, who according to him are separate from him, are engaged in mining business.

The management also carries on mining business and admittedly the two sons of the workman are engaged in a business similar to that of the management. In these circumstances, it would not be surprising that the management would lose confidence in Shiv Shanker Sharma.

In *Bunny Limited v. Their Workmen and another* (A.I.R. 1972 S.C. 1975), the Supreme Court observed:—

"It has become almost a settled principle that reinstatement should not be awarded where the management justifiably alleges that they have ceased to have confidence in the dismissed employee. In other cases, the Tribunal must consider carefully the circumstances of the case to come to a finding that justice and fair play require that reinstatement should be awarded."

In *M/s Francis Klein & Co. Private Ltd. v. The Workmen and another* (A.I.R. 1971 S.C. 2414), it was observed that:—

".....if once the Company has lost confidence in its employee it is idle to ask them to employ such a person in another job."

In *Bunny Ltd. v. Their Workmen* (A.I.R. 1973 S.C. 1403), the Supreme Court observed:—

"It was quite clear that on his own admission he had acted in a manner by which the Management could possibly have no confidence in him for the future. His reinstatement as well as the payment of Rs. 5,000/- as back wages therefore, could not have been ordered according to the well settled law and principles on the point."

While it was denied by the workman that he was carrying on a mining business of his own, he has admitted that his sons are carrying on such business. Even though the workman has said that his sons have their separate business and it was argued on his behalf that he had no concern with the business of his sons, I am not prepared to go to the extent of believing that the workman himself was entirely disinterested in the business of his sons. Where a person is employed in a business concern and his sons start separate business of their own on similar lines, there will, particularly in the circumstances of the case before me, be a valid reason for the management for losing confidence in the employee concerned. I am, therefore, not prepared to direct the reinstatement of the workman in the service of the management.

The management, however, has acted in an arbitrary manner in dispensing with the services of Shiv Shanker Sharma without giving him any notice or asking for any explanation from him. As mentioned above, it also avoided appearing before the Regional Labour Commissioner as also before me prior to 4-4-1974 when I took up the case at Jaipur. Evidently, the management has scant respect for legal formalities. Even if it had a valid ground for dispensing with the services of Shiv Shanker Sharma, it should have not done so in an arbitrary manner without giving him any notice or an opportunity to explain his position. Shiv Shanker Sharma did not ask for his reinstatement when he sent his letter to the management dated 3-11-1972 through his Advocate. As mentioned above, I am not prepared to direct the reinstatement of Shiv Shanker Sharma in the service of the management. He is, however, entitled to compensation from the management, particularly in view of the rash and arbitrary manner in which his services were terminated by the management. He is entitled to get Rs. 1,000/- as compensation from the management together with Rs. 200/- as costs, in all Rs. 1200/-.

I hold that the action of the management in terminating the services of Shiv Shanker Sharma, Munshi, Mining Office, Karauli with effect from 31st October, 1972 was arbitrary and not in accordance with the law and he is entitled to get Rs. 1,000/- as compensation and in addition Rs. 200/- as costs from the management.

I make my award accordingly.

Dated 23-4-1974

S. N. KATJU, Presiding Officer.

[No. L-29012/29/73-I.R. IV].

S.O. 1643.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute, between the employer in relation to Shri Kanhaiji Dhakad, Mine Owner, Budhpura Sand Stone Mine, Post Office Budhpura, District Bundi and his workmen, which was received by the Central Government on the 7th June, 1974.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)
CAMP AT PACHMARHI

Case No. CGIT/LC(R) (7) of 1974.

(Notification No. L-29011(4)/74-LRIV Dated 2-3-1974).

Parties :

Employers in relation to Shri Kanhaiji Dhakad, Mine Owner, Budhpura Sand Stone Mine, Post Office Budhpura, District Bundi (Rajasthan) and their workmen represented through the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota (Rajasthan).

Appearances :

For employer	None
For workmen	Shri Mahabir Prasad Sharma

District : Bundi (Rajasthan) Industry : Stone Mine.

AWARD

This is a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

The question raised in the reference is whether the workmen employed in the Budhpura Sand Stone Mine of Shri Kanhaiji Dhakad, Post Office, Budhpura, District Bundi (Rajasthan) are entitled to the grant of the following National and Festival holidays as paid holidays as claimed by them.

1. 26th January (Republic Day)	... 1 day.
2. Holi (Dhulendi)	... 1 day.
3. 1st May (Labour Day)	... 1 day.
4. Ruksha Bandhan	... 1 day.
5. Krishna Janmastmi	... 1 day.
6. 15th August (Independence Day)	... 1 day.
7. Dipawali	... 1 day.
8. 2nd October (Gandhi Jayanti)	... 1 day.
9. Dushehra	... 1 day.
10. Id or Local Festival	... 1 day.

The dispute as regards the said claim of the workmen was sponsored on behalf of the workmen by the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota.

The President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Shri Mahabir Prasad Sharma, at first sent a letter to the management with regard to the workmen's claim on 31-10-1973 (Ex. W/1) but the management did not send any reply to the said letter. Thereafter the Mazdoor Sangh raised the present dispute before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota by its letter dated 21-11-1973 (Ex.W/2). The management's representative did not appear before the Assistant Labour Commissioner (Central) Kota and the conciliation proceedings before him ended in failure.

No one appeared on behalf of the management on the various dates fixed for the hearing of the reference. The service of the notices sent to the management were not received back by this Tribunal. On 18-3-1974 I fixed 10-4-74

for filing of written statements by the parties. On 10-4-1974 Shri Mahabir Prasad Sharma appeared on behalf of the workmen, but no one appeared on behalf of the management. Since the notice had not been served on the management I fixed 26-4-1974 for filing of written statement by the management and for written statement-cum-rejoinders by the parties. No one appeared on behalf of the parties on 26-4-1974 and acknowledgment of service of the notice on the management was also not received by that date. Again on 7-5-1974 the acknowledgment of service on the management had not been received. I directed the reference to be put up for filing of "written statement by the management, rejoinders of the parties and final hearing on 21-5-1974 at Pachmarhi". Again no one appeared on behalf of the management, nor the acknowledgment of service of notice on the management has been received by the Tribunal. It is difficult to understand as to why repeated notices sent to the management have not been served on it. I am not prepared to adjourn the hearing of the case any further. The management had been duly informed of this reference by the Central Government and it should by itself have filed its written statement within 10 days of the receipt of the order of reference by the Central Government.

Shri Mahabir Prasad Sharma, the President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh (Independent) Kota, gave evidence on behalf of the workmen. He has stated that the workmen in the neighbouring mines are given the aforesaid Festival and National holidays as paid holidays. In a number of references, which have come to me from districts Bundi & Sawai Madhopur, the same question as is involved in the present reference came for consideration before me. I expressed the view that the workmen are entitled to the aforesaid holidays as paid holidays. These holidays are national holidays and are observed as such throughout the country. There is no reason why these holidays should be denied to the workmen of the Budhpura Sand Stone Mine. The mere fact that the workmen are given one day's off in a week under the Mines Act is no ground for withholding the aforesaid National & Festival holidays from them. I am clearly of the view that the workmen of Budhpura Sand Stone Mine of Shri Kanhaiji Dhakad, Mine Owner, Post Office Budhpura, District Bundi, are entitled for the grant of the aforesaid National & Festival holidays as paid holidays from 31-10-1973 and I make my award accordingly. The workmen will have Rs. 100/- as costs.

S. N. KATJU, Presiding Officer
Dated 21-5-1974

[No. L-29011/4/74-LR. IV]

P. P. KANTHAN, Under Secy.

नई दिल्ली 22 जून, 1974.

K.A. 1644.—खान अधिनियम, 1952, (1952 का 35 की धारा 5 की उपधारा (1) स्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतदिवारा श्री स. बी. सिंह को मुख्य खान निरीक्षक एवं अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. ए-35017/7/71-स्प-1]

टी. एस. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd June, 1974

S.O. 1944.—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 5 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri A.B. Singh as Inspector of Mines subordinate to the Chief Inspector of Mines.

[No. A. 35017/7/71-MT]
T. S. KRISHNAMURTHI, Under Secy.

प्राप्तेश

तर्फ़ दिल्ली, 18 मई, 1974

का० आ० 1645—यदि केन्द्रीय सरकार की याचना है कि इसमें उपचार, अनुसूची में विनियोगित विधियों के बारे में बुरहार और अम्लाई कोलियरीज, डाकघर धानपुरी, जिला शहडोल (मध्य प्रदेश) के प्रबन्ध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक आवृत्तिगिक विवाद विद्यमान है;

और यदि केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वैधित करना चाहनीय समझती है;

धन्तः, धब्द, आवृत्तिगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुष्ठान (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित आवृत्तिगिक अधिकारण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वैधित करती है।

अधिकृत

क्षया बुरहार सं० 1 और 2 अम्लाई कोलियरीज, धानपुरी, शहडोल (मध्य प्रदेश) के पत्रिले मालिक—मैमसं रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, कलकत्ता का, लेखा वर्ष 1972 के कुल नाभों से दी जाने योग्य उपदान की स्फीत राशि को घटा देवा न्यायावित है और यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

क्षया बुरहार सं० 1 और 2 और अम्लाई कोलियरीज, धानपुरी, शहडोल (मध्य प्रदेश) के पत्रिले और इस ममत्य के मालिक मैमसं रेवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, और मैमसं लूल माइन्स आवृत्तिगिक लिमिटेड का बोनस संदाय अधिनियम, 1965 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए लेखा वर्ष 1972 के लिए अपने कर्मकारों को बोनस का भुगतान न करना न्यायोचित है। यदि नहीं, तो वे किस तारीख के हकदार हैं?

[सं० एल०-22011/12/73-एल०आर०-2]

पी० भार० नैयर, उप-सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th May, 1974

S.O. 1645.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Burhar and Amlai Collieries, Post Office Dhanpuri District Shahdol Madhya Pradesh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether Messrs Rewa Coalfields Limited, Calcutta, erstwhile owners of Burhar No. 1 and 2 and Amlai Collieries, Dhanpuri, Shahdol (Madhya Pradesh) are justified in deducting inflated amount of gratuity payable from the gross profits of the accounting year 1972 and if not, to what relief are the workmen entitled?

Whether Messrs Rewa Coalfields Limited and Messrs Coal Mines Authority Limited, the erstwhile and present owners of Burhar No. 1 and 2 and Amlai Collieries Dhanpuri, Shahdol (Madhya Pradesh) are justified in not making payment of bonus to their workmen for the accounting year 1972 in Contravention of the provisions of payment of Bonus Act, 1965. If not, to what benefit are they entitled?

[No. L-22011/12/73-I.R.I.]

New Delhi, the 22nd June, 1974

S.O. 1646.—In pursuance of the section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Arbitrator in the industrial dispute between employers in relation to the management of Honnahalli Iron Ore Mines of Shri Inniah Reddy and their workman Shri R. Lakshmi Reddy which was received by the Central Government on the 12th June, 1974.

BEFORE SHRI M. R. RAJU, REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL) HYDRAFABAD—ARBITRATOR

In the matter of on an industrial dispute under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947.

No. B1/105 (6)/74

BETWEEN

Shri A. Laxmi Reddy, Workman.....Claimant

AND

Shri A. R. Murthy Power of Attorney to Shri S. Inniah Reddy, Mine Owner.....Respondent

PRESENT

Shri M. R. Raju, Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad.—ARBITRATOR.

APPEARANCES :

For workman — 1. Shri A. C. J. Dasen Solomon Authorised representative.

2. Shri R. Laxmi Reddy—Workman.

For Employer — 1. Shri A. R. Murthy, Power of Attorney to Shri S. Inniah Reddy, Mine Owner.

AWARD

The present reference arises out of order No. L-260-13/1/74-LR-IV dated 10th April, 1974 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. Subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order, and the said schedule runs as follows :—

“Whether the management of Honnahalli Iron Ore Mines is justified in terminating the services of Shri R. Lakshmi Reddy, Mastry? If not, to what relief Shri R. Lakshmi Reddy is entitled to?”

2. This order was received by me on 18-4-74 and notices were sent to the parties for submission of their written statements. In his written statement it is contended by the workman that he was employed as a Mastry in the above Iron Ore Mine from 18-11-72 and his services were terminated on 25-11-73. He also contended that the services of a temporary workman cannot be terminated as punishment for misconduct without establishing it at a proper domestic enquiry held for the purpose and he further demanded that he should be reinstated with all back wages and continuity of service. In reply to the statement of the workman, the respondent stated that Shri Laxmi Reddy had been

working as casual masonry and his services were dispensed with after 10 months of service. He was again reappointed as a fresh employee on 6-9-69 as a casual worker and he was put on probation and his services were terminated with effect from 24-11-73. As he has hardly put in 2 months service he is not entitled to invoke the provisions of the Industrial Disputes Act.

3. The matter was posted for hearing on 5-6-74 in the office of the Asstt. Labour Commissioner (Central) Bellary. During the course of discussions the parties requested time to have mutual discussions. The request was acceded to. After completion of their discussions, the parties filed a memo of compromise according to which the workman will be paid Rs. 400/- in full and final settlement of his claims against the management and he will have no claim against the management for employment. I have gone through the terms of settlement contained in the said petition. They are fair and reasonable and, therefore, I make an award on the basis of the terms of settlement. The joint petition of compromise shall part of the award.

4. Let a copy of this award be forwarded to the Central Government under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

M. R. RAJU, Regional Labour Commissioner.

BEFORE THE ARBITRATOR REGIONAL LABOUR COMMISSIONER (CENTRAL), HYDERABAD CAMP AT BELLARY ON 5-6-1974

BETWEEN

Shri A. R. Murthy.....Claimant

AND

Shri R. Lakshmi Reddy.....Respondent

JOINT MEMO FILED ON BEHALF OF PARTIES

The parties have compromised the matter and the claimant has agreed to receive Rs. 400/- (Rupees Four Hundred only) in full and final settlement of all claims against

the respondent. The claimant has no claims on employment. The amount will be paid in the presence of the Assistant Labour Commissioner (Central) Bellary with in 15 days from the date of this memo on a date fixed by the Assistant Labour Commissioner (Central). Bellary.

It is prayed that award may be passed in terms of this Joint Memo.

Signature of the parties.

Representing the Management

A. R. MURTHY, Power of Attorney to Shri S. Inniah Reddy Mine Owner.
Camp : Bellary
Dated : 5-6-74

Representing the Employee.
A. C. J. DASEN SOLOMON, Authorised Representative.
R. LAKSHMI REDDY, Workman Claimant.

[No. L-26013(1)/74-LR.IV]

P. R. NAYAR, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th June, 1974

CUSTOMS

S.O. 1647.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 1391 (77-Customs) dated 19th May, 1973, published at page 1818 of the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated 19th May, 1973 for "7th May, 1969" read "7th May, 1960".

[No. 55-Customs/F. No. 14/8/70-LCII]

D. SARUP, Under Secy.

